

two years back. Only a fortnight back, one lady passenger, Miss Zarina Dastur was travelling in the First Class compartment between Charni Road and Marine Lines and a goonda entered the compartment and tried to snatch away her golden chain. She successfully resisted bravely, caught hold of the goonda and with the help of other passengers handed him over to the Railway Police. Between Hirar and Boriwali, there are lonely stations, like, Meera Road, and Dahisar where this gang of goondas stay in hutments, keep a watch and forcibly enter the First Class compartment and assault the passengers in broad day-light and snatch away their valuables.

Repeated requests have been made to the Railway Minister to check these crimes. In my speech on the Railway Budget, I made a mention of it. But I am sorry to find that the hon. Minister, in his reply, did not say anything about it. I would urge upon the Railway Minister to take urgent and drastic steps to curb the activities of the goondas on the suburban trains and firmly deal with them so that there are no more such incidents and the passengers feel a sense of security and safety on both these suburban lines.

**SHRI VAYALAR RAVI** (Chrayinkil) : Sir, I have also written to you about the same thing.

**MR. SPEAKER** : Only one Member was permitted.

**SHRI VAYALAR RAVI** : My concern is that we belong to the linguistic minority living in Maharashtra, in Bombay. I only add one sentence. She said, "I can identify the goonda." But the police did not come in time before her death.

The hon. Home Minister, the other day, assured the House that linguistic minorities will be protected in Maharashtra. But, unfortunately, it has not been done.

13 HRS.

**SOME HON. MEMBERS** rose—

**MR. SPEAKER** : I am not allowing any one. I am not going to depart from the practice. I have already allowed one...

**SHRI JYOTIRMOY BOSU** (Diamond Harbour) : Then tomorrow, Sir?

**MR. SPEAKER** : You may try. But, I think, something else is coming up tomorrow.

**MR. Banerjee**, please sit down. I have been allowing matters to be raised under Rule 377 which is a marginal thing between point of order and other motions. But now every one has started claiming it as a matter of right. I am extremely sorry. In other Parliaments they never allow these things. Here we have call-attention and many other things...

**SHRI DINEN BHATTACHARYYA** (Serampore) : Something else is allowed there, but here that is not allowed.

**MR. SPEAKER** : No where call-attention and other motions which we are allowing here are allowed.

13.03 HRS.

\*DEMANDS FOR GRANTS, 1974-75—Contd.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY—Contd.

**MR. SPEAKER** : Dr. Laxminarain Pandeya to continue his speech.

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर)  
प्रध्वक्ष महोदय, औद्योगिक मंत्रालय की जिस प्रकार की नीति है उस के कारण औद्योगिक उत्पादन घटा है जिसे रबर्ग मंत्री जो ने भी स्वीकार किया है। आर्थिक सर्वेक्षण जो 1973-74 का उपलब्ध कराया गया है उस के पृष्ठ 13 में लिखा गया है कि उद्योगों द्वारा अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया

\* Moved with the recommendation of the President.

[श० लक्ष्मीनारायण पांडेय]

गया है। उस में लिखा है : पिछले कुछ वर्षों में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के विषय में बराबर यह अनुभव किया जाता रहा है कि बहुत उद्योगों में उन की क्षमता का पूरा पूरा उपयोग नहीं किया जाता उन की उत्पादन क्षमता का उपयोग भी हर साल कम होता जा रहा है। इस के उत्कृष्ट उदाहरण हैं—

इस्पात और उर्वरक और सभी हाल में अल्मुनियम भी उसी श्रेणी में आ गया है। तो इस्पात, अल्मुनियम और उर्वरक का उत्पादन घटा है। 20 तारीख के 'फाहनेशियल ऐक्सप्रेस' में भी इसी बात की प्रोग्नोसिस दीया गया है कि फटिलाइजर का उत्पादन जिस रूप में होना चाहिये, किननी आवश्यकता देश को आगामी खरीफ सीजन में है उतना भी उपलब्ध नहीं करा पायेगे। उस में लिखा है :

"17% fall in fertiliser for kharif crops According to the estimates made by the Ministry the country needs a minimum of 15.43 lakh tonnes of nutrients for the 1974-75 kharif crops. Nitrogen (10.13 lakh tonnes) forms the bulk of it The requirement of phosphorus and potash is 3.33 and 1.97 lakh tonnes respectively."

13 04 hrs.

[Mr DEPUTY-SPEAKER in the Chair.]

इतनी आवश्यकता होगी लेकिन उत्पादन न होने में आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते। इसी कारण आज अनेक स्थानों पर उद्योगों की हानत खराब है। मंत्री जी ने एक भाषण में स्वीकार किया था कि हम जिन साधनों का जिस प्रकार से उपयोग करना चाहते हैं उन का उपयोग नहीं हो रहा है जिन स्वार्थों का दोहन होना था, नहीं हुआ। एक बार हेबी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने अपने भाषण में जो "हिन्दुस्तान टाइम्स" के 17 अगस्त, 1973 के अंक में छपा है इस बात की प्रोग्नोसिस किया है कि उद्योगों ने अपनी क्षमता का उप-

योग नहीं किया है और इसी कारण औद्योगिक उत्पादन में, जो चौथे प्लान पीरियड में उत्पादन हम ने आका था, उस को हम प्राप्त नहीं कर सके हैं। जैसा कि इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है। मिसाल के लिये कोटन को लीजिये जो उत्पादन हम ने चौथे प्लान पीरियड में आका था उस के अनुसार जो प्राप्त कर सके हैं वह बहुत थोड़ा है। ठीक इसी प्रकार से स्टील के बारे में जो विचार किया था उस में भी पीछे रहे हैं। फटिलाइजर का भी यही हाल रहा है और हम इस कमी के कारण हमारी आर्थिक स्थिति, पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। कागज की कमी आज भयकर है। कागज उद्योग पर उचित ध्यान दिया होता तो सम्भवतः यह स्थिति न होती।

जहां तक टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज का सवाल है उस के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। जैसा कई माननीय सदस्यों ने संकेत किया है कि जो कटौत कपड़ा है उस की जितनी उपलब्धी जनता को करायी जानी चाहिये थी, प्रति व्यक्ति जितनी खपत होनी चाहिये, उस में कमी इस बात का प्रमाण है कि जनता को उपलब्ध नहीं करा सके हैं। लेकिन उस के विपरीत आर्ट मिल्क और रेशम का उत्पादन बढ़ा है। लेकिन मोटे कपड़े का नहीं बढ़ा। जो हमने अनुमानित किया था उससे विभिन्न उद्योगों के लिये स्टील, सीमेंट, अन्य उपकरण और बिजली बाँटित-मात्रा में उपलब्ध कराने में सरकार असमर्थ रही है और इसी कारण कई उद्योग बिजली के अभाव में बन्द हो रहे हैं। तो कई स्टील के अभाव में आज के "टाइम्स आफ इंडिया" समाचार-पत्र में आया है कि

"Power-less Haryana is for deep crisis Haryana is heading for utter industrial chaos if the Union Government does not come to its rescue with power supply from other States on an emergency basis."

यदि भारत सरकार ठीक से पावर की सप्लाई नहीं करती है तो फ़रीदाबाद और भासपास की इंडस्ट्रीयल यूनिट्स का उत्पादन गिरेगा और उस का असर कुल मिला कर हमारे उत्पादन पर भी पड़ेगा। मंत्री जी ने स्वयं अपने मंत्रालय की 1973-74 की रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आयी है, और भागे भी यदि इसी प्रकार की स्थिति रही तो गिरावट आ सकती है। और जो उन्होंने संकेत दिये हैं उन में इन्होंने प्रमुख रूप से बिजली की कमी को बताया है :

- “1. Inadequate capacity of plants;
2. operational problems in industrial units (steel, fertilisers);
3. lack of maintenance (steel, fertilisers);
4. design deficiencies (steel, fertilisers);
5. shortfalls in investment (capital goods);
6. shortage of steel, non-ferrous metals (engineering industry);
7. shortages of power, coal and movement problems (all industries);
8. unsatisfactory industrial relations;
9. shortage of construction materials;
10. larger reliance on domestic equipment and technology.”

कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है। मंत्री महोदय को उधर ध्यान देना चाहिए।

डिजाइन में डिफ़ेक्ट की वजह से भी कई उद्योग ऐसे हैं जो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। या किसी कारण से अगर चलाये जाते हैं तो बाद में जा कर डिजाइन डिफ़ेक्ट की वजह से कमी आ जाती है और उत्पादन जिस रूप में चाहते हैं वह नहीं होता है। स्टील इंडस्ट्रीज के अन्दर हम को अनुभव है कि बारबार उन की डिजाइन में डिफ़ेक्ट होने से, चाहे दुर्गापुर हो या रूरकेला हो, इन के उत्पादन के जो लक्ष्य हम ने निर्धारित किये थे उन को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। स्टील के उत्पादन में गिरावट का यह

प्रमुख कारण रहा है। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिये।

इसी प्रकार से सीमेंट की हालत है। सीमेंट की मांग बढ़ रही है, लेकिन मंत्री महोदय ने माना है कि सीमेंट उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। अनेक क्षेत्रों में सीमेंट के लिये रा-मैटी-रियल भरा पड़ा है लेकिन सीमेंट कोपोरेशन आफ इंडिया को जहां जहां फ़ैक्ट्री लगाने के लाइसेंस दिये हैं वहां फ़ैक्ट्रीज लगाने में बिलम्ब हुआ है। उदाहरण के लिये मैं आप को बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में निमंच में सीमेंट फ़ैक्ट्रीज हेतु लाइसेंस मिला। किन्तु अभी स्थान का ही चुनाव हो रहा है, जब कि मध्य प्रदेश के अनेकों स्थानों के बारे में चौथी योजना में विचार हुआ लेकिन आज तक सीमेंट कोर-पोरेशन आफ इंडिया निमंच में भी सीमेंट की फ़ैक्ट्री डालने में असमर्थ रही है। यह हमारी दोषपूर्ण नीति का परिणाम है। इसके कारण जो हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनकी कमी अनुभव की जा रही है। सीमेंट की कमी दूर करने में मंत्रालय असमर्थ रहा है और इसी तरह से दूसरी आवश्यक वस्तुओं की कमी को दूर करने में भी वह असमर्थ रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से भी घाटा ही हो रहा है लाभ नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के बारे में आम धारणा यह है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग नहीं बल्कि सरकारी उद्योग मात्र हैं और केवल सरकारी भाषा का ही वे अनुसरण करते हैं उनका दृष्टिकोण सार्वजनिक नहीं और ऐसा करने से उनमें हजारों करोड़ रुपये की जो पूंजी लगी हुई है उसके बावजूद भी उन में घाटा हो रहा है। सौ से अधिक यूनिट्स सार्वजनिक क्षेत्र के हैं और अधिकांश उन में—ऐसे हैं जो अनुत्पादक हैं, जिन के बारे में कहा जा सकता है कि करोड़ों रुपये का घाटा आज उनके अन्दर हो रहा है। उन में लाभ होना चाहिये, घाटा दूर होना चाहिये। उनका प्रबंध संचालन ठीक हो यह आवश्यक है।

[डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय]

दूसरी तरफ आप देखें कि एकधिकार प्राप्त जो घराने है उन पर भी कोई नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। टाटाज हो या बिड़लाज हों उन्हें के एसेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके कारण भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की प्रोत्साहन मिलना चाहिये या, प्रथम मिलना चाहिये या, नहीं मिलता है। मैं समझता हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हो या निजी क्षेत्र के उद्योग हो इन दोनों में भेद भाव करने की नीति को हमको छोड़ देना चाहिये इन दोनों में पारस्परिक समन्वय की नीति होनी चाहिये। एक बार मंत्री महोदय ने ज्वायंट सैक्टर की बात कही थी। ज्वायंट सैक्टर का क्या स्वरूप होगा या सशुक्त उद्योगों का क्या स्वरूप होगा, उनका मैनेजमेंट किस प्रकार का होगा, उनके प्रबन्ध भाषीदारी किस प्रकार की होगी, मजदूरों की भागीदारी किस प्रकार की होगी, जनता की या सरकार की किस प्रकार की होगी, सरकार उन में कितने प्रतिशत शेयर लेना स्वीकार करेगी अथवा जनता को कितने प्रतिशत शेयर देना स्वीकार करेगी, इसका कुछ भी पता नहीं है, इस का कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, कोई स्पष्ट चित्र हमारे सामने नहीं रखा गया है। इस कारण से ज्वायंट सैक्टर को जो कल्पना है वह केवल अधूरी कल्पना मात्र बन कर ही रह गई है। ज्वायंट सैक्टर हो, सार्वजनिक क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो, इन में भेदभाव करने की नीति को छोड़ कर उद्योग के तथा उत्पादन के हित की बात को हमको सोचना होगा, देश की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से प्रबल और सुदृढ़ हम बना सकते हैं, इसको सामने रख कर सोचना होगा और राष्ट्रीय हित की दृष्टि से नेशनल सैक्टर के स्वरूप को विकसित कर कार्य करे। उद्योग किसी भी स्थान पर खड़े हों हमको देखना होगा कि उत्पादन में हम बृद्धि लाएँ फिर चाहे वह शक्कर का उत्पादन हो, सिमेंट का हो, फर्टिलाइजर का हो। चाहे जिस किसी भी क्षेत्र के कारखाने हों अगर हम

चाहते हैं कि उनके उत्पादन में बृद्धि हो तो उनकी जो पूंजी की आवश्यकता है, उनके वास्ते जिस प्रकार के साधनों की आवश्यकता है कच्चे माल की आवश्यकता हो, उनको हर्षे उपलब्ध कराने का प्रयत्न करना होगा।

हमारे यहां विदेशी पूंजी का प्रभुत्व बढ़ रहा है। प्राकड़े इसको मिट्ट कर रहे हैं। विदेशी कोलोकोरेशन से, विदेशी सहयोग से, विदेशी टैकनालाजी से, विदेशी नो हूड से हमारे यहां कारखाने बड़े हैं। नौ हूड हम प्राप्त करें और उनके आधार पर कारखानों का विस्तार हो, इस से कोई दो राय नहीं हैं मतभेद नहीं हैं। लेकिन अगर विदेशी पूंजी बढ़ती है तो यह चिन्ता का विषय हो जाना है। जो प्राकड़े उपलब्ध है उनके अनुसार लगभग 72 नए कारखानों में विदेशी पूंजी लगने वाली है, इसकी सरकार ने—अनुमति दी है। इससे विदेशी पूंजी का प्रभुत्व बढ़ेगा। पहले से भी यह बहुत बढ़ा है। कालगेट को आप ले, हिन्दुस्तान लिबर को से या इस प्रकार की दूसरी कम्पनियों को लें आपको पता लगेगा कि करोड़ों रुपये की नहीं अरबों रुपये की पूंजी उन्होंने हमारे देश से अर्जित की है। आपको एक निश्चित नीति निर्धारित करनी चाहिये कि विदेशी कम्पनियों जो पूंजी वे कमाती हैं उसका कितना प्रतिशत भाव बाहर भेज सकती हैं,—प्रतिशत तय कर दिया जाना चाहिये और उम प्रतिशत से अधिक मुनाफा उनको बाहर भेजने की इजाजत नहीं होनी चाहिये।

प्लानिंग कमीशन की एक्सपर्ट बाडी ने यह बताया है कि इम्पोर्ट में जो डिफेज होती है मशीनरी वगैरह की उसके कारण 335 करोड़ की हमको हानि हुई है। इसी तरह से जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उन में भी अमनेसिमरी डिफेज होती है। उनके कारण भी करोड़ों रुपये की हानि होती है। उसको बचावा जाना चाहिये आपको तय करना चाहिये कि किस प्रकार से इन डिफेज से बचा जा सकता है ताकि हमें हानि इस तरह से न उठानी पड़े।

यह हमारी कार्य प्रणाली का दोष है। इसे हल कर दें।

जनवरी में स्टेट मिनिस्टर्स कान्फेंस हुई थी। मंत्री महोदय उस में नहीं गए। लेकिन 23 जनवरी, को समाचार आया कि उम कान्फेंस में यह घोषणा की गई कि हमें सिमट शककर आदि की देश के अन्दर खपत को कम करना चाहिये क्योंकि इनका निर्यात करके हम विदेशी मुद्रा कमाना चाहते हैं। मकान बनाने हो तो लोगों को सिमेट मिलना चाहिये। शककर की लोगों को आवश्यकता है उनको शककर मिलनी चाहिए। यह भी जरूर है कि हमें विदेशी मुद्रा भी चाहिये। लेकिन विदेशी मुद्रा के नाम पर आप देश की जनता को भ्रष्टा नंगा नहीं रख सकते हैं बिना खाण के नहीं रख सकते हैं, इनकी जा आवश्यकताये हैं उनकी पूर्ति में उनको बाँचन नहीं कर सकते हैं। यह कहा गया था कि निर्यात को बढ़ावा देन के लिए उन चीजों की खपत को हमें देश में घटाना होगा। यहाँ चाहे ये उपलब्ध न हा लेकिन हमको इनको बाहर जरूर भेजना होगा। इस प्रकार की औद्योगिक नीति का कभी भी समर्थन नहीं किया जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि आप उत्पादन बढ़ाये। उत्पादन के अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा मान करे। निर्यात और आन्तरिक खपत में आपकी सन्तुलन रखना होगा। औद्योगिक नीति में अभी तक हम प्रकार के सन्तुलन का अभाव रहा है। सन्तुलन नाम की कोई चीज अभी तक देखने को नहीं मिली है। इसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये। केवल आंतरिक खपत या निर्यात में ही सन्तुलन की आवश्यकता, नहीं है अपितु देश के औद्योगिक ममज्ञ विकान में यह सन्तुलन हो।

आप यह भी देखें कि देश के कुछ भाग विकसित होते जा रहे हैं, दूसरे पिछड़ते जा रहे हैं। वे विकसित नहीं हो रहे हैं। चारों तरफ से इस प्रकार की भिन्नतायें सुनने को मिल

रही हैं। पिछड़े हुए इलाकों में जिस प्रकार से उद्योग लगने चाहिये नहीं लगे हैं। सरकार घोषणा तो करती रहती है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग लगाने के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी लेकिन उसको कार्यरूप में परिणत नहीं किया जाता है। मध्य प्रदेश का ही उदाहरण ले, बस्तर और सरगुजा में बाक्सइट काफी मात्रा में उपलब्ध है जिससे एल्यूमिनियम बनाया जा सकता है। एक कारखाना बालको के नाम से नेकोरवा में लगाया है। लेकिन उस में केवल एल्यूमीना बन रहा है। स्मल्टज के अभाव में एल्यूमिनियम नहीं बन रहा है। स्मल्टज भी साथ साथ लगाने चाहिये थे। ये नहीं लगे इस कारण में कगोडो रुपये का नुकसान हो रहा है। बस्तर में भी कारखाने लगाने की काफी गुंजाइश है। काल बेस्टर उडस्ट्रीज वहाँ बन सकती हैं। लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं है। ऐसे ही दूसरे राज्य का उदाहरण ले तो राजस्थान में राक फास्फेट आयरन और आदि खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं किन्तु वहाँ इनके आधार कोई बड़े कारखाने नहीं बनाए गए हैं। जहाँ तक कारबा रा सम्बन्ध है जिस गति से वहाँ काम हो रहा है मुझे नहीं लगता है कि पाच वर्ष में भी वह बन कर तैयार हो जाएगा। कई उद्योगों की कैपेसिटी अनयुटिलाइज्ड पडी हुई है उसका प्रापर युटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि कुछ मुद्रा सम्बन्धी बठिनाइयाँ हो सकती हैं। लेकिन उनका भी आप हल करे। आप टैक्सों पर टैक्स लगाते जा रहे हैं। ऐसा करके आपने जनता के जीवन को हूषर कर दिया है। उसके ऊपर आपने भारी टैक्सों का बोझ लाद दिया है। फिर भी अगर उत्पादन यथेष्ट नहीं होता है तो इसका एक मात्र कारण नियोजन में दोष होना है। प्लानिंग हमारा दोषपूर्ण है। अनेक प्रोजेक्ट्स हैं, निर्माणधीन हैं बाहे वे स्टील के ही, इरिगेशन के हो या दूसरी तरह के प्रोजेक्ट्स हो इस प्रकार के लगभग 64 प्रोजेक्ट्स हैं

## [डा० लक्ष्मीनारायण पाडेय]

जिन की कीमत आज या तो दुगुनी हो गई है या दुगुना खर्च पर उन पर होने की संभावना है। यह इस लिए हुआ है क्योंकि हमारा जो सारा आयोजन है वह ठीक नहीं। केवल विदेशों के आधार पर, विदेशी तकनीकी के आधार पर, विदेशी यांत्रिकी के आधार पर, विदेशी नौ हऊ के आधार पर हम नहीं चल सकते हैं, हम को स्वदेशी आधार पर सोचना और विचार करना होगा। हमारे देश में लोग हैं जो अपने नौ हऊ से बहुत अच्छा स्टील बना सकते हैं, दूसरे क्षेत्रों में बहुत अच्छे उद्योग स्थापित कर सकते हैं, उत्पादन की दिशा में आगे आ सकते हैं, अपने प्रतिष्ठान खड़े कर सकते हैं। आप तो जानते हैं कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स भोपाल में मशीनरी के किसी विशेष कम्पोनेट की आवश्यकता पड़ी, उसको उपलब्ध कराने में रूस का अपना मत था ब्रिटेन का अपना मत था फेल हुआ लेकिन एक छोटे में इजीनियर ने उसको तैयार कर दिखाया बाहर का नौ हऊ इस में असमर्थ रहा हमारे यहाँ के नौ हूँ वे इसको कर दिखाया। सरकार इस प्रकार के नौ हऊ को प्राप्त करे और इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन दे। ऐसा सरकार नहीं करती है। मैं समझता हूँ कि यह इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट है और उसी रूप में हमारे सामने आया है।

आपने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाई हैं और बना रहे हैं। लेकिन ये कहाँ बन रही हैं? बम्बई के पास बन रही है, नागपुर के पास बन रही है, दिल्ली के पास बन रही है, फरीदाबाद में बन रही है, जो बड़े-बड़े शहर हैं उन्हीं के इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बन रही हैं। छोटे शहरों के पास बनती हैं तो उनको राम्पेटेरियल नहीं मिलता है, बिजली मग्नार्ड नहीं की जाती है, पैसा नहीं दिया जाता है। आप स्वयं जा कर देख सकते हैं कि वे शोड खानी पड़े हैं इनका विज्ञानिक आधार पर विबाम हाँ, कोआडिनेशन हाँ।

राम्पेटेरियल की उनकी आवश्यकता होती है तो पहले जिस जिले में वे होती हैं उस जिले के अधिकारी के पास जाना पड़ता है और जिला अधिकारी जब सन्तुष्ट हो जाता है तो वह उनके केम को उस प्रान्त की राजधानी को रिक्मंड करता है और वहाँ अगर काम बन सकता है तो वहाँ बनता है और अगर नहीं बन सकता है तो दिल्ली और कसकता उनको जाना पड़ता है इस प्रकार विभिन्न मामलों में कई स्थानों व कई मंत्रालयों के चक्कर काटना पड़ते हैं।

कोई इंट्रिप्टिड मिस्टम डम के लिए आप क्या लागू नहीं कर सकते हैं, कोई ब्याबहारिक हल आप इसका नहीं निकाल सकते हैं? आप कोई लिमिट बाध सकते हैं कि इस लिमिट तक तत्काल उसको जिले में ही परमिट मिल जाए या नाइसेस मिल जाए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि छोटे उद्योगों को खालने में उनको सुविधा होगी, वे चल भी सकते हैं।

इस तरह उन में काफी प्रगति हो सकती है, उन की काफी उन्नति हो सकती है।

कट्रोल आइटमज व वारे में चारों तरफ से शिनायत है कि वे लोगों को नहीं मिलती हैं। सरकार को उन के वितरण की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। या जिन्हें मिलनी है व उसकी काला बाजारी करतें हैं। इस प्रक्रिया को ठीक करना चाहिये।

इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट बैंक वार्माशयल बैंक और स्टेट फिनाम कॉर्पोरेशन की हालत यह है कि आप यद्यपि सरकार छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन रमाल-स्कैल इंडस्ट्रीज को निरन्तर चक्कर काटने में बावजूद ऋण नहीं मिलता है।

विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के बारे में बड़े उद्योगों और छोटे उद्योगों के बीच बाइकॉर्नेशन होना चाहिए, कोई सीमा-रेखा निर्धारित की जानी चाहिए। उदाहरण

के लिए कपडा मिले ऊंची किस्म का कपडा बनाये लेकिन टावल और चादर बनाने का काम हूडलूम और पावरलूम के लिए सुरक्षित रखा जाये । टावल और चादर का उत्पादन किसी बड़ी करडा मिल में नही होना चाहिए ।

इस बात की भी कोई आवश्यकता नही है कि हिन्दुस्तान नीबर साबुन और कासमेटिकम का, या कालगेट टेलकम पाउण्डर, या अन्य दैनिक उपभोग की वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर करे । इन वस्तुओ का उत्पादन छोटी-छोटी वाटेज इडस्ट्रीज में किया जाना चाहिए, जिन से हम काफी लोगो को रोजगार दे सकते हैं । हमारा मकल्प है कि हम ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुधारेगे । हम के लिए आवश्यक है कि गाबो मे रोजगार के अवसर पैदा हो और रूरल इडस्ट्रिज का विकास हो । उस दृष्टि मे यह आवश्यक है कि विभिन्न वस्तुओ के उत्पादन के विषय मे मीमा-रेखा निर्धारित की जाये । परम्परागत व कुटीर उद्योगो के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना जरूरी है ।

आज लाइसेंसिंग की मारी पावर कन्डीय सरकार के हाथ मे है । स्टेट्स छोटे उद्योगो के बारे मे भी लाइसेंस नही दे सकती है । हम के लिए मंड्रल गवर्नमेंट के पास दौडना पडता है । हम लिए यह आवश्यक है कि लाइसेंसिंग पालिसी पर पुनर्विचार कर के लाइसेंसिंग की व्यवस्था का डीसेन्ट्रलाइजेशन किया जाये ।

एक तरफ मार्बजनिज उद्योग कोई अच्छी स्थिति में नही है और दूसरी तरफ निजी उद्योग चिन्तित और भयभीत है, क्योंकि व समझते हैं कि नेशनलाइजेशन की तलवार उन के मिर पर लटक रही है । अगर वे कोई पूजी लगाते हैं तो सरकार कभी भी हमारी पूजी पर हाथ डाल सकती है । निजी उद्योगो के भय को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार यह तय कर दे कि कि हम अभीक समय तक—फिर चाहे वह पांच

बरस तक या दस बरस तक का समय हो— टैक्सटाइल, शूगर या किसी अन्य उद्योग का राष्ट्रीयकरण नही करेगे । इस से उन उद्योगो मे पूजी लगेगी, राटन मशीनरी के स्थान पर नई मशीनरी लगाई जायेगी और उत्पादन भी बढ मकेगा ।

कानज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुओ की माग बढ़ती जा रही ह, लेकिन आज वे लोगो को उपलब्ध नही है और अगर उपलब्ध होती भी है, तो महंगे दामो पर । छोटी छोटी इडस्ट्रीज को उपभोक्ता वस्तुओ के निर्माण में जो सरकार की तरफ से योगदान देना चाहिए, वह नही मिल रहा है दूसरी तरफ विदेशी प्रभुत्व और विदेशी पूजी वाली कम्पनिया लकसरी गुड्स बना रही है । इनके उत्पादन में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है । इस स्थिति मे उपभोक्ता वस्तुओ की कमी होती चली जा रही है । गत 6 मास में ही इनकी कीमतें 13 प्रतिशत बढी हैं । हम देखते हैं कि विदेशी और बहुराष्ट्रीय कम्पनिया उपभोक्ता वस्तुओ के निर्माण के क्षेत्र मे अपने पाव फैलाती जा रही है । उन को नियंत्रित करना चाहिए और विदेशी कम्पनियो का भारतीयकरण किया जाना चाहिए— उन की दो-तिहाई पूजी भारतीय होनी चाहिए ।

नेशनल स्माल-स्केल इडस्ट्रीज कार्पोरेशन मशीनो का प्रायात करती है । लेकिन जो मशीने अनेक वर्षों से मगाई हुई हैं, वे बेकार पडी हुई हैं । उनका उपयोग ठीक ढंग से होना चाहिए । आज लाखो रुपये की प्रायादित मशीने कार्पोरेशन के पाम बेकार पडी हैं ।

हमारे चमडा उद्योग, कायर उद्योग, ऊन उद्योग और अन्य उद्योगो की कोई छाम अच्छी स्थिति नही है । उन की स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार का उचित कदम उठाने चाहिए । औद्योगिक विकास मे ट्रांसपोर्टेशन का बडा महत्व है उसका भी ताल मेल प्राप्त बिठा दे ।

[डा० लक्ष्मीनारायण पंडेय]

आप्यत घोर निर्वात प्रकिया में सुधार करना चाहिए घोर लाइसेंसिंग सिस्टम को सरल बनाना चाहिए, जिसके आधार पर वास्तविक उपभोक्ता आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त कर सके। मैं पुनः दुहराना चाहूँगा कि औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरह एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रभुत्व और एकाधिकार ठीक नहीं है, उसी तरह सरकार का प्रभुत्व बढ़ना भी कोई अच्छा लक्षण नहीं है। इसीलिए हमें राष्ट्रीय क्षेत्र को कम्पना करनी चाहिए।

सत्र में मध्य प्रदेश के बारे में निवेदन करना चाहूँगा—मेरे क्षेत्र में ओरियम काफी मात्रा में पैदा होता है। इसलिए नीमच या मदमीर में ओरियम बाई-प्राइक्टम के कई कारखाने लगाये जा सकते हैं। वहाँ एलकनायड फैक्टरी लगाई जा रही है, लेकिन पापी हस्त के आधार पर वहाँ कई कारखानों की स्थापना की जा सकती है। इसी मदमीर जिले की जावर नहसील में घायरन घोर उपलब्ध है उसका उपयोग होना चाहिये। मध्य प्रदेश में मग्गूजा घोर बस्तर में बाकसाइट काफी मात्रा में मिलता है। इस लिए वहाँ पर एक घोर एलुमिना प्लांट लगाया जा सकता है। खरगोन, रनलाम, आदि जिलों में लाइम-स्टोन काफी मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए मध्य प्रदेश में घोर सीमेंट फैक्टरियां लगाई जा सकती हैं। नीमच की सीमेंट फैक्टरी के बारे में काफी बिलम्ब हुआ है। उसे जल्दी लगाया जाये।

मध्य प्रदेश में पानी बिजली घोर ग मैटीरियल है, वहाँ कोयला, तांबा, मैंगनीज, बाकसाइट, लाइमस्टोन घोर बांस के घने जंगल हैं। लेकिन औद्योगिक दृष्टि से वह पिछड़ा हुआ है। इसलिए देश के औद्योगिक मानचित्र में उसको स्थान देने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। आज हमारे देश में औद्योगिक विकास असंतुलित बन

से हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र-राष्ट्र घोर उत्तर प्रदेश आदि सब राज्यों में समान रूप से औद्योगिक विकास होने, इस को दृष्टि में रखते हुए हम एक राष्ट्रीय औद्योगिक नीति का पालन करें घोर वर्तमान नीति में आमूल-बूल परिवर्तन करें। लभी हमारी औद्योगिक प्रगति का वास्तविक स्वरूप सामने आयेगा, हम औद्योगिक दृष्टि से आगे होंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have a request from the Whip of the Congress Party to allot ten minutes each to each Member from the Congress Party I shall co-operate with him and ring the bell at the proper time

SHRI VAYALAR RAVI (Churayinkul). Some Members are absent. So, their time may be given to the others.

MR DEPUTY-SPEAKER: The list is a very long one. It is his party's arrangement, and I am only co-operating. I am giving them only the party's time

श्री मूलबन्धु डागा (पानी) : उपाध्यक्ष महोदय, नीनिया कितनी भी अच्छी हो, जब तक निष्ठा घोर ईमानदारी से उनका पालन नहीं किया जाता है, तब तक वे नीतियां केवल किताबों में रहती हैं। 1956 का इंडस्ट्रियल पालिसी रजोत्युषान भी है, लाइसेंसिंग पालिसी भी है घोर एम० आर० टी० पी० एक्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारी जा नीति है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगा है ?

17-4-73 को एक सत्र के अन्त में यह बताया गया था कि टाटा के प्राफिट्स 1969-70 में 32.78 करोड़ रुपये थे घोर 1970-71 में वे बढ़ कर 53.57 करोड़ रुपये हो गये। इसी तरह बिड़ला के प्राफिट्स 1969-70 में 51.60 करोड़ रुपये थे, जब कि 1970-71 में वे बढ़ कर 61.58 करोड़ रुपये हो गये। इनमें साबित होता है कि हिन्दुस्तान में मुनीमाद



बढ़ रहा है। हम कानसेनट्रेशन आफ इका-  
नोमिक पावर नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर  
भी वह बढ़ रहा है। इस बात का भय है कि  
कहीं ये पूंजीपति राजनीति पर हावी न हो  
जायें और राजनीति उन की चेरी न बन जाये।  
इस से लोकतन्त्र के लिए खतरा पैदा हो  
सकता है। हम लोकतांत्रिक समाजवाद  
लाना चाहते हैं। उस में पूंजीवाद का खात्मा  
होना जरूरी है। लेकिन सरकार कमीशन ने  
अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है ?

“The Commission, which was re-  
presented by a retired judge of the  
Calcutta High Court, used three  
main arguments to show that IDBI  
had in fact shown undue favour to  
the Birlas.”

The time at my disposal is short;  
otherwise, I can read more from the  
article to show how favour has been  
shown. This is the report of the com-  
mission appointed by Government  
themselves.

THE MINISTER OF INDUSTRIAL  
DEVELOPMENT AND SCIENCE  
AND TECHNOLOGY (SHRI C.  
SUBRAMANIAM) : The commission  
has not submitted its report. This is  
unfair.

SHRI M. C. DAGA : I am reading  
from the *Economic and Political Week-  
ly* from an article entitled ‘Public  
Money for Private Enterprise’. It is  
dated the 12th January, 1974. If the  
hon. Minister would read the whole  
article, he will see the arguments which  
have been advanced.

SHRI C. SUBRAMANIAM : It may  
be an article, but it is not the Com-  
mission’s report. The report has not  
yet been submitted.

SHRI M. C. DAGA : It appears  
under the heading ‘Sarkar Commis-  
sion’.

इनवेस्टमेंट कैसे होता है ? 1968-69  
में 85 करोड़ रुपये, 1969-70 में 111  
करोड़ रुपये, 1970-71 में 133 करोड़

रुपये और 1971-72 में 162 करोड़  
रुपये। इसका मतलब यह है कि पूंजीपतियों  
को बराबर पूंजी मिल रही है। कोई चैलेंज  
नहीं कर सकता है कि उन को पूंजी क्यों मिल  
रही है। हर एक जानता है कि पूंजीपतियों  
को डिमबर्समेंट होता है।

सरकार का कहना है कि रिजिनल इम्बैलेंस  
नहीं होना चाहिए। एस्टीमेट्स कमेटी की  
1972 की रिपोर्ट में कहा गया है—मेरा  
खयाल है कि यह मिनिस्ट्री इस रिपोर्ट को  
पढ़ती होगी :

“The Committee regret to note  
that barring four or five States,  
other States do not attach that much  
priority to small-scale industries as  
they deserve”.

This means that other States have  
neglected this. I do not want to go  
through the whole report. But this  
observation would be found at page 12  
of the Thirty-Fifth Report of the Esti-  
mates Committee (Fifth Lok Sabha).

आप की कमेटी की रिपोर्ट इस बात को  
साबित करती है। आप का जो इम्बैलेंस है  
स्टेट्स में उस की बात मैं आप को बता रहा  
हूँ :

“Advances made by the commer-  
cial banks also indicate that Rajas-  
than share is 1 per cent as against  
30 per cent advances given in Maha-  
rashtra, 19 per cent in West Bengal,  
11 per cent in Tamil Nadu and  
6 per cent in Gujarat. *Per capita*  
investment by these banks in Rajas-  
than is only Rs. 18.2 as against  
Rs. 69.4 for the country as a  
whole and Rs. 231.6 in Maharashtra,  
Rs. 136.7 in West Bengal...”

See how Rajasthan has been ne-  
glected.

SHRI DINEN BHATTACHARYA  
(Serampore) : All of Rajasthan is now  
in Calcutta, West Bengal.

**SHRI M. C. DAGA :** This is the argument being advanced. I am pointing out how our State is being neglected.

यह राजस्थान के इन्वैलेस की बात में ने आप के सामने रखी। आप खुद मानेंगे इस बात को। वह कह रहे हैं.—

“The Committee are concerned to note that many of the small scale industries are working on outmoded technology and many of the small scale service institutes in the States are not well equipped to give guidance in modern lines of industry”.

आप का सारा जो स्टेट्स का काम है मेरी समझ में नहीं आता है कि आप सारा कंसट्रेशन सेक्टर में क्यों कर के रखना चाहते हैं। स्टेट्स पर कुछ जिम्मेदारी डालिए। स्टेट्स के अंदर लोग अगर अपने अपने यहां की इंडस्ट्री को नहीं देखते हैं, अधिकारी लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो क्या लाभ है? आप ने सारी पावर सेट्रलाइज कर के रखी है। एक तरफ तो आप डि-कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरी तरफ सारी पावर को सेट्रलाइज कर रखा है। आप के विभागों में क्या होता है कि सारा पावर आपने गाम सेट्रलाइज कर के रखते हैं। आज पावर लोगों को अवैलेबल नहीं है, पावर की शार्टेज है, रा मंटीरियल की शार्टेज है। कौन उस की जिम्मेदारी लेगा?

मान लीजिए मैं कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ। अब नौकरशाही आप की लोगों का मदद करने के लिए तैयार नहीं, उस के लिए इंडीकैटेड लाइफ उस की नहीं। उसका एटीट्यूट, उस का बिहेवियर, उस का काम करने का तरीका सब उस के विपरीत है। मैं पूछता हूँ आप ने आज तक किसी अधिकारी का, किसी स्टेट के इंडस्ट्रीज आफिसर का एक्सामिनेशन काल किया? आखिर करोड़ी रुपये खर्च होते हैं, इंडस्ट्री लगते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं और सब कुछ

करने के बाद भी, क्या कोई उस की जिम्मेदारी लेता है? सारी मशीनरी आप की किस प्रकार से डील करती है उस का एक उदाहरण मैं देता हूँ एक अप्लीकेशन 23-3-73 को दी गई। वह एकोनामिक एडवाइजर के पास जून 73 में गई।

Sanction of the Economic Adviser was received in DETD in August, 1973. Allocation letter by DGTD was issued on 3-9-73 to CCI & E Licences and release order was issued by CCI & E on 1-12-73. Material sale orders issued by MMTG, New Delhi, on 25-1-74 against which no material yet arrived

यानी एक बात है।

In 1973, he had applied. It is now 1974 But he has not got the raw material This is a procedure which is laid down. Applications should be disposed of within a short time.

आप सारी अप्लीकेशन को डिस्पोज आप कीजिए विदिन ए बेरी शार्ट पीरियड एक अप्रैल 1973 में आप को कहता है कि मैं रा-मंटीरियल चाहता हूँ और 1974 तक उस को रा-मंटीरियल नहीं मिलता है ता यह क्या तरीका है काम करने का। एक अप्लीकेशन आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है काम कुछ नहीं होता।

I want raw materials This is one instance which I have quoted I can give you in writing.

आखिर आज किस प्रकार से आप के आफिसर्स डील करते हैं। कोई गवर्नमेंट हो, उस का डाइरेक्टर यह समझता है कि यह मेरी रेस्पॉसिबिलिटी नहीं है। पावर नहीं मिलती, रा मंटीरियल नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता और कोई उस की जिम्मेदारी नहीं लेता। आखिर किसी की रेस्पॉसिबिलिटी हानी चाहिए।

अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप के लेबर का क्या हाल है वह देखिए। आप के जो अपने सेक्टर्स हैं उन में क्या हाल है।

'The third five year Plan has observed that for the peaceful revolution of the economic system on a democratic basis, it is essential that workers' participation in the management should be accepted as a fundamental principle and urgent need'

Has it been implemented or not

यह थर्ड फाइव इयर प्लान के अन्दर दिया हुआ हुआ है। आखिर वर्कर्स का आप पार्टिसिपेशन चाहते हैं या नहीं? अगर नहीं चाहते हैं तो कहिए कि हम नहीं चाहते। लेकिन चाहते हैं तो आप के खुद के सेक्टर्स में वह नहीं है। ता कि मैं आप समझते हैं कि यह होगा? आप कहते हैं कि इस में लेबर के अन्दर इसेटिव पैदा होगा। यह आप का टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट है

The number of Indian scientists abroad who registered themselves with the CSIR during the third Plan was about 6,900. A detailed breakdown of the limited available data is provided in Table 3.7 to show the seriousness of the 'Brain Drain' problem in the Indian context'

What is the sense?

अगर माइम और टेक्नोलॉजी में मारा ब्रेन ड्रेन होता है, मारे साइंटिस्ट और इंजीनियर बाहर चले जाते हैं आप के देश में कोई रिमचें न होता है और केवल खर्चा ही खर्चा होता तो ह्यूट इज दी सेंस?

Here is the Report of the Public Accounts Committee

'The Committee had an occasion to review certain aspects of the working of the NRDC and the CSIR in 1969-70 and from the information made available to the Committee with regard to the working

of the Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur, the Committee finds that during 14 years of its existence, the institute incurred an expenditure of Rs 6.92 crores, out of which about Rs 3.87 crores was of a recurring nature'

You will kindly go through this report and find out what the technical institutions are doing

MR DEPUTY-SPEAKER That is a good sentence to conclude with

SHRI M C DAGA I am finishing It says that the expenditure incurred on pay and allowances on the staff during the year 1971-72 was Rs 43.87 lakhs, and for non-academic staff it was Rs 27 lakhs

आप का एक्सपेंडीचर बढ़ता जाता है और इधर आप का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आपके साइंटिस्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, आप के इंस्टीट्यूशनस वर्क नहीं कर रहे हैं।

व्यवधान) मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

आप ने मेहरवानी कर के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर जोधपुर को ले लिया, सिरोही को ले लिया जालौर को ले लिया लेकिन बीच में पाली को छोड़ दिया। पाली में हाथ में काम करने वाले हैं प्रोसेस में काम करने वाले लोग हैं। वह हाथ में काम करते हैं फिर भी उन के ऊपर ड्यूटी लगती है। वह पावर वाम में नहीं लाते मारा काम हाथ में करने हैं। पन्द्रह सो रुपये की उन की मशीन और 3 हजार रुपये उस के ऊपर कम्पाउन्ड गकमाइज ड्यूटी लगाते हैं किस प्रकार में वह आगे बढ़ सकते हैं। शर्ट टाइम में इतना ही बह वर में समाप्त करता हूँ?

SHRI K S CHAVDA (Patan) Mr Deputy Speaker Sir within the 10 minutes at my disposal I would like to deal with only the foreign sector vis a vis the Indian sector in relation to the industrial development that is taking place in our country

[Shri K. S. Chavda]

Sir, at the outset, I would like to make it clear that I am not against foreign firms as such. But, at the same time, I do feel that the foreign firms should not exploit the Indian Industries. In the initial stages of industrial development in our country, we took the help of foreign firms, and as industries in India developed, we should have reduced our dependence on foreign firms. But, this is on the increase and Government is giving encouragement to foreign firms to grow bigger and bigger at the cost of Indian industries.

Take for example. Pfizer limited. Their initial equity was Rs. 2 lakhs and at present, their equity is Rs. 5.6 crores. The assets built up by the Company from out of their profits are worth Rs. 52 crores. The amount repatriated directly to America, in the year 1970, was Rs. 63.13 lakhs; in the year 1971, it was Rs. 68.20 lakhs and in the year 1972, it was Rs. 68.21 lakhs. I would like to give another example of Glaxo Laboratories. Their initial equity was Rs. 1.5 lakhs and their present equity is Rs. 7.5 crores. Their assets are now worth Rs. 65 crores. Further, they have repatriated large amounts from out of their profits made in this country. Another example is that of Firestone. They have increased their assets from Rs. 20,000 to Rs. 55 crores. I do not want to take the time of the House by giving more examples. But, I would certainly ask Shri C. Subramaniam, Minister of Industrial Development, through you, Sir, to explain to this house and through this House, to the whole country, as to why production of cigarettes worth Rs. 160 crores out of a total production worth Rs. 300 crores per annum, in our country, has been entrusted to foreign firms by the Government; secondly, why the production of coca cola has been entrusted to foreign firms, when enough syrups and sharbats are available in our country, produced by the small scale sector? Sir, it is highly scandalous that foreign firms, as admitted by

the Government, have exceeded their licensed capacity and thereby contravened the conditions in regard to licensing, namely, capacity specified in the licences. Such firms have made themselves liable to action under the provisions of the Industries Development and Regulation Act, 1951. But, no action has been taken by the Government for reasons best known to them. But my information is, the question of taking penal action against foreign firms which have indulged in unauthorised production in this country was considered in a halting and half-hearted manner in a number of ministries and put up to the concerned Cabinet Sub-committee for decision. The Committee did take some decisions, but they have not been implemented. The firms guilty of unauthorised production have got pulls and pressures in various ministries and Departments of Government and with the connivance and collusion of officers, they can manage to see that Government decisions taken at the highest level are either indefinitely postponed or not implemented at all. Therefore, certain points arise out of these: 1. How long did each firm indulge in unauthorised production? 2. Were periodical production returns sent to the DGTD and if so, what action did DGTD take in this matter? 3. Did DGTD sanction imported raw materials on the basis of unauthorised production and if so, under what authority? 4. Has the unauthorised production compelled the Indian sector to curtail their production or prevent them from applying for Industrial licence? 5. How much profits have been made by these firms from unauthorised production and to what extent the profits have been repatriated and what assets have been built out of these profits by them in our country? The firms have been allowed to indulge in unauthorised production with impunity on the ground that it is the intention of the Government to allow the production and had these firms not over-produced, Government would have been compelled to import such items involving expenditure on foreign ex-

change. If this argument is to be admitted, it strikes at the root of licensing of industries. My advice to Government is, in that case the licensing of industries should be scrapped altogether. Why should the Government give the impression that rules and regulations are meant only for the Indian sector and foreign firms with their huge resources and influence can contravene the laws of the land with impunity?

I would like to make a few suggestions for the consideration of the Government. 1. The licensing committee has done a good job in disposing of 3540 cases in 1973 as compared with 2252 cases in 1972. My suggestion is there is need for continuous vigilance to see that foreign firms do not get an upper hand over Indian firms under the guise of export promotion, liquidation of equity etc. 2. While Government has delicensed medium-scale industries whose investment is upto Rs. 1 crore, this is not beneficial because the conditions of registration and delicensing are the same. Therefore, there should be completed delicensing for medium-scale industries. 3. Diversification should be allowed to Indian firms with minor balancing equipment and imported raw materials to the tune of at least 40% of the licensed capacity for conversion of obsolete items into new articles. 4. In spite of the improved procedure of licensing of industries, the Indian entrepreneur, whose applications are rejected, should be allowed to be heard by the full Licensing Committee. 5. The reports of the Bureau of Industrial Costs and Prices should be considered to be equal in importance to the reports of the Tariff Commission. Out of the five reports submitted by the BICP in 1973 not a single report has yet been implemented. 6. For the development of the 230 backward districts what is required to be done is that there should be an Open General Licensing system for Indian entrepreneurs only. 7. For the proper financing of industries in backward districts the restrictions put upon lending by commercial institutions should be lifted as financial institutions have failed to

meet the requirements. 8. Non-S.I.A. applications pending before Government, which amount to roughly 4,000, should be disposed of within a reasonable time limit. 9. Firestone, M/s. Abot Anglo French and other foreign firms, which have a multi-national character, had initially very small investments but today they have grown to be giants and have come in the way of Indian industry. They ought to be cut down to size, if Indian industry is to grow and prosper. 10. All COB licences to foreign firms, based on wrong information and diversification etc. be revoked immediately. Lastly, all permission letters which are proved illegal and which have no backing of any Act must be scrapped immediately, in the interest of the Indian Sector.

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री  
(श्री जियार्जरंहमान अंसारी) उपाध्यक्ष  
जी, इन बहस में हिस्सा लेने में मैं सिर्फ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज मेन्टर, खादी ऐंड विलेज इंडस्ट्रीज, सेरिकल्चर और क्वायल पर अपनी बहस को महत्त्व रखूंगा। कल्ल इसके कि मैं इस बहस के सिलसिले में कुछ कहूँ, मैं उन आनरेबिल मेम्बर्स का जिन्होंने खुशीसयत के साथ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के सिलसिले में, क्वायल इंडस्ट्री और सेरिकल्चर इंडस्ट्री के सिलसिले में, खादी ग्रामोद्योग के सिलसिले में अपने सुझाव दिए हैं और अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले को हमें तीन जावियों से देखना चाहिए। तीन एंग्लिस से मैं उस पर कुछ थोड़ी बहुत रोशनी डालना चाहता हूँ और यह कोशिश भी करूंगा कि इस सिलसिले में हमारे आनरेबिल मेम्बर्स ने जो कुछ बातें कही हैं उन बातों का कुछ जवाब भी हो जाये। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के सिलसिले में एक एंग्लिश तो यह है कि हमारी दिक्कतें क्या हैं।

[श्री जियाउर्रहमान असारी]

वह दिक्कतें जो स्माल स्केल एन्टरप्रिन्वोर्स को पेश आती हैं और साथ ही स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रमोशन के काम में लगे हुए लोगों की जो दिक्कतें हैं, वह दिक्कतें क्या हैं। इसका दूसरा पंगिल यह है कि इन सारी दिक्कतों और परेशानियों के बावजूद जो हमारे सामने हैं, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज सेक्टर में हमारी क्या पर्फार्मेंस रही है, हमारे क्या रिजल्ट्स रहे हैं और क्या हमारे अचीवमेंट्स रहे हैं। इसका तीसरा पंगिल यह है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के सिलसिले में, छादी ग्रामोद्योग के डेवलपमेंट के सिलसिले में आगे के हमारे प्रोग्राम्स क्या हैं और किम हद तक हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं।

जैसा मैंने पहले अर्ज किया और जैसा हमारे आनरेबिल मेम्बर्स ने भी कहा, हमारी बहुत सी कठिनाइयाँ और दिक्कतें हैं और अभी हाल ही में हमारे कुछ फाइनेंशियल और एकोनामिक कॉन्स्ट्रेंट्स आ गए हैं जिनकी वजह से उन दिक्कतों और परेशानियों में इजाफा हुआ है। खास तौर से कुछ आनरेबिल मेम्बर्स ने रा-मैटीरियल की तरफ तबज्जह दीलाई है कि रा-मैटीरियल दिक्कत ऐसी बुनियादी दिक्कत है जिसके बगैर इंडस्ट्रीज का चलना मुमकिन नहीं है। रा-मैटीरियल के सिलसिले में यह शुबहा नहीं है कि दिक्कत है, परेशानी है और उस परेशानी को हल करने के लिए बहुत बड़ी हद तक, कुछ इम्पोर्टेड रा-मैटीरियल के सिलसिले में पार्लिसी को लिब्रलाइज किया गया है और इंडिजीनस रा-मैटीरियल के सिलसिले में भी जो रूकथं रा-मैटीरियल है—बुसूसियत के साथ आयरन ऐंड स्टील और डूमरे नान फेरस मेटल्स—उनमें भी पहले मुकाबले में स्माल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर को निस्वतंत्र में उन आंकड़ों में जाना नहीं चाहता लेकिन यह एक वाक्या है कि

उसको पहले के मुकाबले में ज्यादा एलोकेशन मिल रहा है लेकिन इसमें उस परेशानी और मुसीबतों का हल निकलने वाला नहीं है।

एक बात यहाँ पर कही गई, एक सवाल के जवाब में भी यह बात यहाँ पर प्रा चुकी है कि रा-मैटीरियल के सिलसिले में स्माल स्केल सेक्टर और लार्ज स्केल सेक्टर के बीच में कुछ डिस्क्रिमिनेशन है। हम ने तो खुले दिल और सफाई के साथ पहले भी कहा है कि लार्ज स्केल सेक्टर और स्माल स्केल सेक्टर में रा-मैटीरियल देने के सिलसिले में स्माल स्केल सेक्टर को जिन बुनियादों पर हम देने हैं वह मुख्तलिफ लार्ज स्केल से और उसकी वजह यह है कि हमारे पास स्माल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स की कोई एक सही तस्वीर नहीं है, हम को यह नहीं मालूम है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कितना रा-मैटीरियल चाहिए, कौन सा रा-मैटीरियल किम मात्रा में चाहिए। इसी लिए भट्ट कमेटी ने जहा बहुत सी बैल्युणबिल सजेन्स दिए हैं स्माल स्केल सेक्टर को प्रमोट करने के सिलसिले में वहाँ पर एक सिफारिश यह भी की है कि स्माल स्केल—इंडस्ट्रियल यूनिट्स का बड़े पैमाने पर माने मुन्क में सन्स होना चाहिए। हमारे एक आनरेबिल मेम्बर ने कटमोशन मूव करन हुए एस्टीमेट्स कमेटी की 35वीं रिपोर्ट की तरफ तबज्जह दीलाई थी जिसमें इस तरफ इशारा किया गया है कि सबसे बड़ी इबाईक जो है वह यह है कि कोई सन्स नहीं है, कोई डाटा नहीं है जिसकी वजह से स्माल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा हैडीकैप्ड है। इसलिए एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट की लाइट में और भट्ट कमेटी की रिपोर्ट की लाइट में भी इस बात को बहुत टाप प्रायटी दी गई कि हमारे सामने सही तस्वीर पूरी तौर पर होनी चाहिए और इसीलिए सन्स के काम को शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है कि इस साल के प्राब्लि तक हमारे पास एक मुकम्मिल तस्वीर स्माल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रा जायेगी कि कितनी इंडस्ट्रीज हैं, कितना उनके लिए

रा-मैटीरियल चाहिए, किन किन स्टैट्स में चाहिए, कहा कहा वह लोकेटेड हैं। हम उम्मीद करते हैं इस डाटा के क्लेकट होने के बाद हमारी वह दिक्कत बहुत बड़ी हद तक दूर हो जायेगी। और फिर हम बालचन्द्रन कमेटी की उस रिपोर्ट को, जिस का हवाला अक्सर यहाँ दिया जाता है, हम उसली तौर पर उस को मान चुके हैं लेकिन उस के इमप्ली-मेंटेशन में डाटा न होने से, बीग सैन्स के मुमकिन नहीं है, हमारे लिये दिक्कत है और हम समझते हैं कि सैन्स का काम पूरा होने के बाद शायद उस कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तौर पर इमप्लीमेंट करने के काबिल हो जायेंगे उस हद तक जो उस की रिकमन्डेशनस हैं उन को बड़ी हद तक पूरा करने की हालत में हो जायेंगे।

14 hrs.

उपाध्यक्ष महाशय, रा-मैटीरियल के अलावा और जो दूसरी दिक्कतें हैं उन में बहुत सी ऐसी हैं जिन पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि वह दिक्कतें हैं पावर की कमी, इनफ्रास्ट्रक्चर का न होना, और मुक्तलिफ किस्म की दिक्कतें हैं जिन पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे पावर की शार्टेज है, जो हमारे मुल्क में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में है, उसकी लाइट में हम फरक के साथ कह सकते हैं कि हम फिर भी अपनी जगह पर मजबूती के साथ कदम जमाये खड़े हैं। यह कम श्रेय की बात नहीं है। इसलिये मैं उम सिलमिने में ज्यादा नहीं कहना चाहता।

जो हमारी परफोरमेंस और अचीवमेंट रहे हैं चौथे प्लान में उन के मुताबिक कुछ दो, चार बाते अर्ज करना चाहता हूँ। हमारी यूनिट्स जो रजिस्टर्ड थी 1998 में उन की तादाद थी 1.71 लाख, लेकिन 1973 में उन की तादाद बढ़ कर 4.05 लाख हो गई। ऐम्प्लायमेंट की दृष्टि से 1968 में 29.6

लाख लोग काम करते थे जिनकी तादाद बढ़ कर 1973 में 45 लाख हो गई। इनवेस्टमेंट की दृष्टि से 620 करोड़ के फिक्सड असेट्स में जो बढ़ कर 1973 में 814 करोड़ हो गये। प्रोडक्शन स्माल स्केल में किस हद तक बढ़ा है इस को भी जरा देखा जाय। 1968 में 3207 लाख रु० का प्रोडक्शन था जो 1973 में बढ़कर 6,249 लाख रु० तक पहुँच गया। ऐक्सपोर्ट 1970 में 93.17 करोड़ रु० था वह बढ़ कर 132.03 करोड़ स्माल स्केल सैक्टर प्रोडक्ट्स का हो गया। ऐन्सिनियरीज के डेवलपमेंट के आकड़ों का जरा मुलाहिजा फरमाया जाय। लाज स्केल सैक्टर की ऐन्सिनियरीज की तादाद 1969-70 में 2,008 थी जो 1971-72 में बढ़ कर 7,606 हो गई। इन फिगर्स को पेश करके मेरा यह मशा नहीं है कि इन पर बहुत फरक किया जा सकता है। हर गिज नहीं। मैं महसूस करता हूँ कि बहुत बड़ी हद तक स्माल स्केल इंडस्ट्रिज सैक्टर को डेवलप किया जाना चाहिये था जो कि नहीं हो सका। लेकिन अगर यह फिगर्स कुछ थोड़ा बहुत इशारा करती हैं तो यह कि हम स्टेगनेन्ट नहीं रहे हैं, और जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि स्माल स्केल सैक्टर में हम स्टेगनेन्ट रहे हैं तो इन फिगर्स से स्टेगनेशन जाहिर नहीं किया जा सकता।

यह सही है कि स्माल स्केल सैक्टर लाज स्केल सैक्टर के मुकाबले में इम मुल्क की इकोनॉमी और ऐम्प्लायमेंट की दृष्टि से सब से ज्यादा महत्वपूर्ण सैक्टर है। लाज स्केल सैक्टर हमारे मुल्क की दौलत को बढ़ाने और इजाफा करने का एक कारण बन सकता है। लेकिन हमारे मुल्क की दूसरी सब में बड़ी प्रोबलम अन्-ऐम्प्लायमेंट की है उम का हल करने का सबसे बड़ा जरिया स्माल स्केल सैक्टर है। कमपरीजन के लिये यह बात कही जा सकती है कि अगर हम किन्ही दो स्टेट्स को ले, एक जगह पर लाज स्केल इंडस्ट्रीज काफी डेवलप हुई हो और दूसरी स्टेट जहाँ

[श्री जिवाउरहमान असादी]

पर लार्ज स्केल सैक्टर इंडस्ट्रीज का म्यूरिबली कम डेवलप हुई हो, स्माल स्केल सैक्टर इंडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप हुई हो तो मालूम किया जा सकता है आसानी मे कि वह स्टेट जहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है वह पिछडी हुई है बनिस्पत उस स्टेट के जहाँ पर स्मल स्केल सैक्टर इंडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप हुई है। वहा पर ऐम्प्लायमेंट ज्यादा पैदा हुआ है, और ज्यादा खुशहाली प्रायी है।

इस लिये मैं कहना चाहता हू कि हम लोग इस बात से कोई बहुत ज्यादा मुतमइन नहीं है और इस सैक्टर को ज्यादा तेजी से बढ़ाना चाहते है। लेकिन हमारी निमितेशन्स है और जो तबज्जह इस सदन के माननीय सदस्या ने स्माल स्केल सैक्टर की तरफ दिखायी है उस के भरोमे पर मैं फख के साथ कह सकता हू कि स्माल स्केल इंडस्ट्रियल सैक्टर के बढने को कोई नहीं रोक सकेगा, और यह तरक्की करेगा।

उपाध्यक्ष जी बैंकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट हमारी बहुत बडी प्रोबलम है। बैंकवर्ड एरियाज और बैंकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के बारे मे बहुत से मंत्रानर ने तशबीश का इजहार किया है कि बैंकवर्ड एरियाज को डिक्लेयर करने मे कोई डिस्ट्रिमिनेशन किया गया है। लेकिन बैंकवर्ड एरियाज और डिस्ट्रिक्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट के कसलटेशन से प्लानिंग कमीशन मुकर्रर करता है। उस के कुछ नीम्स है। मैं इन्कार नहीं करता हो सकता है कि कुछ डिज़रविंग जिले जो वाकई बैंकवर्ड हो, छूट गये हो। लेकिन बैंकवर्ड जिलो को तय करना प्लानिंग कमीशन का काम है जो वह स्टेट गवर्नमेंट से कमलट कर के करता है। अलबता यह हमारा काम है कि जब बैंकवर्ड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हो जाब तो हमारी सारी तबज्जह उस के डेवलपमेंट की तरफ लज जानी चाहिये। मैं कोई लम्बे चौड़े दावे नहीं करना चाहता, बैंकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का डेवलपमेंट कोई बहुत आसान काम नहीं

है। आखिर वजह तलाश करनी पडेगी, सब से पहले हम को उन डिस्ट्रिक्ट्स और एरियाज के बैंकवर्ड होने की पिछडे रह जाने की वजह क्या है, यह देखना होगा। जब मुस्क की इकोनोमी डिक्लेप कर रही है, इंडस्ट्रीज बढ रही हैं तो कुछ एरियाज रह जाए, बैंकवर्ड एरियाज डिक्लेप न कर पाए तो उसकी वजह हमें तलाश करनी पडेगी और उस वजह को तलाश किए बगैर उस तरफ हमे बितनी एंटेनन पे करनी चाहिये नहीं कर सकते हैं। इनफास्ट्रक्चर की कमी है, दूसरे प्रापर एटरप्रेन्प्योरसिप का न होना है, तीसरे टेक्नीकल नो हूऊ का न होना है और इसी तरह के दूसरे और भी बहुत से फैक्टर्स हैं—

श्री मूल खन्ड डांगा . नौकरशाही को पहले ठीक करो।

श्री जिवाउरहमान असादी : इन चीजो को पहले कर ले उसके बाद उमको भी कर लेंगे। ये बुनियादी चीजें हैं। बहुत आसान नहीं है। इसी वास्ते हमारी सारी तबज्जह बैंकवर्ड एरियाज के डिक्लेपमेंट की तरफ है और उसके लिए मुकतलिफ किस्म क इन्वेस्टिञ्ज हमने प्रायोज किए हैं ताकि एटरप्रेन्प्योर्ज वहां जाकर उन तमाम इन्वेस्टिञ्ज की वजह से इंडस्ट्रीज, लगान और बहा का इंडस्ट्रियल डिक्लेपमेंट हो।

इंडस्ट्रियल डिक्लेपमेंट का जहा तक तात्सुक है, स्माल स्केल इंडस्ट्रियल सैक्टर एक नए मोड पर आ गया है। जो अब तक हमारा एप्रोच स्माल स्केल इंडस्ट्रिज के डिक्लेपमेंट का रहा है और अब नए पाच मासा प्लान मे जा हैं, दोनो मे बहुत फर्क है। नए प्लान मे हम हकीकी जोर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के असिस्टेंस प्रोग्राम के ऊपर लगाना चाहते है और यह बात कह देना चाहते हैं कि यह असिस्टेंस इंटिग्रेटेड असिस्टेंस हो। मिनिस्टर इचार्ज की हैसियत से मुझे मुकतलिफ सूबों में जाने का मौका मिला है और मैंने पाया है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के डिक्लेपमेंट के सिस्-मिलि में एक बहुत बडी बाधा यह भी है कि



इट्रैटिड असिस्टेस हम एंटरप्रेन्वोर्ज को नहीं दे पा रहे हैं और डिफेंट जो इस्टीट्यूशज लगी हुई है स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोमोट करने के सिलसिले में इनके बीच कोओर्डिनेशन की कमी है। हमारा जोर अब इस बात पर है कि हम स्माल स्केल एंटरप्रेन्वोर को इट्रैटिड असिस्टेस दे मैनजमेंट कंसलटेसी और ट्रेनिंग के सिलसिले में, क्रेडिट एवेलिविलिटी के सिलसिले में, टेक्नीकल सर्विस और फेसिनिटीज के सिलसिले में और डोमैस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट की पोसिबिलिटीज को मान्य करने के सिलसिले में। यह फिफथ प्लान रा हमारा एक सीधा एप्रोच है। साथ साथ जो डिफेंट इस्टीट्यूशज और आर्गनाइजेशन स्माल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगी हुई हैं उनमें बीच हम कोओर्डिनेशन चाहते हैं ताकि सब मिल कर डिवेलपमेंट के काम को आगे बढ़ाने में एक साथ आगे चल सकें।

एक और एप्रोच पाचवे प्लान में हमारा इस सिलसिले में है। अब तक जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के डिवेलपमेंट का तरीका रहा है वह यह रहा है कि हम न कोई टेक्नाइकोनामिक सर्वे पहले से किसी बैंकबंड एरिया का नहीं करवाया, वहां पर लोकली अवैलेबल रा-मैटीरियल या इंडिजिनस रा-मैटीरियल जो है उसकी तरफ हमारी तवज्जह नहीं गई और स्केरस रा-मैटीरियल इस्तेमाल करने वाले यूनिट्स को रजिस्टर करके हमने समझा कि हम इस तरह से इन इंडस्ट्रीज को सेंट-अप करके इनको बढ़ावा दे सकते हैं। मेरी राय है कि स्माल इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो लोकली रा-मैटीरियल अवैलेबल है—

श्री राजबेब सिंह (बौनपुर) : मेरा एक ब्यवस्था वा प्रश्न है। मंत्री महोदय ने कहा है कि बैंकबंड एरियाज में रा-मैटीरियल लोकली अवैलेबल है या नहीं इसकी जांच नहीं कराई गई। मैं इसको साफ कर देना चाहता हू कि बैंकबंड एरियाज के लिए एक पटेल स्टेडी टीम एप्वाइंट हुई थी और उसने बताया था कि कौन-कौन सा रा-मैटीरियल कहा-कहां है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह मैं नहीं कहना चाहता कि नहीं हुआ है। मैं अर्ज यह करना चाहता हू कि आज हमारा जो मेन थ्रस्ट है जो जोर हम दे रहे हैं पाचवे प्लान में वह दे रहे हैं लोकली अवैलेबल रा-मैटीरियल के ऊपर, उनके एक्स्प्लायटेशन के ऊपर इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट के लिए।

SHRI PARIPOORNANAND PAINULI (Tehri Garhwal) Based on the locally available raw materials, I want to know, whether you would establish the industries here or you would export them outside

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : हमारी मजबूरी यह है कि हम एंटरप्रेन्वोर्ज का किसी खास जगह डाल कर वहां उनका उगा नहीं सकते हैं। एंटरप्रेन्वोर्ज हमको पैदा करने दोगे मुसाम। तीर पर अग्नेवल नहीं टाता पूरा हिन्दुस्तान का मूल है और अगर बाहर के एंटरप्रेन्वोर या कर वहां के लोकल रा-मैटीरियल का एक्स्प्लायट करके इंडस्ट्री सेंट अब करना चाहते हैं तो वे करेगे। अगर आप यह चाहते हैं कि हम उगाए एंटरप्रेन्वोर्ज का तो यह हमारे बस की बात नहीं है।

पाचवे प्लान में हम एन०एम०आई० सी की नई आबिज—खोलना चाहते हैं और स्पेशलाइज्ड सर्विस वा प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं और फारेस्ट बेन्ड इंडस्ट्रीज के लिए एमिनरी डिवेलपमेंट के लिए दा हजार नए यूनिट्स इलेक्ट्रानिक्स के लिए खोलना चाहते हैं। यह हमारा नया प्लान में एक मेन ट्रस्ट है।

एन०एम०आई०सी० के बारे में शिकायत हुई है। यह एन०एम०आई०सी० के बारे में शिकायत है जो बड़ी बेल्युएबल खिदमत प्रजाम दे रहा है। यह ठीक है कि उसके बॉरुंग में दिक्कतें और परेशानिया महसूस की गई जिसकी वजह में एक कमेटी एप्वाइंट हुई और उस कमेटी की रिपोर्ट में शिकायत मिनिस्ट्री के जेरे गीर है और उनकी

[श्री जियाउर्रहमान अनसारी]

रौशनी में हम कुछ उसका स्टीम लाइनिंग करना चाहते हैं, उसके बकिंग का, उसके तरीको का और मेनली नैशनल स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का जहां तक हायर परचेज का ताल्लुक है हम चाहते हैं कि रटेस के लिए रिफाइनेम इस्टीट्यूशन के तौर पर काम करें। इसको हम स्टेजिज में करेंगे। फर्स्टस्टेज में एक लाख तक रिफाइनेंस इस्टीट्यूशन के तौर पर हम चाहते हैं कि एन० एस० आई० मी० वर्क करें। एक लाख से ऊपर हायर परचेज मशीनरी के लिए वह खुद करेंगी। लेकिन सैकड़ रटेज में हम सारा काम स्टेट गवर्नमेंट्स के जरिये से, या स्टेट्स के इस्टीट्यूशन के जरिये से करना चाहते हैं। हम वन मैन कमेटी का इस प्रोजेक्शन को कन्सिडर कर रहे हैं कि एन० एस० आई० सी० रीफाइनेसिंग इस्टीट्यूशन के तौर पर वर्क करें।

कुछ खादी एण्ड विल्नेज इंडस्ट्रीज कमीशन की एक्टिविटीज का भी तज्जिबिरा धाया। इस कमीशन की एक्टिविटीज कोई महज समझती, औद्योगिक, एक्टिविटीज नहीं हैं, बल्कि उस के साथ हमारा सोशल अपलिफ्ट का प्रोग्राम और एक फिलासफी जुड़ी हुई है कि किस तरह ग्राम लोग घर में थोड़ा बहुत काम कर के मुक्त की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, गावा की लोकल जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस सिलसिले में खादी एण्ड ग्रामोद्योग कमीशन ने काफी काम किया है। यह सही है कि जब खादी एण्ड ग्रामोद्योग कमीशन उस काम को मुख्तलिफ इस्टीट्यूशन के जरिये से करेगा—वह एक बड़ा डीमेटलाइज्ड सेंक्टर है—, तो उस में कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट्स होंगे, उनमें मैं इन्कार नहीं करता हूँ। इस बात की मुसलमल कोशिश की जा रही है कि किस तरह से उन डिफेक्ट्स को दूर किया जाये।

जहां तक उस में प्रोडक्शन बढ़ाने और माड्युनाइजेशन लाने का सवाल है, हम खादी के सिलसिले में ट्रेडीशनल चर्खों से ग्रम्बर चर्खों

तक और ग्रम्बर चर्खों से न्यू माडल चर्खों पर आए हैं, जिससे खादी का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उन में जो लेबर लगे हुए हैं, उन की बेजिज में भी इजाफा होगा। लोक बस्त्र का एक नया प्रोग्राम भी हमारे जेरे गौर है। खादी एण्ड ग्रामोद्योग कमीशन ने प्रोग्राम बनाया है कि मामूली इन्सान जो कपडा इस्तेमाल करता है, उस को किस तरह खादी के जरिये से बनाया जा सके, ताकि वह सस्ता बने और लोग उस को ले सके। उसमें म्पिनिंग सेंक्टर में कुछ हद तक पावर इन्तेमाल कर के सस्ता और अच्छा कपडा बनाने का एक प्रोग्राम ग्रडर कन्सिडरेशन है।

कायर इंडस्ट्री के सिलसिले में कुछ मेम्बरो ने बहुत ही तथवीश का इजहार किया है मैकेनाइजेशन के बारे में। इस लिये मैं अपना यह फरीजा समझता हूँ कि कायर इंडस्ट्री को मैकेनाइज करने के सिलसिले में गवर्नमेंट के रख को सफाई के साथ अर्ज कर दूँ। गवर्नमेंट कायर इंडस्ट्री को इस अदाल से और उस हद तक मैकेनाइज करने के हरगिज-हरगिज हक में नहीं है कि उससे अनएम्पलायमेंट की प्रोबलम पैदा हो जाय। गवर्नमेंट का कर्नई तौर पर यह रख है कि वह इस हक में नहीं कि अनएम्पलायमेंट की प्रोबलम किकेट हो। केरल में 283 लोकली फीब्रिकेटिड मशीन्ज, जिन के लिये लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, रेटिंग सेंक्टर में चलने लगी थी और उससे काफी अनएम्पलायमेंट पैदा हुआ था। गवर्नमेंट आफ केरल ने सही वक्त पर कदम उठा कर उन 283 मशीन्ज को, जिन्होंने काफी लोगों को आउट आफ एम्पलायमेंट कर दिया था, डी० आई० आर० के तहत बैं कर दिया।

हम इस तरह के मैकेनाइजेशन के हक में नहीं हैं, जो अनएम्पलायमेंट लाने वाला है, जो लोगों की रोजी छिन से और उन को नंगा और भूखा कर दे। लेकिन अगर ऐसा माड्युनाइजेशन हो, या इस हद तक माड्युनाइजेशन हो, जिन से हमारी एम्पलायमेंट पर

कम असर पड़े, लेकिन हम एकसपोर्ट की अच्छी मार्केट हासिल कर सके, तो हम हमेशा उस के हक में रहे हैं। इसलिये इस सिलसिले में गवर्नमेंट की काशस मैकेनाइजेशन की पालिसी है।

1961 में गवर्नमेंट ने यह तय किया था कि मैनूफैक्चरिंग सेक्टर में कायर इंडस्ट्री की एक लिहाई प्राइवेट्स को मैकेनाइज किया जाय। तभी से तीन मैकेनाइज्ड युनिट्स मैनूफैक्चरिंग सेक्टर में लगे थे,—एक पब्लिक सेक्टर में कायर बोर्ड के अदर और दो प्राइवेट सेक्टर में। इस के अलावा मैनूफैक्चरिंग सेक्टर में या स्पिनग सेक्टर में कोई फर्दर मैकेनाइजेशन नहीं हुआ है।

एक आनरेबल मेंबर ने सिरीकल्चर के बारे में कहा है। मैं इस तपसील में नहीं जाना चाहता कि किम तरह से मिल्क बोर्ड ने, और मुख्तलिफ जगहों पर हमारे जो सिरीकल्चर रिसर्च स्टेशन हैं, उन्होंने किम तरह सिरीकल्चर इंडस्ट्री को डेवेलप किया है। मैं आप के माध्यम से आल-इंडिया मिल्क बोर्ड को मुबारकवाद देना चाहता हूँ और उम में काम करने वाले रिसर्च ऑफिसर्ज और डायरेक्टर्ज को भी मुबारकवाद देना चाहता हूँ कि हमने किस तरह से—मैंने खुद अपनी आँखों से कनार्टक स्टेट में देखा है—मल्टी-वोल्टीन से वाई-वोल्टीन की तरफ स्विच ओवर किया है, और किस तरह से वहाँ किसान ज्यादा से ज्यादा सिल्क पैदा करने की तरफ बढ़ रहा है।

सिल्क इंडस्ट्रीज के सिलसिले में एक और महत्वपूर्ण कदम जेरेनर है। अभी तक हमारा ज्यादा जोर सिर्फ मलवारी सीड पर रहा है। एक नया प्रोग्राम हमारे अडर कनसिडरेशन है कि सब-हिमालयन रिजन में, आसाम से ले कर काश्मीर तक, जो ओक पैदा होता है, उस से किस तरह ओक टसर डेवेलप किया जाय और अगर उस के लिये जरूरी समझा

जाय, तो, एक ओक टसर डेवेलपमेंट कार्पोरेशन को वजूद में लाया जाय। दुनिया में हिंदुस्तान के सिल्क की माँग को देखते हुए हम किस तरह इस इंडस्ट्री को डेवेलप कर के फारेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं, उस पर भी ज्यादा जोर दिया जाना चाहिये।

वक्त की कमी का एहसास करते हुए, जो बहुत सी बातें मैं विस्तार के साथ कहना चाहता था, मुझे अफसोस है कि मैं नहीं कह सका। मैं माफी चाहता हूँ उन आनरेबल मेंबरान से, जिन की कोई बात वक्त की कमी की वजह में छूट गई हो। उन्होंने इस सेक्टर पर जो इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट का निस्वनन एक बीकर सेक्टर है, जो तबजुह की है, उस के लिये मैं उन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हर वक्त उन से गाइडेंस लेना चाहता हूँ और उन की एक्सिस्टेंस के लिये और उन के खयालान को हासिल करने के लिये उन की तरफ देखना चाहता हूँ।

ادیوگک وکاس مترالہ میں

اب مسری (سری صیالرحمان انصاری) :

اپادھیکیکھس حی ، اس بحث میں حصہ لینے میں میں صرف شمال سیکل انٹسٹری سیکٹر ، کھادی اینڈ ویلج انٹسٹری ، سریکلچر اور کوانٹر پر اپنی بحث کو محدود رکھوںگا۔ قبل اس کے کہ میں اس بحث کے سلسلے میں کچھ کہوں ، میں ان آریبل ممبرز کا جیہوں نے خصوصیت کے ساتھ شمال سیکل انٹسٹریز کے سلسلے میں کوانٹر انٹسٹری اور سریکلچر انٹسٹری کے سلسلے میں ، کھادی گرام ادیوگ کے بارے میں اپنے سچے و دئے میں اور اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے لئے میں

[شری ضیا الرحمان انصاری]

انکا بہت بہت سکرہ ادا کرنا چاہا  
ہوں۔

انڈسٹریل ڈویلپمنٹ کے معاملے کو  
ہمیں بن زاویوں سے دیکھا جائے۔  
بن انگلر سے اس پر کچھ بھڑی  
بہت روسی ڈالنا چاہتا ہوں اور یہ  
کوئٹہ بھی کرونگا کہ اس سلسلے  
میں ہمارے آرڈر سمیر نے جو کچھ  
ناس کہی ہیں ان ناپوں کا کچھ  
حواب بھی ہو جائے۔ شمال سکیل  
اسٹریٹ کے ڈویلپمنٹ کے سلسلے میں  
انک اینگل یہ ہے کہ ہماری دس  
لیا ہیں۔ وہ دس جو شمال سکیل  
انٹرویوور کو دس آئی ہیں اور  
ساتھ ہی شمال سکیل انڈسٹری کے  
بروموس کے کام میں لکھے ہوئے لوگوں  
کی جو دس ہیں وہ دس کا ہیں۔  
اس کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ ان  
ساری دسوں اور پریسوں کے ناوجود  
جو ہمارے سامنے ہیں۔ شمال سکیل  
انڈسٹری سیکٹر میں ہماری کیا  
پرفورمنس رہی ہے۔ ہمارے کیا  
ریٹ رہے ہیں اور کیا ہمارے  
اچومینٹ رہے ہیں۔ اس کا سرا  
انگل یہ ہے کہ شمال سکیل انڈسٹریل  
سیکٹر ڈویلپ کرنے کے سلسلے میں،  
کھادی گرام اڈیوگ کے ڈویلپمنٹ  
کے سلسلے میں آگے کے ہمارے  
پروگرام کیا ہیں اور کس حد تک  
ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔

جس میں نے پہلے عرض کیا اور  
جیسا ہمارے آنریبل ممبرز نے بھی  
کہا، ہماری بہت سی کٹھنٹیاں اور  
دقیق ہیں اور انہی حال ہی میں  
ہمارے کچھ فائنسل اور اکاؤنٹ  
کاسٹریٹس آگے ہی حکمی وجہ سے ان  
دفتروں اور پریسیوں میں اضافہ ہوا  
ہے۔ خاص طور سے کچھ آرڈر ممبرز  
نے رامیٹریل کی طرف توجہ دلائی ہے  
کہ رامیٹریل کی دس ایسی سادی دس  
ہے جس کے بعد انڈسٹری کا حلنا ممکن  
نہیں ہے۔ رامیٹریل کے سلسلے میں یہ  
سہہ نہیں ہے نہ دس ہے، برسانی  
ہے اور اس برسانی کو حل کرنے کے  
لئے بہت بڑی حد تک، کچھ امور  
رامیٹریل کے سلسلے میں نالسی کو  
لرلائر دنا ہے۔ اور اندھس  
رامیٹریل کے سلسلے میں بھی جو  
سکیرس رامیٹریل ہے ان میں بھی  
پہلے کے معاملے میں شمال سکیل  
انڈسٹریل سیکٹر کو نسبتاً۔۔۔ میں ان  
آنکڑوں میں جانا نہیں چاہتا۔ واقعہ  
ہے کہ اس کو پہلے کے معاملے میں  
زیادہ ایلوکسٹن مل رہا ہے لکن  
اس سے اس پریسی اور مصسوں کا حل  
نکلنے والا نہیں ہے۔

ایک ناب یہاں پر کہی گئی ہے،  
ایک سوال کے حواب میں بھی نہ ناب  
یہاں پر آچکی ہے کہ رامیٹریل کے  
سلسلے میں شمال سکیل سیکٹر اور لارج  
سکیل سیکٹر کے بیچ میں کچھ

ڈسکریمنٹیشن ہے۔ ہم نے تو پہلے دل اور صفائی کے ساتھ پہلے بھی کہا ہے کہ لارج سکیل سیکٹر اور شمال سکیل سیکٹر میں را میٹریل کے دینے کے سلسلے میں شمال سکیل سیکٹر کو جن کی بنیادوں پر ہم دیتے ہیں وہ مختلف ہیں۔ لارج سکیل سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس شمال سکیل انڈسٹریل یونٹس کی کوئی ایک صحیح تصویر نہیں ہے۔ ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ شمال سکیل انڈسٹریل یونٹس کو کتنا را میٹریل چاہئے، کون سا را میٹریل کس مائٹرا میں چاہئے۔ اس لئے بھٹ کمیٹی نے جہاں بہت سے ویلیو ایبل سچیشن دئے ہیں شمال سکیل سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے سلسلے میں وہاں پر ایک سفارش یہ بھی کی ہے کہ شمال سکیل انڈسٹریل یونٹس کا بڑے پیمانے پر ملک میں سینیسیس ہونا چاہئے۔ ہمارے ایک آنریبل ممبر نے کٹ موشن موو کرتے ہوئے ایسٹیمیشن کمیٹی کی پینتیسویں رپورٹ کی طرف توجہ دلائی تھی جس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سب سے بڑی ڈرائیک جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سینیسیس نہیں ہے، کوئی ڈاٹا نہیں ہے جسکی وجہ سے شمال سیکٹر انڈسٹریل سیکٹر بہت زیادہ ہیڈبکڈ ہے۔ اس لئے ایسٹیمیشن کمیٹی کی رپورٹ کی لائن میں بھٹ کمیٹی کی

رپورٹ کی لائن میں بھی اس بات کو بہت ٹاپ پرایوریٹی دی گئی ہے کہ ہمارے سامنے صحیح تصویر پوری طور پر ہونی چاہئے اور اسی لئے سینیسیس کے کام کو شروع کر دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس سال کے آخر تک ہمارے پاس ایک مکمل تصویر شمال سکیل انڈسٹریل سیکٹر کی آجائیگی کہ کتنی انڈسٹریز ہیں۔ کتنا ان کے لئے را میٹریل چاہئے۔ کن کن سٹیشن میں چاہئے۔ کہاں کہاں وہ لوکیڈ ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں اس ڈاٹا کے کولیکٹ ہونے کے بعد ہماری وہ دقتیں بہت بڑی حد تک دور ہو جائیں گی۔ اور پھر ہم بالچندر کمیٹی کی اس رپورٹ کو جس کا حوالہ اکثر یہاں دیا جاتا ہے۔ ہم اصولی طور پر اس کو مان چکے ہیں لیکن اس کے امپلی منٹیشن میں ڈاٹا نہ ہونے کے بغیر سینیسیس کے ممکن نہیں ہے۔ ہمارے لئے دقتیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سینیسیس کا کام پورا ہونے کے بعد شاید اس کمیٹی کی رپورٹ کو پوری طور پر امپلی منٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اس حد تک جو اس کی سفارشاتیں ہیں ان کو بڑی حد تک پورا کرنے کی حالت میں ہو جائیں گے۔

اپادھیکش سہودنے۔ را میٹریل کے علاوہ اور جو دوسری دقتیں ہیں ان میں بہت سی ایسی ہیں جن پر قابو

## [شری ضیا الرحمان انصاری]

ہانے کی کوشش جا رہی ہے۔ لیکن میں سویکار کرتا ہوں کہ وہ دقتیں ہیں پاور کی انفراسٹرکچر کا نہ ہونا، اور مختلف قسم کی دقتیں ہیں جن پر قابو ہانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جب سے پاور کی شارٹجج ہے، جو ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے، اس کی لائٹ میں ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پھر بھی اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ قدم جمائے کھڑے ہیں۔ یہ کیا تعریف کی بات نہیں ہے۔ اس لئے میں اس سلسلے میں زیادہ نہیں کہنا چاہا۔

جو ہماری ہرفار رمینس اور اچیومینٹس دے رہے ہیں چوتھی پلان میں ان کے مطابق کچھ دو چار باتیں عرض کرنا چاہا ہو۔ ہماری یونٹس جو رجسٹرڈ تھیں ۱۹۶۸ میں ان کی تعداد تھی ۱۰۷۱ لاکھ، لیکن ۱۹۷۳ میں ان کی تعداد بڑھ کر ۴۰۵۵ لاکھ ہو گئی۔ ایمپلائمنٹ کی نگاہ سے ۱۹۶۸ میں ۲۹۰۶ لاکھ لوگ کام کرتے تھے جن کی تعداد بڑھ کر ۱۹۷۳ میں ۴۵ لاکھ ہو گئی۔ انویسٹمنٹ کی درشتی سے ۶۲۰ کروڑ کے فکسڈ ایسٹس تھے جو بڑھ کر ۱۹۷۳ میں ۸۱۳ کروڑ ہو گئے۔ پروڈکشن شمال سکیل میں کس حد تک بڑھا ہے اسکو بھی ذرا دیکھا جائے۔ ۱۹۶۸ میں ۳,۲۰۷ لاکھ روپے کا پروڈکشن تھا جو ۱۹۷۳ میں بڑھ

کر ۶,۲۴۹ لاکھ روپے تک پہنچ گیا۔ ایکسپورٹ ۱۹۷۰ میں ۹۳۰۷ کروڑ روپے تھا وہ بڑھ کر ۱۳۲۰۵۳ کروڑ سال سکیل سیکٹر پروڈکشن کا ہو گیا۔ اینسی لیریز کے ڈویلپمنٹ کے آنکڑوں کا ذرا ملا خطہ فرمایا جائے۔ لارج سکیل سیکٹر کی آینی لیریز کی تعداد ۱۹۶۹-۷۰ میں ۲,۰۰۸ تھی جو ۱۹۷۱-۷۲ میں بڑھ کر ۷,۶۰۶ ہو گئی۔ ان فکرس کو پیش کر کے میرا یہ منشا نہیں ہے کہ ان پر بہت فخر کیا جا سکتا ہے۔ ہر گز نہیں۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بہت بڑی حد تک شمال سکیل انڈسٹریز کو ڈویلپ کیا جانا چاہئے تھا جو کہ نہیں ہو سکا۔ لیکن اگر یہ فکرس کچھ دھوڑا بہت اشارہ کرتی ہیں تو یہ کہ ہم سٹیڈنٹ نہیں رہے ہیں اور جیسا کہ مانیفیسٹو میں نے کہا کہ شمال سکیل سیکٹر میں ہم سٹیڈنٹ رہے ہیں تو ان فکرس سے سٹیڈنٹن طاہر نہیں کیا جا سکتا۔

یہ صحیح ہے کہ شمال سکیل سیکٹر لارج سکیل سیکٹر کے مقابلے میں اس ملک کی اکانامی اور ایمپلائمنٹ کی درشتی سے سب سے زیادہ مہتوہورن سیکٹر ہے۔ لارج سکیل سیکٹر ہمارے ملک کی دولت کو بڑھانے اور اضافہ کرنے کا ایک کارن بن سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کی دوسری سب سے بڑی پراہلم ان ایمپلائمنٹ کی ہے اس

کو حل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ  
 شمال سکیل سیکٹر ہے۔ کمپریزن کے  
 لئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر  
 ہم کہنیں دو سٹیٹس کولیں، ایک  
 جگہ پر لارج سکیل انڈسٹریز کافی ڈویلپ  
 ہوئی ہوں اور دوسری سٹیٹ جہاں  
 پر لارج سکیل سیکٹر انڈسٹریز کمپریٹیو  
 کم ڈویلپ ہوئی ہوں۔ شمال سکیل  
 سیکٹر انڈسٹریز زیادہ ڈویلپ ہوئی ہوں،  
 تو معلوم کیا جا سکتا ہے آسانی سے  
 کہ وہ سٹیٹ جہاں پر لارج سکیل  
 انڈسٹریز کا ڈویلپمنٹ زیادہ ہوا ہے وہ  
 پچھڑی ہوئی ہے نسبتاً اس سٹیٹ کے  
 جہاں پر شمال سکیل سیکٹر انڈسٹریز  
 زیادہ ڈویلپ ہوئی ہیں۔ وہاں پر  
 ایمپلائمنٹ زیادہ پیدا ہوا ہے اور  
 زیادہ خوشحالی آئی ہے۔

اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ  
 ہم لوگ اس بات سے کوئی بہت زیادہ  
 مطمئن نہیں ہیں طور اس سیکٹر کو  
 زیادہ تیزی سے بڑھانا چاہتے ہیں۔  
 لیکن ہماری لیمیشنز ہیں اور جو توجہ  
 اس سدن کے مانتیہ سدسیوں نے شمال  
 سکیل سیکٹر کو طرف دکھائی ہے اس  
 کے بھروسے پر میں فخر کے ساتھ کہہ  
 سکتا ہوں کہ شمال سکیل انڈسٹریل  
 سیکٹر کے بڑھانے کو کوئی نہیں روک  
 سکے گا اور یہ ترقی کرے گا۔

اٹادھیکش جی، بیکورڈ ایریا کا  
 ڈویلپمنٹ ہماری بہت بڑی پرابلم

ہے۔ بیکورڈ ایریاز اور بیکورڈ ڈسٹرکٹس  
 کے بارے میں بہت سے ممبران نے  
 تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بیکورڈ  
 ایریاز کو ڈکلیئر کرنے میں کوئی  
 ڈسکریمنیشن کیا گیا ہے۔ لیکن بیکورڈ  
 ایریاز اور ڈسٹرکٹس کو سٹیٹ گورنمنٹ  
 کے کنسلیشن سے پلاننگ کمیشن مقرر  
 کرتا ہے۔ اس کے کچھ ممبرز ہیں۔  
 میں انکار نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ  
 کچھ ڈزرونگ ضلع جو بیکورڈ ہوں  
 چھوٹ گئے ہوں۔ لیکن بیکورڈ ضلعوں  
 کو طے کرنا پلاننگ کمیشن کا کام  
 ہے جو وہ سٹیٹ گورنمنٹ سے کنسلٹ  
 کر کے کرتا ہے۔ البتہ یہ ہمارا کام  
 ہے کہ جب بیکورڈ ڈسٹرکٹ ڈکلیئر ہو  
 جائے تو ہماری ساری توجہ اس کے  
 ڈویلپمنٹ کی طرف لگ جانی چاہئے۔  
 میں کوئی لمبے چوڑے دعوے نہیں  
 کرنا چاہتا، بیکورڈ ڈسٹرکٹس کا  
 ڈویلپمنٹ کوئی بہت آسان کام  
 نہیں ہے۔ آخر وجہ تلاش کرنی پڑے  
 گی، سب سے پہلے ہم کو ان  
 ڈسٹرکٹس اور ایریاز کے بیکورڈ ہونے  
 کی، پچھڑے رہ جانے کی وجہ کیا ہے،  
 یہ دیکھنا ہوگا۔

اب ملک کی اکانامی ڈویلپ کر رہی  
 ہے، انڈسٹریز بڑھ رہی ہیں تو  
 کچھ اعتراض رہ جائیں، بیکورڈ ایریاز  
 ڈویلپ نہ کر پائیں تو اس کی وجہ  
 ہمیں تلاش کرنی پڑے گی اور اس  
 وجہ کو تلاش کئے بغیر اس طرف ہمیں

[سری صبا الرحمان انصاری]

حتیٰ اٹسٹس بے کرنی چاہئے<sup>2</sup> نہیں کر سکتے ہیں۔ انٹرسٹرکچر کی کمی ہے، دوسرے برادر انٹریسور سب کا ہونا ہے، بسرے ٹمکیکل بوھاؤ کاہ ہوا ہے اور اسی طرح کے دوسرے اور بھی نہیں سے فیکٹر ہیں . . . . .  
سری مول حد 513 - بوکر ساہی  
کو پہلے بھک کرو۔

سری صبا الرحمان انصاری - ان حروں کو پہلے کرلیں اس کے بعد اس کو بھی کر لیں گے۔ وہ ساری حیرین ہیں۔ بہت آسان نہیں ہیں۔ اسی واسطے ہماری ساری بوجہ سکھ رہے انبار کے ڈولمنٹ کی طرف ہے اور اس کے لئے محلہ سم کے اسٹور ہم نے روپور کئے ہیں تاکہ اثر برسورر وہاں جا کر ان عام اسٹور کی وجہ سے انڈسٹری لگائیں اور وہاں کا انڈسٹریل ڈویلپمنٹ ہو۔

انڈسٹریل ڈویلپمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے۔ شمال سکول انڈسٹریل سکٹر ایک نئے موڑ پر آ گیا ہے۔ حوا اب ہمارا اپروچ شمال سکول انڈسٹری کے ڈویلپمنٹ کا رہا ہے اور اب نئے پانچ سالہ پلان میں جو ہے، دوہوں میں بہت فرق ہے۔ نئے پلان میں ہم حقیقی رور شمال سکول انڈسٹری کے اسٹنس پروگرام کے اوپر لگانا چاہتے ہیں اور یہ اب کہہ دیا جاتے ہیں کہ یہ اسٹنس انٹگریٹڈ اسٹنس ہو۔

منسٹر انچارج کی حثیت سے مجھے مختلف صوبوں میں جانے کا موقع ملا ہے اور میں نے پایا ہے کہ شمال سکول انڈسٹری کے ڈولمنٹ کے سلسلے میں انک بہت بڑی ناکاہا یہ نبی ہے کہ انٹگریٹڈ اسٹنس ہم انٹریسورر کو نہیں دے سکتے ہیں اور محلہ جو اسٹی ٹیوسر جو لگی ہوئی ہیں شمال سکول انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے سلسلے میں ان کے بچ کوارڈننس کی کمی ہے۔ ہمارا رور اب اس باب پر ہے کہ ہم شمال سکول انٹریسورر کو انٹگریٹڈ امداد دینے سے محروم کرنا اور ٹرنڈ کے سلسلے میں ٹرنڈ اوپنٹی کے سلسلے میں، ٹمکیکل سرور اور مسٹری کے سلسلے میں اور ڈومسٹک اور انکسپورٹ مارنٹ کے امکانات کو معلوم کرنے کے سلسلے میں یہ پانچوں پلان ہمارا انک سداہا اپروچ ہے۔ ساتھ ساتھ جو ڈورنٹ اسٹی ٹیوسر شمال سکول انڈسٹریل سکٹر میں لگی ہوئی ہیں ان کے بچ ہم کوارڈننس چاہتے ہیں تاکہ سب مل کر ڈویلپمنٹ کے کام کو آگے بڑھانے میں ایک ساتھ آگے چل سکیں۔

ایک اور اپروچ پانچوں پلان میں ہمارا اس سلسلے میں ہے۔ اب تک جو شمال سکول انڈسٹری کے ڈولمنٹ کا طریقہ رہا ہے وہ نہ رہا ہے کہ ہم کوئی ٹیکنو اکا نامک سروے



پہلے سے کسی سکورڈ ایریا کا نہیں کروایا۔ وہاں پر لوکلٹی اوپنل را مشنریل یا انڈیجیس را میٹریل جو ہے اس کی طرف ہماری بوجہ نہیں گئی اور سیکریس را مشنریل استعمال کرنے والے نوٹس کو رجسٹر کر کے ہم نے سمجھا کہ ہم اس طرح سے ان انڈسٹریز کو سٹ اپ کر کے ان کو بڑھاوا دے سکے ہیں۔ سری رائے نے ہے کہ سماں سکمل انڈسٹریل سکٹر میں حولو لی اوپنل را مشنریل ہے۔ سری راجندو سنگھ (ہونور) : مرا

انک ووٹیا ڈ پریس ہے۔ سری مہوڑے نے کہا ہے کہ سکورڈ ایریا میں را مشنریل لوٹی اوپنل ہے نا نہیں اس کی حاجت نہیں لڑائی گئی۔ میں اسکو صاف کر دنا چاہتا ہوں۔ کہ سکورڈ ایریا کے لئے انک پٹل سڈی ٹیم اپائنٹ ہوئی تھی اور اس نے سانا تھا کہ نوں کون سا را مشنریل کہاں کہاں ہے۔

سری صیالرحمان انصاری - یہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ نہیں ہوا ہے۔ میں عرض نہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا جو میں بھرسٹ ہے جو ہم دے رہے ہیں پانچویں پلان میں وہ دے رہے ہیں لوکلٹی اوپنل را میٹریل کے اوپر، اس کے ایکسپلائٹیشن کے اوپر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لئے۔

SHRI PARIPOORNANAND PAINULI Based on the locally available raw materials, I want to know, whether you would establish the industries here or you would export them outside

سری صیالرحمان انصاری - ہماری محسوری نہ ہے کہ ہم ایٹروپروٹور کو کسی خاص حکمہ ڈالکر ان کو آکا نہیں سکتے ہیں۔ ایٹروپروٹور ہم کو پیدا کرنے ہونگے مقامی طور پر اور اگر مقامی طور پر اوپنل نہیں ہے تو پورا ہندوستان ایک ملک ہے اور اگر ناہر کے ایٹروپروٹور آکر وہاں کے لوکل را مشنریل کو انکسپلائٹ کر کے انڈسٹری سٹ اپ کرنا چاہئے ہیں تو وہ کر سکتے۔ اگر اب نہ چاہئے ہیں کہ ہم اس ایٹروپروٹور کو تو نہ ہمارے میں کی بات نہیں ہے۔

ناجوعے پلان میں ہم اس میں آئی سی کی نئی برانچر کھوسا چاہئے ہیں اور سٹیلارڈ سروسز ڈ پریٹرووسس کرنا چاہئے ہیں اور فارسٹ سٹڈ انڈسٹری کے لئے ایسی لری ڈولپمنٹ کے سے دو ہزار نئے نوٹس ایکٹرائسکل کے سے ڈولنا چاہئے ہیں۔ نہ ہمارا ہے پلان میں انک میں بھرسٹ ہے۔

ان اس ائی سی کے بارے میں سکابٹ ہوئی ہے۔ نہ انک اسٹا کارپوریشن ہے جو بڑی ویلوانل حدت انجام دے رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے ورکنگ میں دفس اور نرستانان محسوس کی گئی جس کی وجہ سے انک کمٹی اپائنٹ ہوئی اور اس کمٹی کی رکوڈسٹر مسٹری کے رپر سور ہیں اور ان کی روسی میں ہم لچہ اس کا سٹرم لائن کرنا چاہئے ہیں۔ اس کے

[شری ضا الرحمان انصاری]

ورکنگ کا، اس کے طریقوں کا اور مینلی نیشنل سمال سکیل انڈسٹریز کا جہاں تک ہائر رجنز کا تعلق ہے ہم چاہتے ہیں کہ سٹس کے لئے ریٹائنس اسٹی۔ ٹیوشن کے طور پر کام کرے۔ اس کو ہم سٹیج میں کریں گے۔ فرسٹ سٹیج میں ایک لاکھ تک ریٹائنس اسٹی۔ ٹیوشن کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں آئی سی ورک کرے۔ ایک لاکھ سے اوپر ہائر پریجس منسری کے لئے وہ خود کریں گے۔ لیکن سیکنڈ سٹیج میں ہم سارا کام سٹٹ گونڈنیمس کے ذریعے سے، یا سٹیٹس کے اسٹی۔ ٹیوسر کے ذریعے سے کرانا چاہتے ہیں۔ ہم وں میں کمیٹی کے اس پرابول کو کسٹڈر کر رہے ہیں کہ اس میں آئی سی ریٹائنس اسٹی ٹیوشن کے طور پر کام کرے۔

کچھ کھادی اینڈ ویلج انڈسٹریز کمپس کی ایکٹیویٹی کا بھی تذکرہ آتا۔ اس کمپس کی ایکٹیویٹی کوئی محض صنعتی، ادیوگک، ایکٹیویٹی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہمارا سوشل اب لمٹ کا پروگرام اور ایک فلاسفی جڑی ہوئی ہے کہ کس طرح عام لوگ گھر میں تھوڑا بہت کام کر کے ملک کی ضروریوں کو پورا کر سکتے ہیں، گاؤں کی لوکل ضروریوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کھادی اینڈ گرام ادیوگ کمیشن

نے کامی کام کیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جب کھادی اینڈ گرام ادیوگ کمیشن اس کام کو مختلف انسٹی ٹیوشنز کے ذریعے سے کرے گا۔ وہ ایک بڑا ڈی سینٹریلائزڈ سیکٹر ہے، اس میں کچھ انہریٹ ڈیفیکٹس ہونگے، اس سے اس انکار نہیں کرتا ہوں۔ اس بات کی مسلسل کونسل کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ان ڈیفیکٹس کو دور کیا جائے۔

جہاں تک اس میں پراڈکشن بڑھانے اور موڈرنائزیشن لانے کا سوال ہے ہم کھادی کے سلسلے میں ٹریڈیشنل جرج سے اسر جرج تک اور اسر جرج سے نو ماڈل جرج پر آئے ہیں۔ اس سے کھادی کا پراڈکشن بھی بڑھے گا اور اس میں جو لوسز لگے ہوئے ہیں ان کی ویجر میں بھی اضافہ ہوگا۔ لوک وستر کا ایک نیا پروگرام بھی ہمارے رپر عور ہے۔ کھادی اینڈ گرام ادیوگ کمپس نے پروگرام سایا ہے جو معمولی اسان جو کپڑا استعمال کرتا ہے اس کو کس طرح سے کھادی کے ذریعے سے سایا جا سکے، تاکہ وہ سسٹم اور لوگ اس کو لے سکیں۔ اس میں سپنگ سیکٹر میں کچھ حد تک پاور استعمال کر کے سستہ اور اچھا کپڑا بنانے کا ایک پروگرام انڈر کنسیدریشن ہے۔

کونٹر انڈسٹری کے سلسلے میں کچھ ممبروں نے بہت ہی نشوونما کا اظہار کیا ہے میکینائزیشن کے بارے

مس۔ اس نئے میں اپنا یہ وسیعہ سمجھتا ہوں کہ کوئر انڈسٹری کو مسکسائیر کرنے کے سلسلے میں گورنمنٹ کے رج کو صفائی کے ساتھ عرصہ کر دوں۔ گورنمنٹ کوئر انڈسٹری کو اس انداز سے اور اس حد تک مسکسائیر کرنے کے ہر گھر گرو میں نہیں ہے کہ اس سے ان ایمپلائمنٹ کی پرابلم ندا ہو جائے۔ گورنمنٹ کا وطعی طور پر نہ رح ہے کہ وہ اس حق میں نہیں ہے کہ ان ایمپلائمنٹ کی پرابلم ندا ہو۔ کمرل مس ۲۸۳ لوئلی مسریکنڈ مسرر، جن کے لئے لائسنس کی ضرورت نہیں تھی، ریٹنگ سکٹر میں حلے لگی نہیں اور اس سے کافی ان ایمپلائمنٹ ندا ہوا تھا۔ گورنمنٹ آف لبرل نے صحیح وقت پر دم اٹھا کر ان ۲۸۳ مسر نو، جسوں نے کافی لوگوں کو آوٹ آف ایمپلائمنٹ کر دنا تھا۔ ڈی آئی آر کے بعد اس کر دنا۔

ہم اس طرح کے مسکسائیریشن کے حق میں نہیں ہیں، جو ان ایمپلائمنٹ لائے والا ہے، جو لوگوں کی روزی چھینے اور ان کو نیگا اور بھوڑ کر دے۔ لیکن اگر اس موڈرنائزیشن ہو، نا اس حد تک موڈرنائزیشن ہو جس سے ہماری ایمپلائمنٹ ر لم اثر پڑے، لیکن ہم ایکسپورٹ کی اچھی مارکنٹ حاصل کر سکتے ہو ہم ہمیشہ اس کے حق میں رہیں۔

اس نئے اس سلسلے میں گورنمنٹ کی کوشش مسکسائیریشن کی ہالیسی ہے۔

۱۹۶۱ میں گورنمنٹ نے نہ طے کیا تھا کہ مسویکچرنگ سیکٹر میں کوئر انڈسٹری کی ایک بھائی برانڈکس کو میکسائیر کا جائے۔ یہی سے بن میکسائیرڈ یوشن مسو مسکچرنگ سیکٹر میں لئے تھے۔ ایک ہلک سیکٹر میں کوئر بورڈ کے بعد اور دو برانڈوٹ سیکٹر میں۔ اس کے علاوہ مسو مسکچرنگ سیکٹر میں یا سپنگ سیکٹر میں کوئی مدید مسکسائیریشن نہیں ہوا ہے۔

ایک آریبل مسو نے سرریکلر کے کے بارے میں کہا ہے۔ مس اس مصل میں نہیں جانا چاہا ہوں کہ کس طرح سے سلک بورڈ نے اور مختلف حکموں پر ہمارے جو سرریکلچر رسچ سٹیس ہیں انہوں نے کس طرح سرریکلچر انڈسٹری کو ڈولب کیا ہے۔ مس آ کے مادہ میں سے آل انڈنا سلک بورڈ کو سارک ناد دیا جہا ہوں اور اس میں کام کرنے والے رسچ آفسر اور ڈائریکٹر کو بھی سارک ناد دیا جہا ہوں کہ ہم نے کس طرح سے۔ مس نے خود اپنی آنکھوں سے لربانک سٹ مس دیکھا ہے۔ ملٹی ووٹین سے نائی ووٹین کی طرف سفل کیا ہے اور کس طرح سے وہاں کساں زیادہ سے زیادہ سلک پیدا کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔

[شری ضیا الرحمان انصاری]

سلک انڈسٹری کے سلسلے میں ایک اور مہتو پورن قدم زبر عور ہے۔ ابھی تک ہمارا زیادہ زور صرف ملبری سبڈ پر رہا ہے۔ ایک نیا پروگرام ہمارے انڈر کنسٹرکشن میں ہے کہ سبھالین ریجن میں اسام سے لے کر کسمر تک جو اوک پیدا ہوا ہے اس سے کس طرح اوک ٹرس ڈویلپ کیا جائے اور اگر اس کے لئے ضروری سمجھا جائے تو ایک اوک ٹرس ڈویلپمنٹ کارپوریشن کو وجود میں لایا جائے۔ دنیا میں ہڈوسٹان کے سلک کی مانگ کو دیکھتے ہوئے ہم کس طرح اس انڈسٹری کو ڈویلپ کر کے فارن ایکسچینج حاصل کر سکتے ہیں اس پر بھی زیادہ زور دیا جانا چاہئے۔

وف کی کمی کا احساس کرنے ہوئے حو بہت سی اس میں وسار کے ساتھ کہا جا رہا ہے مجھے افسوس ہے کہ میں نہیں کہہ سکا۔ میں معافی چاہتا ہوں ان 'ٹریبل مہرز سے جن کی کوئی بات وقت کی کمی کی وجہ سے چھوٹ گئی ہو۔ انہوں نے اس سیکٹر پر جو انڈسٹریل ڈولوپمنٹ کا نسبتاً ایک ویکر سیکٹر ہے جو توجہ کی ہے اس کے لئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ہر وقت ان سے گانڈینس لینا چاہتا ہوں اور ان کی اسسٹینس کے لئے اور ان کے خیالات کو حاصل کرنے کے لئے ان کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔]

SHRI H. M. PATEL (Dhandhuka) : I would like very much to understand the functions of the Industrial Development Ministry. The Report describes these, but one thing it does not make clear is what precisely is the role it plays in respect of basic utilisation, and facilities on which industrial development depends but which are not necessarily within its own control. What role, for instance, does it play in respect of shortages of steel, coal and power? What would the Ministry do to assist industries which cannot function without an adequate supply of power, steel, coal and a host of other raw materials? Does the Ministry of ID play the role of spokesman for all these industries which ought to be within its responsibility as against the other Ministries in the Government?

Today, for instance, I have received a telegram from Ahmedabad pointing to the large number of industries which will virtually come to a halt because of the failure to receive adequate coal or to the Ministry of Railways, one supply. I would presume it is the Ministry of ID which would take up this matter even before this difficulty actually arose. When we put a question to the Ministry responsible for coal or to the Ministry of Railways, one puts the blame on the other. But what we would very much like to know is whether the Minister of Industrial Development takes up the cudgels on behalf of these industries well in advance almost as if the industries themselves were putting forward their case and press upon those Ministries, upon Government, for an adequate and satisfactory planning for this purpose. May be—it is possible—he is doing it, but I see no mention of the fact that he is to regard this as one of his most important responsibilities.

Take another point, for instance. There is the question of the increase in the price of naphtha in regard to which an announcement was made day before yesterday. Only a few few weeks earlier...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Decrease.

SHRI H M PATEL. No Only a few weeks earlier, the price of naphtha had been raised from Rs 446 to Rs 2000 It was decreased from Rs 2000 to Rs 1,000 But the fact remains that the increase is of the order of 250 per cent or more This may be necessary, may be unavoidable from certain points of view But the point of view from which the Minister of ID, I presume, would have taken it up is what its effect would be on the production of other industries dependent on these supplies what effect it would have on their markets, what effect it would have on the price level For instance, one of the inevitable consequences of this would be that the consumer would be paying instead of Rs 9 for a plastic Bucket Rs 21 in future What would be the effect of that? When you are already fighting inflation, when this becomes an inevitable consequence, the inflation would become from whatever it is today a runaway inflation I would expect therefore that the Minister of Industrial Development should fight the battle within the Cabinet and Government for these industries I hope he is doing it

I would then ask him a question regarding the cement industry The report merely refers to the fact of its installed capacity, what it is actually producing and what is the intended increase of its capacity and so forth But what I would like to know is, why is it that the Government has been following a stop go policy A couple of years ago the cement production was more than enough for the requirements of this country, and indeed, there was something left over for export And then all of a sudden, there is a stop on expansion Now again after creating a shortage—and today the shortage is quite serious—the signal has been given to go ahead How does it help either the industrial development or the economy of the country?

I notice that the report refers with considerable satisfaction to the fact that they have streamlined the procedure for sanctioning industrial approvals I

would like very much to know whether, having established a procedure, it is in fact resulting in speeding up the sanctioning of industrial approvals. I know not only in regard to this but in regard to other matters also, that the Ministry of Industrial Development is not particularly expeditious in replying to references made to it I know of one reference in respect of a request for the establishment of an industry for the extraction of oil from cotton seed, about which I wrote to the Minister myself. I wrote to him only because the industrial unit concerned was not able to get a reply for several months, and to this day I have not received a reply The industrial unit may go ahead because it falls within the medium scale group, where it can do so It has, I hope, gone ahead and I am quite convinced that if it has done so it will have done so partly without fulfilling the necessary pre-requisite conditions Why does the Ministry force an industrial unit which wants to act correctly to act somewhat not so correctly? I suggest the Ministry while it is rightly interested in streamlining the procedures should also see that having streamlined the procedures in that respect and in certain other respects—undoubtedly they are very praiseworthy efforts and praiseworthy actions—they should also be implemented and enforced and all this should result in expeditious action Streamlining is for a specific purpose, it is not for itself Therefore, that is something which I hope he will be looking into

Another thing which I noticed with some interest is the fact that a Commission of Inquiry had been appointed to go into the question of large industrial houses This Commission is known, I think, as the Sarkar Commission The report says

“A Commission of Inquiry on Large Industrial Houses consisting of former Chief Justice of India, Shri A K Sarkar, was appointed on the 18th of February, 1970 to inquire into instances of irregularities, lapses or improprieties referred to in

[Shri H. M. Patil]

the Report of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee. The Commission was required to submit its report by February 2, 1971. The term of the Commission has been extended up to 17th February, 1975..."

There is no explanation to say why the Commission has failed to submit its report by February 2, 1971. Thereafter, it seems to have dawned upon the Ministry that the work of this Commission would take four more years. Is it so certain that even by 1975 the report would be forthcoming? If this inquiry was likely to take such a long time, why was it not even realised or envisaged right at the outset? I think these are pertinent questions in respect of an inquiry of some importance.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, this Ministry comes under attack from different corners every time. Especially, Sir, the vested interests and the monopoly houses always make this Ministry a target of attack by saying that production has come down. They also say that production is not increasing, because the Ministry is not issuing licences properly. Sir, to an extent, they create a climate in the country and put pressures on the Government. Their only slogan is, production. Then, Sir, I would like to ask...

SHRI B. V. NAIK (Kanara) : It is not a slogan. It is a purpose.

SHRI VAYALAR RAVI : He is one among them.

SHRI B. V. NAIK : I am one among you, unless you are going to disown me.

SHRI VAYALAR RAVI : My simple question is this. Production for what and by whom? This is the only question I would like to ask. Sir, if you take production of Vanaspati and other food items, which are essential for the urban population, you will see that production in these fields is completely controlled by the private entrepreneurs.

SHRI PILOO MODY (Godhra) : 75 houses.

SHRI VAYALAR RAVI : Not at all.

Naturally, it is a question of policy, whether the Government will allow these monopoly houses as well as the multi-national corporations to expand and influence the whole economic and political life of this country. The experience of Latin American, African and other developing countries is,—this is true even today—these multi-national corporations which have been operating in these countries have always collaborated with the national vested interests, made political capital and they even tried to topple the democratic institutions of those countries. It is a fact. Nobody can deny this. In Santiago, where the UNCTAD Conference was held, the late President Allende suggested the setting up of a commission to go into the working of the multi-national corporations. In fact, India had the privilege of becoming the Chairman of this Commission. Now, the question is, are we playing the role that is expected of us? Are we doing our duty in that respect? Are we fulfilling the expectations of the developing nations? What is the purpose of setting up such a commission? It is only to prevent these multi-national corporations, operating through different international agencies, and big capitalists, from influencing the political and economic life and thereby topple—I repeat—the democratic institutions of those countries. My only appeal to the hon. Minister is, he should consider this fact and he should take into account the feelings of other developing nations in regard to these multi-national corporations. He should be careful while giving whatever little preference to these multi-national corporations.

Sir, the slogan of production has gone only to help the monopoly houses to expand more. I definitely agree that small-scale and local entrepreneurs should come up and invest more. But, unfortunately, this is not happening. In

the name of production, all these big houses are given financial assistance by the public financial institutions. Sir, on the floor of this House, the hon. Minister himself has admitted that bulk of financial assistance from Industrial Development Bank and other financial institutions, banks and even LIC, has gone to the big houses. If the Government are to finance all these big houses, then, the only simple question is, what is the purpose of these monopoly houses? They will collaborate with the vested interests and they will always try to create chaos in the country. I repeat that more and more entrepreneurs should come into the field. In this connection, I would like to ask the Minister, what is the purpose of DGTD? The Minister himself admits that it functions only in an advisory capacity. He wants to do something. I have no complaints against him. He is very eager that more industries should come up in the country. There is pressure from unemployed youth for more employment. The monopoly houses have no complaint against the functioning of the DGTD because DGTD is functioning more to protect the interest of the monopoly houses and prevent the smaller entrepreneurs from coming up. Naturally when they form an advisory committee and give a technical report, even the minister's hands are tied and he says, "This is the report of the advisory committee." When the reports of the Planning Commission and other ministries are there, what is the purpose of this advisory report? They are not even technocrats. They merely serve the purpose of the monopoly houses. So, I submit that the minister himself should process it, without depending upon this advisory report.

I had some complaints against the Small Industries Development Corporation earlier, but not now. Fortunately the Government got rid of the gentleman who was there for a long time and the minister himself took more interest in improving its functioning. But there is one point. There was a conference in Kerala in 1968. There was

a big programme for giving machinery and small industrialists deposited their hard-earned money. But unfortunately they could not get the machinery nor their money back. The complaints are still there and I request the minister to look into this.

Coming to the establishment of a paper corporation in Kerala, NIDC were appointed technical advisers in collaboration with Siemens. But it seems the collaborators have backed out now and it has created a big problem. I raised this matter in the House earlier and the minister took some initiative and assured the House that the paper corporation will be established in 1976. Even though this difficulty has cropped up now, I request the minister to see that necessary steps should be taken to commission this plant in 1976 itself.

The employees of the HPC have an apprehension that the corporation may be shifted to Calcutta. I request the minister not to put more hardship on the people working in Delhi by shifting the office to Calcutta.

Coir and khadi have been mentioned. Coir is a subject about which only people from Kerala can speak. Coir industry is giving rural employment and the bulk of the rural population are earning their livelihood through this. Their wage is the lowest—Rs. 1½ or 2. Yet, we could not provide proper employment to them because of certain difficulties. Even though the exports have gone up in terms of money because of higher prices, in terms of quantity the exports have come down from 51 to 49 lakh tonnes. It means production has gone down resulting in lesser employment opportunities. That is why the Kerala Government made a proposal for restructuring the industry. It has been admitted here and I quote :

"The Government of Kerala initiated implementation of special schemes for the re-structuring of the coir industry."

[Shri Vayalar Ravi]

I know the hon. Ministry is very much interested in improving the coir industry. I would like to know from him what he proposes to do and how he is going to help the Kerala Government.

SHRI C. SUBRAMANIAM : We would like to know it from you.

SHRI VAYALAR RAVI : Our demand is that you should give at least Rs. 15 crores in a phased manner for the restructuring of the coir industry.

SHRI C. SUBRAMANIAM : It is not money that is the problem, but it is something else.

SHRI VAYALAR RAVI : If money is not the problem, I would be very happy. Definitely we can help the Minister to sort out the other problem. The Kerala Minister said that even though the Planning Commission promised about Rs. 45 crores, the provision this year is only Rs. 1.5 crores, whereas we expected at least Rs. 3.5 crores. Since the Minister says that money is not a problem, I hope he will look into this because it concerns my constituency also.

Lastly, I come to the Khadi and Village Industries Commission where a lot of employees are working. There are no rules or regulations for appointment transfer and promotion and they are done mostly on the basis of favouritism or patronage. I hope the Minister will go into this.

Finally, I would say that our industrial policy should be based on socialist outlook and there should be no departure from that policy.

SHRI D. D. DESAI (Kaira) : Sir, while supporting the grants, I would like to offer few constructive suggestions to the industries Minister. The industrial sector has been slipping badly during recent years. It has about 9.3 per cent growth in the early sixties and we maintained it for six years. From 1966 onwards we are on downward grade. Last year we had almost nil and this year

I would not be surprised if we end with a minus figure. But I am not interested in the figure part of it; I am more interested in seeing that the industries do pick up at the earliest opportunity, because the extent of disorder or discontent that is prevailing in the country is rather upsetting for any thinking person. We have to go back to the last decade and see what are the policies which had brought us to the present state of stagnation and also inflation in fact, if we are putting it collectively, stagflation resulting in huge unemployment. This is an explosive matter.

Individual items have been taken care by most of our friends. So, I would rather concentrate on the policy part of it. By calling a country democratic, it does not become democratic; by calling a country socialist, it does not become rich. In that way, we are a poor man by name Dhannal he does not become rich. In that way, we are only deluding ourselves. There are today countries in the world which have a very high standard of democracy, human freedom and liberty, a definite amount of highest development and highest social benefits and socialism that we are aspiring for.

Here, I would like to quote from a recent book on Sweden some of the information which is no different from our economic policy goals :

"The central goals in the management of the Swedish economy are: rapid economic growth, high and stable employment, reasonable price stability, a more even distribution of income and regional balance."

There have been the things that we have been talking about. Is this country or these people of Sweden really socialist or not? As for the amount of money that the Swedish Government and that country spend on development and social activities, I think, there is no equal in the whole of the world. Their *per capita* income is the highest in Europe; the wages are the highest in Europe; the strikes are the least; the



man-hours lost are the lowest. In each respect, the Swedish economy has done so well. Why should we not have some sort of examination, if necessary, on the lines of what Sweden is doing? We are today pursuing the examination and collaborations with so many other countries. Why don't we also find out how best we could make use of the technology, the know-how, that Sweden has developed for socialism and democracy?

There is another thing which inhibits our growth. One of the main reasons stated has been the labour problem. The labour problem is the root of it. Of course, the labour has reasons to feel dissatisfied. One of the reasons for their dissatisfaction is inflation because the wages that they receive become low. In other words, in real terms of value, the money is losing significance. This is one of the effects of scarcity and inflationary condition.

In Sweden, they have certain labour laws and, generally, the people are under the impression that labour disputes must have been left to themselves as elsewhere and they must be creating a chaos in the society. Sweden has an elaborate system of avoiding labour disputes. I quote :

"The law provides facilities for negotiations. If preliminary negotiations fail, the employees are not allowed to strike until they have officially given a week's notice. This week is spent in efforts to avert conflict and, at this stage, negotiations are led by a Government appointed mediator or a group of mediators.

The right to resort to conflict measures is subject to certain limitations by law."

This is something which might interest our friends. We have uninhibited right to strike. We know the present problem of Railway, coal and steel. Steel production which was in 1965-66 is not matched in 1973-74. This is something which is unheard of with such huge investments in important

core sector of the country. The same thing is about coal. There is stagnation in production. There are transport bottle-necks in the movement of articles. There is the problem of power. We have put in large sums of money. We are told that a large amount of generating equipment are lying idle for want of maintenance, for want of coal, for want of this and that. This is an unfortunate situation which we have to resolve if we have to avoid unprecedented unrest which, I am afraid, has hurt us badly and we may all be the victims of the situation.

The fiscal and credit policies also require a certain amount of change. We have seen that taxation does not leave money for investment. We have seen that if at any time the development rebate is required by the country it is this time because we are short of new entrepreneurship, we are short of goods, services and so on.

15 HRS.

[SHRI NAWAL KISHORE SINHA in the Chair.]

We have already got sick units and the way in which we are maintaining sick units is quite interesting. For example, we are quite proud of certain sick textile mills making profits.

These sick textile mills obtain from fine and superfine mills a certain lump sum amount per metre of coarse cloth quota. They are expected to manufacture coarse cloth of efficient mills quota which the cooperatives and others are disposing of after little process in the open market and are making around Rs. 40 to 50 crores. This is what is going on. I do not want to go into the details. I only want to point out that this mechanism is going to hurt the economy of the country.

The licensing procedure has been considerably changed. I would like to say that the licensing policy also requires certain modifications to the extent that we should not be carried away merely by dogmas but want to achieve a cer-

[Shri D. D. Desai]

tain development in the country. It is said: let the cow be fattened and then milk it and do not butcher it. That is one way of looking at it. If we butcher it, we have it only for one day, but if we fatten it and milk it, it is there for all the time. The industry can give income to the State. As some economists have said, ten to twelve per cent growth is good enough to give the State Rs. 1,000 crores of additional income annually. This is how we should look at it. This is not something which is not possible in the country. The demand for goods is there; the talents are there; everything that we can hope for is there. I am not saying this just by way of criticism only; I am saying out of the sincere feeling that we have to set right our house; and earlier we do, the better—before it is too late.

We have been talking about unemployment is there. I would estimate that we have to create one crore additional jobs. One cannot get a good salary with the per capita investment of Rs. 10,000, i.e., one job for the capital investment of Rs. 10,000. That means, to create one crore additional jobs, there should be investment of Rs. 10,000 crores. Where have we got the money? From where is it going to come? Therefore, I would suggest strongly that we have to go in for handicrafts. That is an area where we need only a limited investment and improvised tools; people are used to handicrafts; the cost of dislocation and the cost of re-location is to the barest minimum; and it can generate employment opportunities and can produce consumer goods. If we have to create one crore additional jobs, we must somehow or other provide as much training as possible for undertaking handicrafts in villages. You may call it a Gandhian policy. After all, ours is a large and a poor country, with practically not much of exchange resources or capital; ours is a capital-hungry country. Even if we provide huge plants, how much employment are they generating? Our experience has been that it creates more tensions between the employed and the

unemployed, it creates social tensions, it has dislocation problems and so on and so forth.

Now I come to agro-industries. Our entire economy picked up during the late Sixties. The reason was good agricultural production. We had the growth rate of 7.9 per cent or about 8 per cent principally due to agro-industries. But, unfortunately, I find from the planning Commission's report that the provision for agriculture has been very limited. If the provision for inputs for agriculture is also reduced, then we will have a poor performance on the agricultural front, and with the present day economy of the world and the shortage in agricultural production in the world, we cannot look anywhere for our requirements; we cannot do without them.

With these words, I support the Demands for Grants in respect of the Ministry of Industrial Development and the Department of Science and Technology.

**SHRI DHAMANKAR (Bhiwandi) :** I rise to support the Demands of the Ministry of Industrial Development and Science and Technology.

If you go through the reports of the Department of Science & Technology for 1971-72 you will be proud to know that our scientists have done a very good and commendable job. Various researches have been made and they have been commercialised and brought into operation. Various laboratories—Chemical laboratories, physical laboratories, metallurgical laboratories, fuel research laboratories, rubber laboratories—all these laboratories are doing a splendid work and they are helping the industrial growth of this country. But the financial provision for Science and Technology, I find, is rather meager and I would request the hon Minister to review it and increase the allotments for this vital Department.

Yesterday some of the friends opposite were agitated and said that the

Minister revised and liberalised the licensing policy and shamelessly given opportunity to the monopolists to exploit it. That is not the correct position. We have to revise and liberalise the licensing policy wherever called for. Of course, the monopolists should be curbed. They should not be allowed to use all the profits for themselves. All the capital with the monopolists or with the public sector or the private sector must be utilised to increase the production in the country. Even the foreign capital that is here now should be utilised fully. I can understand if you would not allow any more foreign capital and domination in this country, but those who have already invested, their capital we must utilise. To day only in the Press it has appeared that Hindustan Lever, a company with major foreign shares, has been issued a licence to manufacture STPP. While doing so, the MRTP has laid down certain conditions, that more capital will be issued exclusively to Indians and no more foreign share-holders will be given any opportunity to join in this and secondly 20% of the production will be reserved for export and thirdly, the output will be utilised for not only themselves but for other people also who are manufacturing detergents. We have to save edible oil and so encourage the use of detergent in the country. In the circumstances, all the capital in the country, whether private or public or even the foreign capital that is here in the country, must be utilised to the fullest extent and we must increase the production in the country. Unless we do this, it is very difficult for us to survive as a free nation.

The licensing policy in the case of cement should have been revised earlier because it is such a heavy industry that it is not possible to attract people to make investment as its capital requirement is very large and the returns are rather low. So, only big capitalists will come in. And the public sector cement factories should be increased. But the shortage of cement could have been compensated if the licensing policy had been reviewed and revised earlier as

also by issuing more licences or permitting expansion of the existing units and I hope this will be reviewed now.

Then I come to the salt industry. There are two public sector salt firms—the Hindustan Salts and Sambhar Salts. They are doing very well and are making very high profits. We should be very proud of them and we commend their performance to the other public sector concerns. Along with that, I would request that the small salt pans should also be encouraged. In the co-operative sector a big unit has come up in Palghar. The Maharashtra Co-operative Fertiliser Society has come up. Various societies have joined and started a very big salt manufacturing concern. Some thousands of acres of land have been allotted to them. This salt can be utilised to manufacture ammonium chloride from sodium chloride and this can be used as a fertiliser. One more point. You will have to review the position of the Shilotris or the small salt pan owners. They own salt pans but after their death their children are not allowed to inherit them. I don't know how this can be done. Even as per the Land Legislation after the death of a father the son inherit the lands. So, this should be looked into. I would request the Minister to review this position and remove the difficulties of the small salt pan manufacturers. At Bhayandar and round about, salt pan manufacturers have to go to Bassein to get clearance passes of permits for the disposal of salt. This causes great difficulty. This should be looked into and their difficulties must be removed.

Now, regarding the rubber industry, raw rubbish is just enough to meet our requirements of rubber manufacturers. There was a slump last year and rubber was allowed to be exported but this year the position is reversed. Now we are short of rubber because synthetic rubber production has come down considerably. From 30,000 tonnes it has come down to 20,000 tonnes. In respect of natural rubber if you allow exports like this, I

[Shri Dhamankar]

think a situation will come when we will be forced to import rubber from outside from other countries. This should be avoided and to avoid this, I request the hon. Minister to review the position and see to it that export of rubber is restricted.

The National Textile Corporation is doing commendable work. That is managed by the Industrial Development Department. The textile mills and the decentralised sector, that is, handlooms and powerlooms are with the Commerce Ministry. I feel that this position should be reviewed. The Textile mills and the decentralised sector of powerlooms and handlooms should go under the purview of the Industrial Development Department and not under the Commerce Ministry. I say this because Commerce Ministry is concerned with internal trade and foreign trade which is their main work. They are not concerned with industry and therefore I feel that this should be examined.

The definition with regard to small-scale industry stipulates that its capital limit would be 7.5 lakhs. This has been increased to some extent now but still I feel that it is very low and it should be reviewed again. The value of rupee has gone down. One lakh of rupees of licence will now fetch goods worth only Rs.25,000, because the value of the rupee has gone down. So, I request that this position should be reviewed and this amount should be increased.

My last point is regarding the Khadi and Gramodhyog Commission. The management of the Khadi and Gramodhyog Bhavans should be examined. If you go to their shops they are not prepared to go and show you the things inside. They simply sit in the chair showing utter disregard to the customers. It has become their monopoly and they behave as monopolists. They must learn how to treat the customers. If you go to a private shop you will find that they go inside and show you so many things and they persuade you to buy. But here you find that

these people show utter disregard to the customers. So, this should be reviewed. This is my respectful submission. With this I have done.

SHRI C. M. STEPHEN (Muvatupzha) : Sir, I am told, the time allotted to each Member from these benches is drastically cut.

Therefore, Sir, I am not able to traverse the whole ground which I had contemplated to do. To my great relief Professor Dhamankar who preceded me has materially covered the grounds which I too wanted to emphasise with respect to the small-scale industries there is only one point which, due to the constraints of time, I particularly want to emphasise

The hon. Minister himself, in his speech, underlined the importance of small-scale sectors in the conditions of economy obtaining in this country.

It will be observed that there are two vital problems that we have to face— one is the rise in prices and the other is the rise in the rate of unemployment. If these two problems are not tackled, no solution will bring about stability either political or economic.

Looking forward, the position is rather dismal. The year we are facing happens to be under a synchronistic circumstance, the first year of the Fifth Five Year Plan. The current year is the taking-off stage for the Plan. The review before us, reports that the year just past has recorded zero growth. It is not able to promise that the position would be better. The Ministry's report says that the circumstances are such that they cannot promise that tomorrow is going to be better than yesterday.

The unemployment problem is rather too frightening. The Fifth Five Year Plan emphasises that an estimated addition to labour force is about 65 million. This alone is more than three and half times the present level of employment in the entire organised sector, including both public and private sectors. In addition, there is the huge back-

log of unemployment, underemployment and thin (very low productivity) employment. These 65 million people is in addition to the carryover. So, the backlog is not being reduced. This is a very frightening picture indeed. My hon. friend, Shri D. D. Desai pointed out the strategy by which we can handle this. And the Fifth Five Year Plan is fairly clear about it. And this is what it says : I quote from the Fifth Five Year Plan the following :—

“From the data regarding the entire factory sector for 1968, the fixed capital per employee, on an average, in small scale industrial unit was as low as about Rs. 3,170, as compared to about Rs. 22,000 in a large scale unit. Moreover, while the small scale sector accounted for about 7.5 per cent of the total fixed capital investment in the factory sector, its share in the total output was as high as nearly 28 per cent. If account is also taken of small industries below the factory level including the household units, the share of the entire small industries' sector in total industrial output would be considerably larger”.

This is how they have contemplated. That being so, the question is : Is the policy sufficiently reflected or not ? The allotments made in the Fifth Five Year Plan are claimed to be more than double those allotted in the previous Plans. That makes no difference at all because taking into consideration the value of the rupee it cannot be said that it is more than double than of the previous Plan. It only means that *status quo* remains and no additional weightage is given to the small-scale sectors at all. The Report before us is certainly good intension, good evaluations and fond expectations. I do not say that the valuation made is bad. I want to ask : have we gone into the task with a real gusto ? Is there any mechanism by which we can expect that the Plan strategy will be implemented or it will be converted into practice. The Minister said that the entrepreneurs cannot be created. I would say that entrepreneurs

must be created. There is no other way. Supposing you do not. The public sectors flounder. Entrepreneurs do not come in. What is the result ? Unemployment will mount; production slumps; there will be price rise to the consternation of everybody. If you want smallscale sector to flourish, you should find them out; you should help them; there should be financial help given to them when they come forward with their project reports. They should be assisted in all possible ways.

Sir, the present position in the rural areas is this. Initiative is not taken by the entrepreneurs. Each area should be put in charge of somebody. The persons put in charge for doing a thing should be judged by their performance. They should take into consideration the prevailing circumstances in each area and should evolve schemes. They will have to find the entrepreneurs and there must be a linkage of the banking and financial assistance and also the technological skills. That way alone we can solve the problem. Now the Five Year Plan says that the major part of the unemployment problem will have to be solved from the agricultural sector. We know how far that is possible. If that is not possible what is going to happen ? There will be migration to cities and in the cities there will be no solution. Socio-economic tension will develop and there will be complete breakdown. Therefore, I would appeal. let us go back to the Old Man, the Father of the Nation, who emphasised that the solution to the economic problems in this country is village industries and the small scale industries. Advertising to another point, Shri Vayalar Ravi was emphasising about monopoly. Attack on monopoly has become a fashion. Nobody is there to support the monopoly. But the question is how to develop production, how to bring more produce and how to give employment. That is the question. Let us not take negative attitude and let us not imbibe sadistic pleasure in taking negative slogans but rather put more positive emphasis.

Certainly there must be restrictions and bridles so that the national interest

[Shri C. M. Stephen]

is not in jeopardy. If the democracy which we are having is dynamic enough there is nothing to fear. But the need of the hour is higher production. That need has not been created by anybody nor is it an artificial one. That is a writing on the wall and the writing has to be taken note of and the challenge has to be answered. Therefore, there should be emphasis on production and employment. Let us go on to the small scale industries and with regard to the large-scale industry let us evolve a policy whereby the installed capacity which is available in this country does not lie idle even for an iota. Let us have a breakthrough on these two fronts, namely, production and unemployment. With these words I support the Demands of the Ministry.

**डा० कैलाश—(बम्बई वक्त्रण)** सभापति महोदय, मैं औद्योगिक विकास, विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय की मर्मों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

जहाँ तक साइंस और टेक्नोलोजी का संबंध है, उस की रिपोर्ट में कहा गया है, प्लानिंग कमीशन भी वही कहता है और पाँचवी पच-वर्षीय योजना बनाने समय भी यही कहा जाता है कि हम सैफ रिलायम प्राप्त करना चाहते हैं, और उस के लिये हमें साइंस और टेक्नोलोजी का पूरा सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि साइंस और टेक्नोलोजी के लिये प्लानिंग कमीशन ने कितनी रकम इंस मंत्रालय को दी है, तो झूठे लगता है कि वह रकम इतनी थोड़ी है उस से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा और हमारी फिजिकल लैबोरेटरीज और एन० सी० एस्० टी० शायद उत्तम काम नहीं कर लेने, जिस की हम उन से आशा करते हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि हमारे नैचुरल रीसोर्सिज से-फारेस्ट्री, वुडों अर्थात् वन-सम्पदा से और भूतर्भ में पड़े मिनरल्स और आयल और नैचुरल गैस से हमें जो आमदनी हो सकेगी, उस विषय

में एन० सी० एस्० टी० ने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया है। रिपोर्ट में कही यह नहीं बताया गया है कि एन० सी० एस्० टी० ने यह कार्य किया।

**सभापति महोदय** क्या माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि साइंस और टेक्नोलोजी में इंडिजनेस रिसर्च भी होनी चाहिये और केवल पश्चिम का अन्धानुकरण नहीं होना चाहिये।

**डा० कैलाश** आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम ने सिर्फ पश्चिम को एक आदर्श मान कर काम करना शुरू किया, तो शायद हम अपने तकनीकी विद्वानों को एक गलत रास्ते पर ले जायेंगे। इसी लिये मैं ने कहा है कि हमें वन-सम्पदा और मिनरल्स की तरफ ध्यान देना होगा। वह भी देश की परिस्थितियों तथा मांग को ध्यान में रख कर ही यह सब कुछ करना होगा।

जहाँ तक औद्योगिक विकास का संबंध है, हम देखते हैं कि हालांकि इस वर्ष अजिया ज्यादा आई है, सरकार ने लैटर्स आफ इन्डेंट भी ज्यादा दिये हैं और लाइसेंस भी ज्यादा दिये हैं, लेकिन ग्रोथ घटता जा रहा है—वह 1 परसेंट या जीरो परसेंट की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बिजली नहीं मिल रही है या, वर्कर्स के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं रहे हैं? एन० सी० एस्० टी० की यह भी जिम्मेदारी हो जाती है कि देश की फ्युअल और पत्थर की रेकॉम्पेन्सेन्स को कैंबे पूरा किया जाये, जिस से हमारा औद्योगिक निर्माण ठीक प्रकार हो सके।

मैं मंत्री महोदय ने रिसर्च और डेवेलपमेंट की एक नई कंपनय देण के सामने खड़ा है। रिसर्च और डेवेलपमेंट के नाम से एक अलग से महकमा शुरू किया गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय यह बतायें कि रिसर्च और डेवेलपमेंट से देश के कारखानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कितना फायदा जाय मिलेगा है।

पिछले कुछ समय से बल्गारिया, यू० एस० एस० आर०, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और हंगरी आदि देशों के साथ हमारे साइंटिफिक रिलेशनन्स स्थापित हुए हैं। ऐसे एग्जीमेन्ट पहले भी होते रहे हैं। अगर रिपोर्ट में उन के बारे में कुछ प्रकाश डाला जाता, तो अच्छा होता।

जहाँ तक औद्योगिक विकास का संबंध है, हमने आईरली डेवेलपमेंट आफ लार्ज, मीडियम एंड स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज की बात बही है। हमने डेवेलपमेंट आफ खादी एंड विल्लेज इंडस्ट्रीज, पब्लिक सैक्टर प्राइवेट सैक्टर और कोऑपरेटिव सैक्टर की बातें की हैं। लेकिन लार्ज सैक्टर के बारे में कुछ लोगों में एक अजीब सी धारणा बनती जा रही है। देश को स्माल-स्केल की ओर से जाने वाला जो भी व्यक्ति हो, अर्थात् जिसके पास रुपये और नोन्हाउ का उपयोग करने की शक्ति हो वह वह मोनोपली हाउस ही क्यों न हो उस को ऐसे क्षेत्र में कारखाना लगाने की इजाजत देनी ही चाहिये, जो भंग पिछड़ा हुआ है, तो उस पर भी अगर टीका-टिप्पणी की जाती है और कहा जाता है कि हम पैस वालों को और पैस वाले क्या इजाजत दी गई तो यह दुःख का विषय है।

हमने तो देखा है कि किस तरह देश में उद्योग धन का उत्पादन हो और किस तरह पिछड़े हुए क्षेत्र आगे बढ़ सकें। अगर हम किसी मोनोपली हाउस को कुछ बघनों के माध्यम, जिन का जित्त माननीय सभासद श्री देसाई और श्री स्टीकन ने भी किया है, एक इनसे-टीसाइडूज बनाते वाला कारखाना लगाने के लिये उस लक्ष्य को लाइसेंस दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि उसके विरुद्ध कोई गड़बड़ नहीं की जानी चाहिये।

लेकिन सरकार ने मीडियम स्केल और छोटी इंडस्ट्रीज के साथ बहुत अन्याय किया है। अभी हमारे मिनिस्टर माहब बहुत ही भावुकता से सचबोल रहे थे। इसने कोई शक नहीं है कि उनका दिम तड़प रहा है। लेकिन

उन पर कौन से बघन आ रहे हैं, वह समझ में नहीं आता है। रिपोर्ट बनती है, लेकिन वे ताले में बन्द पडी रहती हैं। नातो मीडियम स्केल के कारखाने बड़े नहीं छोटे कारखाने।

मिनिस्टर माहब ने चार्ज लेते ही कहा कि हम नब्बे दिन में लाइसेंस दे दिया करेगे लेकिन मेरी जानकारी है कि ऐसे लड़कों में, जो इजीनियरिंग पास कर के आये हैं अर्जी दी है, लेकिन तीन-तीन महीने तक उन के लाइसेंस का पता नहीं चलता है। उन की स्कीम की दोहरी छानवाई की जाती है। एक तो मन्त्रालय करता ही है और जब बैंक के पास जाते हैं, तो वहाँ पर छानवाई होती है जिन से उन को न पैसा मिलता है और न लाइसेंस। क्या मंत्री जो इम तरफ ध्यान देंगे ?

फिर यह सब कुछ तय हो जाने के बाद भी मीडियम इंडस्ट्रीज और स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज को लोहा और सीमेंट नहीं दिया जाता तो वे आगे नहीं बढ़ सकते। इस लिये सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि उन्हें लोहा, सीमेंट और बिजली ठीक समय पर मिल सके। जिन इजीनियर्स ने जमीन ले ली है, इलैक्ट्रिफिकेटी बोर्ड उन को बिजली नहीं दे रहे हैं। इस लिये जब तम मज डिपार्टमेंट्स में आपस में समन्वय नहीं होगा, तब तक इस औद्योगिक प्रगति नहीं हो सकेगी। सीमेंट कार्पोरेशन के बारे में मैंने आप के सामने अभी कहा है। बैंक ही हिंदुस्तान फोटो फिस्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी को चलने हुए कई वर्ष हो गये लेकिन इस का कोई आगे कदम नहीं बढ़ पाया क्यों कि शायद इस कारखाने की सारी पुरानी मशीनरी चली आ रही है। उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वह एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पब्लिक सैक्टर में होते हुए भी ठीक तरह से नहीं चल रही है। अगर बहू ठीक प्रकार से चले तो कोडब और अगफा को भी बहू हटा सकती है या वह हमारे सामने घुटने टेकने को मजबूर हो सकते हैं। हमारे फोटोग्राफर चाहते हैं कि उन्हें हिंदुस्तान

[डा० कैलाश]

फोटो-फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी का कागज मिले जिस को वह उपयोग में लायें लेकिन वह उन्हें नहीं मिलता और उन्हें कोडक और अगफा के पास ही जाना पड़ता है। इस के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड ने चार जगह पल्प और कागज बनाने के कारखाने खोलने का प्लान बनाया एक मन्ड्रया, दूसरा केराला पल्प ऐंड प्रोजेक्ट, तीसरा नागालैंड पल्प ऐंड पेपर प्रोजेक्ट और चौथा नौगांव पल्प ऐंड पेपर प्रोजेक्ट है। आज देश में वच्चों की पाठ्य-पुस्तकों के लिये कागज नहीं है और अखबार वालों के लिये कागज नहीं है तो मेरी समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड इस पर ध्यान क्यों नहीं देता? इस में कहां कठिनाई आ रही है उसे देखने की आवश्यकता है। मंत्री जी बताने की कृपा करें कि ये कारखाने शुरु किये जा सकेंगे?

खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में भी मेरा बड़ा बटु अनुभव रहा है। इतना बड़ा सेल है पर वहां जो बेचने वाले कर्मचारी हैं उन का कोई सहकार ग्राहकों को नहीं मिलता वह शायद इस घमंड में रहते हैं कि उन का सेल इतना ज्यादा है तो क्यों किसी की चिन्ता करें? मंत्री जी मंत्रालय खादी और विलेज इंडस्ट्रीज पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे है उन्हें देखना है कि खादी भवन और अन्य दुकानें किस प्रकार से चल रही हैं। अगर उस तरफ ध्यान दें तो अन्तर्प्रमोशन का सवाल भी हल हो सकता है और देश के आगे बढ़ने में भी उससे मदद मिल सकती है क्योंकि उस में एक्सपोर्ट पोटेन्शियल भी काफी है। इसलिये मैं चहूंगा कि मंत्री महोदय उस की ओर अवश्य ध्यान दें।

SHRI P. R. SHENOY (Udipi) :

Though the big industrialists have continued to amass wealth, industrial production in 1973 has gone down. The reasons given for the decline in produc-

tion are failure of the monsoon, shortage of power, transport bottlenecks in the movement of industrial inputs, steep rise in the prices of imported industrial raw materials such as crude oil, steel and non-ferrous metals and disturbed industrial relations. These are only some of the reasons. The reasons not disclosed by the Ministry in the Report are growing inefficiency in administration, faulty planning by the Planning Commission resulting in shortages of production of industrial inputs such as coal, pig iron, steel and cement and other essential items, non-implementation of physical targets fixed at the commencement of the Plan by the Planning Commission itself, inability to implement major projects within the prescribed time-limit, non-utilisation of capacities and irrational labour policies leading to strikes and other labour unrest.

It has been said that the licensing procedure has been simplified and licences are now issued quickly. Figures of disposal of letters of intent and licences are given in the report, but not those of pending applications in 1973. At the end of October 1973, the different applications for licenses pending with the different Ministries total 3,861. Of these, 1,692 were of 1972 and years prior to that. Therefore, unless information is collected by computer and unless some real reform is made in the licensing procedure, delay is bound to occur in the issue of letters of intent and licences.

Sir, when we formulate plans, we do not assess the actual requirements after a certain period. We simply add a certain percentage to the production in the field of every product, whether it is coal, or oilseeds or cement or steel or baby food. We simply say that it would be five per cent extra after five years or six per cent or seven per cent extra. We do not assess the real requirements after five years. Unless we make a real assessment, ultimately what we will produce will not be enough for the consumption of our people. In other words, we are not planning for



plenty but we are planning for shortages. This system should be changed while we formulate the plan.

Then again, we fix some physical targets while we formulate the plan and we also fix the financial targets, but at the end we only declare that we have reached our financial targets but we never fulfil our physical targets. This is especially so in the case of power plants. In many power plants we have declared that the installed capacity of the power plant is so much, but the real capacity is much lower than the installed capacity. In the case of major irrigation, the actual physical targets are much lower than the physical targets that are announced in the beginning.

Then the capacities of different plants are not fully utilised in our country. No doubt in the report it is said that utilisation has gone up, but what is the percentage of utilisation now? Have we reached at least 85 per cent of the capacity? We have not. In almost all the heavy industries also, as in the steel industry, for example, our utilisation is much below 85 per cent, and it is even below 75 per cent in fact. The utilisation of the capacity should be not less than 85 per cent, and we should achieve this as early as possible.

Then, we do not implement many projects within the time fixed. For instance, we have spent crores of rupees in the installation of the Vijayanagar steel plant, and I am sure at the present rate of construction this steel plant will not come up in the next 15 years. How much money we have wasted and how much interest we are losing on that? I do not think that even the steel plant proposed for Visakhapatnam will come up within the next 10 years, and as reported recently, even the small steel plant proposed for Salem will not also come up within the scheduled time. The construction of the Mangalore major harbour started in the year 1965, and even after about 10 years, it is not completed. They have spent more than Rs. 15 crores. What is the interest on this money? This

interest is wasted and the prices will go up as the construction of the project is delayed.

There must be a national wage policy if there should not be any strikes. We cannot stop strikes by magic. Unless the workers in this country are satisfied, they will continue to stage strikes. The only way of stopping the strikes is to have a national wage policy. At present, the wages are different at the Central level at the State level and at the public sector level. At different levels we are having different wages. So, unless we have a national wage policy, there will be unrest among the labourers.

Another point is, bonus should be related to profit. At present, it is not related to profit. According to the famous economist, Prof. Dandekar, if bonus is related to profit the workers will stand to gain. He has analysed the profits in major factories which are well run, and has shown that if bonus is related to profit, if the labour of a worker is treated as his contribution towards the capital for that particular year, and if he is also given bonus, as the shareholder is given, he stands to gain. The production in the factories will go up.

Sir, the National Textile Corporation is managing 103 sick mills, of which 92 are in operation. It is gratifying to note that most of these units are making profits, and the Corporation, as a whole, is also making profits. But, Sir, out of the 450 million metres of cloth produced by this Corporation, only about 20% is controlled cloth. The Corporation should produce fine cloth only for the purpose of export. The remaining should be controlled cloth. The Corporation should give a lead to other textile mills in the private sector in the matter of production of controlled cloth. Sir, it is the present Minister of Industrial Development who gave the slogan 'banish poverty' to this country. But, if poverty is to be banished, there must be sufficient food and sufficient cloth. The National Textile Corpora-

[Shri P. R. Shenoy]

tion should make available controlled cloth for the use of the poor people. Similarly, for lakhs of handloom weavers in the country, who are now unemployed, the National Textile Corporation should make available adequate quantity of yarn.

Sir, the Cement Corporation of India has proposed to set up a cement factory in Himachal Pradesh, two new factories in Madhya Pradesh and two new factories in Andhra Pradesh. This is a very good proposal. The only question is, whether the Planning Commission will accept this proposal. The Minister should see to it that this is accepted and cement production in the next Plan....

SHRI C. SUBRAMANIAM : All these are accepted.

SHRI P. R. SHENOY : Then, it is very good. This is a very good proposal. Lakhs of house sites have been distributed to landless people for construction of houses.

MR. CHAIRMAN : You have got your answer. Please conclude.

SHRI P. R. SHENOY : They have to construct houses on these sites. For this, they require cement. On these small sites, they have to build houses. If the houses are built, there will be construction activity and more people will get employment. So, keeping this in view, cement production should be doubled in the Fifth Plan.

One more point. This is about big industrial houses. I am not against big industrial houses. But, I do not understand, why should we go out of the way to give them incentives. Sir, it is true that backward areas should be developed. But, backward areas can be developed only by giving incentives to small industrialists and not big industrialists. These monopoly houses or large capital, are given this subsidy. These big industrial houses do not require these incentives. They do not go to a particular area on the basis of the incentives given. For instance, the MRTTP Act is

not applicable to Jammu and Kashmir. But, still, no monopoly house would go to Kashmir to establish a factory there. Similarly, South Kanara District in Karnataka is treated as a backward district. Even if it is not treated as a backward district, the big industrialists will go there, because a major harbour is coming up there. Why should we give them incentives to stare industries in Managlore, where a major harbour is coming up? These incentives should be given to small industrialists and not to the large houses.

Lastly, the recommendation of the Bhat Committee, in regard to small-scale industries, should be implemented as early as possible.

श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव (सीतामढ़ी) : सभापति जी, मैं आप के माध्यम से मंत्री जी का ध्यान उत्तरी बिहार की ओर ले जाना चाहता हूँ। हमारे उप-मंत्री जी ने कहा कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का चुनाव स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश से प्लानिंग कमिशन करता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ—बिहार के जिन 11 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया है, जिन में खास कर उत्तर बिहार के पश्चिमी चम्पारन, पूर्वी चम्पारन, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर तो चुन लिये गये, लेकिन उसी तरह की स्थिति सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर जिलों की हैं, इनको क्यों छोड़ दिया गया? इन तीनों जिलों में कोई इण्डस्ट्री नहीं है—मुजफ्फरपुर में केवल एक शगर मिल है, हाजीपुर जिले में कोई मिल नहीं है और सीतामढ़ी जिले के रीधा में एक मिल है, इसके अलावा वहाँ कोई इण्डस्ट्री नहीं है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ—जब फिर से बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का चुनाव बिहार में हो तो इन तीनों जिलों को भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में चुनवाने की व्यवस्था शीघ्र करें।

सभापति जी, हमारे उत्तर बिहार की आबादी तीन करोड़ है। हमारे यहाँ शिक्षित युवकों की हालत बड़ी दयनीय है, बेचारे पढ़ लिख कर नौकरी के लिये पटना से लेकर

वित्तीय तक दौड़ते हैं । अपनी स्माल-स्केल इण्डस्ट्री लगाने के लिये यदि वे कोई दरखास्त देते हैं—मटना में, जमशेदपुर में या मुजफ्फरपुर में तो उन के मामले अनेकों कठिनाइयाँ आती हैं । एप्लीकेशन देने के बाद महीनो उन्हें आफिस में दौड़ना पड़ता है । बैंक से लोन की आवश्यकता होती है तो बैंको में महीनो दौड़ना पड़ता है । मंत्री जी—अभी भी आप के डिपार्टमेंट में इन शिक्षित बेरोजगारों में परमेन्ट मागी 3. ती है । आप के वे अधिकारी जो लाइसेंस देते हैं, उन इजीनियर्स और शिक्षित बेरोजगारों में 5 परमेन्ट और 10 परमेन्ट घूम मागते हैं । मेरा आप से निवेदन है कि अहाँ भी आप के लाइसेंस देने के कार्यालय में आप वहाँ एक रजिस्टर रखें वह बहुत बड़ा साइज-बोर्ड रखें जिस में लिखा जाय कि आवेदक न किम तारीख को आवेदन किया और कितने दिनों में उस को लाइसेंस दिया गया । इस तरह की लिस्ट हर कार्यालय में टंगनी चाहिए । बड़े इण्डस्ट्री वाले तो लाइसेंस के लिये ऐसी घूम दे सकते हैं क्योंकि उन के पास क्लैब-मनी होती है और इसी लिये उन को लाइसेंस जल्दी मिल जाता है । लेकिन हमारे ये करोड़ों शिक्षित बेरोजगार घूम वा पैसा कहाँ से लायें, उन के अन्दर अनन्तोष फैलता जा रहा है । जिस का नतीजा अभी हाल में आप ने देखा है । बिहार और गुजरात में यवकान जो किया है उस मंत्री जी, आप के यहाँ उत्तर प्रदेश में भी वह फैलत होने वाला है । इस लिये यदि आप अपनी गद्दी को बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मंत्री के स्थान पर आर्कीन ग्ले तो आश को ही प्रशासकीय घूमखोरी बन्द करने की समुचित व्यवस्था करनी होगी । यदि आप मंत्री बरगे तो वह बिना दूर नहीं है कि जिस तरह में गुजरात के नवयुवकों ने किया, बिहार के नवयुवकों ने किया, आप के यहाँ उत्तर प्रदेश में भी होने चाला है । इस लिये इस स्थिति को रोखने के लिये देश के बेरोजगार युवकों को, जिन का संख्या पूरे भारत वर्ष में एक करोड़ है, मौबरी हिलाने के लिये, इण्डस्ट्री हिलाने के लिये तरह-तरीके इदवार, बरे

तभी देश में शांति हो सकती है । मैं बड़े मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आपके विभाग में खास करके हमारे उत्तरी भारतवर्ष के जो काम करने वाले हैं उनको बम तरजीह दी जाती है लेकिन दक्षिणी भारत के लोगों की एप्लीकेशन होती है या उनका रिमी तरह का प्रमोशन होता है तो उनको वह जल्दी मिल जाता है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने कार्यालय में बैठे, मोचे और हरणक स्टेट के, जो काम करते हैं उनको एप्लीकेशन निकलवाये और देखें किस स्टेट के आदमी हैं, क्यों किसी का नीचा स्थान है और क्या माउथ इडिया के जो रहने वाले हैं आपके यहाँ उनको पहले तरजीह दी जाती है । मेरा आपसे निवेदन है पूरे भारत-वर्ष में किसी भी स्टेट के काम करने वाले हो वह सभी लोग बराबर हैं और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उनके लिए आपकी तरह से एक तरह का इन्साफ होना चाहिए ।

अब मैं आपके द्वारा मन्त्री जी का ध्यान बिहार की ओर भी दिलाना चाहता हूँ । बिहार में खास करके उत्तरी बिहार में सीकी का एक उद्योग है जिससे इलिया और बहुत सा दूसरा सामान बनता है । उत्तरी बिहार में सीकी एक पाछे में पैदा होती है । मेरा निवेदन है कि सीकी इण्डस्ट्री का आप अपने विभाग में ले लें तथा जो काम इलिया व दूसरा सामान बनावे उसको बेचने की सरकार की ओर से व्यवस्था होनी चाहिए । जो गरीब किसान माको में रहत हैं वे यदि इलिया या बर्तन बगैरह बनाकर लावे तो उसको खरीदने की व्यवस्था सरकार की ओर में होनी चाहिए ।

**समापति महोदय** अब आप समाप्त कीजिये ।

**श्री नरेश्वर प्रसाद यादव** श्रीमन्, बिहार में सबसे एक खास होती है जिसमें रस्सी बनाई जाती है और रस्सी से घर बनता है, मेरा निवेदन है कि सबसे से जो रस्सी बनती है उसको खरीदने की व्यवस्था भी सरकार की ओर से होनी चाहिए ताकि जो गरीब

[श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव]

किसान इस काम में लगे हुये हैं वे अपनी जीविका चला सकें। सिमेंट, पेपर का कारखाना सरकार की ओर से सीतामढ़ी में बनना चाहिए।

**सभापति महोदय :** अब आप समाप्त कीजिये।

**श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव :** आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मुझे अभी बातें रखनी तो है जो घट रहा है इन दिक्कतों को तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि क्या दिक्कतें हैं इसलिए यदि दो मिनट और दे देते तो बड़ी अच्छी बात होती। खैर, जो समय आपने दिया है उसके लिए बहुत धन्यवाद।

**SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) :** Mr. Chairman, I have heard the speech of the hon. Member who preceded me and I was sorry to hear what he had said about Shri Subramaniam. From whatever experience I have had of Shri Subramaniam for the last 25 years, I can say that he is very honest and straightforward and he is an out and out nationalist and also a realist. The way in which some allegations were levelled are all false and mischievous. Mr. Subramaniam cannot tolerate any injustice or make any difference between one man and another man.

I am very glad to see that Mr. Subramaniam has presented a very good Report to this House. He has projected all the weaknesses and defects in his Report. He has not tried to conceal or hide anything. That shows his boldness with which he is going to tackle the difficult problems of the country.

As the time at my disposal is very limited, I would like to just make a few points. If we want to have an overall growth rate of 5.5 per cent in the country, every year, the industrial output should be not less than 9 to 10 per cent. Then alone, we can maintain 5.5 per cent growth rate every year. As present the population is increasing at the rate of 2.5 per cent and the consumer goods must be produced at the

rate of 10 to 11 per cent. Unless and until that is done, it is not possible to keep up with the demand. The rural rich and so many other classes of people who have never seen the good before are now demanding these goods for their use. So, the production of consumer goods should go up by 10 to 11 per cent.

Andhra Pradesh was very backward in previous years. I am very happy to say that Mr. Subramaniam has laid the foundation of industrialisation in Andhra Pradesh in the field of heavy electricals and other things. It has now come up well. I am asking for some more factories in Andhra Pradesh not because that I am selfish but because that will add to the overall growth of the country. It is in that perspective that I am demanding some factories in Andhra Pradesh.

We want a cooperative jute factory at Salur in Srikakulam district. We want a newsprint project at Bhadrachallam. As you know, we are producing newsprint only to the tune of 40,000 tonnes in this country and we are importing over 2 lakh tonnes from foreign countries. If that gap is to be reduced, this newsprint factory should be immediately established in Andhra Pradesh. I request the hon. Minister that immediately all necessary arrangements may be made so that we may not depend upon foreign countries.

Then, we want two fertiliser factories, one at Kothagadam and another at Vizag. That is very essential. In this area a lot of coal is available. We are now going in for coal-based fertiliser plants. I request the hon. Minister to set up these fertiliser factories in Andhra Pradesh very soon.

There is a proposal for a steel plant at Vizag. It is, of course, during his earlier time that it was contemplated. But it is at a stage where it was before. Immediate steps should be taken to start it.

There should be a nylon filament yarn plant in Rayalaseema area. This

is a very backward area. I hope, the hon. Minister will take suitable steps to do all these things.

Besides this, Andhra Pradesh has lot of raw material for cement. Already, three cement factories have been sanctioned. But the work has not been started. These cement factories have been sanctioned with a capacity of 4 lakh tonnes each at Yerrangunta, Tandur and Adilabad. These factories also should be started early. Our Chief Minister has sent detailed notes to the Central Government. He has given a promise that he would help in establishing these factories. The way our Chief Minister is moving in the matter shows that he is very dynamic and, I hope, all these factories will be started soon.

Recently, Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Padma Shri awards have been awarded to eighty persons. But not a single industrialist has been awarded any of these awards. In the whole of India, when the cement factories were producing not even 80 to 90 per cent of their capacity, one factory in Andhra Pradesh has produced 130 per cent of its capacity.

I want to know whether the Minister is going to consider giving an award to them....

16 hours.

AN HON. MEMBER : Which factory ?

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : Keshav Ram Cement Factory.

It is not a question of individual. Whichever factory has exceeded the target and has produced 20 or 30 per cent more, must be given some encouragement.

Regarding monopolies and other things, I want to say, whether the monopolists are paying the wages to the labourers or not, whether they are paying the taxes or not, whether they are producing goods or not, these are the only things that are to be taken into

consideration and not any other thing. If somebody is making money, after paying all taxes, so long as he makes money legally, it is allright; if there is any illegal thing, then those people can be tried under the law.

SHRI K. GOPAL (Karur) : Mr. Chairman, my hon. friend, Mr. Yadav, has spoken about South Indians; he had a grouse that the South Indians were being preferred everywhere. I will tell a story. When God created man in India, He had two tins of paint, one intelligence and the other beauty. He took the tin of beauty and started painting from Kashmir. By the time He went to Kanyakumari, He finished that. Then He started with the tin of intelligence. You will excuse me, Sir, for saying this. Before He reached Bihar, He had finished with that. That is the reason why the South Indians are intelligent and are preferred.

श्री परिपूर्णानन्द पेंचुली (टिहरी-गढ़वाल) : सभापति जी, मैं उद्योग मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ। इस संदर्भ में मैं उद्योग मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर खींचना चाहता हूँ और वह यह है कि हमारे देश के औद्योगिक विकास के समन्वित रूप से कार्यान्वयन की सब से बड़ी कसौटी यह होनी चाहिए कि हमारे देश के जो प्राकृतिक साधन हैं उनका वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करते हुए हम जन शक्ति का किस प्रकार अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। इन तीनों में जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक औद्योगिक विकास की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। चूंकि जन-शक्ति साधन और साध्य दोनों हैं इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज से 15, 20 साल के बाद हों जिन को रोजगार देना है वे चूंकि जन्म ले चुके हैं इसलिये 15, 20 लाख बाद देश का औद्योगिक विकास किस प्रकार का होना चाहिये अपनी जन-शक्ति को ध्यान में रखते हुये उस का नियोजन करना चाहिये। हमें यदि जन-शक्ति का ठीक प्रकार से उपयोग कर सके तो वो

[श्री परिपूर्णनन्द पैन्थूली]

दो करोड़ बरोजगार लोग हैं वे हमारे देश पर बोझा न हो कर बरदान सिद्ध होंगे ।

एक हमार छोटे छोटे उद्योगों को बड़े कारखाने दारों की प्रतिस्पर्धा में उन्हें मुकाबला करना पड़ता है और दूसरी ओर एम क्षेत्र है जहाँ कोई प्रतिस्पर्धा तो नहीं है किन्तु शासन की नीति ऐसी है कि उन को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है जिसके कारण वहाँ का विकास नहीं होना है । 1951 में 1970 तक औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार 3 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से बढ़ा जिसके विपरीत अद्योगिक उत्पादन 6 प्रतिशत की दर से बढ़ा है । इस औद्योगिक विकास में मुट्ठों भर लोगों को—जहाँ बहुत अधिक लाभ पहुँचा है वहाँ उस क्षेत्र की गरीब जनता को उनकी ही क्षति उठानी पड़ी है । यह भी खेद का विषय है कि 15, 20 सालों में हमारा अधिकांश जोग विकास की अपेक्षा राजनीति पर रहा है—चाहे कुर्सी की लड़ाई हो और चाहे हड़ताल और नानाबन्दी की बात रही हो । यह दुख की बात का विषय है आज भी हम दलबन्दी से बाहर निकल कर देश के विकास की दिशा में नहीं सोचते हैं । मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ चूक पक्षपेकिब प्लानिंग का अभाव रहा है इसलिये क्षेत्रीय विषमता काफी बढ़ी है और बढ़ रही है । इस क्षेत्रीय विषमता को दूर करने का एक उपाय यह ही सकता है कि जो क्षेत्र अधिक विकसित हो चुके हैं, हमारे उद्योग मंत्री जी और प्लानिंग कमीशन को एक बात तय करनी चाहिये कि वह अपनी ग्राम इन्कम से कम से कम 1 प्रतिशत धन जो अपेक्षाकृत रिच्छे हुए क्षेत्र हैं उन के विकास के लिये रखें । यदि ऐसा नहीं होगा तो जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उद्योग की दृष्टि से वे सारे देश पर भार बन कर रह जायेंगे और विकसित क्षेत्रों के विकास में भी रुकावट पैदा करेंगे ।

मैं उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र का जिक्र करना चाहता हूँ जहाँ पर 60 प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं और खनिज सम्पदा भी है । किन्तु खेद

का विषय है कि नाम मात्र को भी कोई उद्योग धंधे वहाँ पर नहीं है । मेरे पास वहाँ पर एक रिपोर्ट है :

Report of the Working Group on Forest Development and Utilisation — 'UP Hill Areas'.

जिस में यह स्वीकार किया गया है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों का दो बिहाई सारा रेजिन मैदान का फेक्ट्रियों में चला जाता है, विशेषकर बरेला में जा पड़ता है जिस में पूजा पत्तियों के शोर्स हैं उस फेक्ट्री को सारा रेजिन चला जाता है, लगभग साग बच्चा माल मैदान के बाखाना का चला जाता है । कैम्पर बन्धा और प्लाई वुड आदि जिनमें भा उद्योग धंधे मैदानों में वन सम्पदा के बने हैं वे पहाड़ों से नीचे चले जाते हैं पहाड़ों में चूना है, जिमम है उन सब को वहाँ में दोहन कर मैदान में भेजा जाता है ठेकेदारों, बिचौलियों के माध्यम से और पहाड़ों का बुरी तरह से शोषण हो रहा है । अग्नी देहगादून के पास विस्फोटक मिश्रित पैदा होने वाली है जो चूना पत्थर के मालिकों ने वहाँ पर पैदा कर दी है, वहाँ पीन के पानी के श्रोत सुख गए हैं, गाव उजड़ गये हैं और लोगों के खाने के माधन समाप्त हो गये हैं ।

अभी उपमन्त्री जी ने कहा कि पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिये सरकार कुछ करना चाहती है, चाहे उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्र हो या जन-जाति के क्षेत्र हों । किन्तु दुर्भाग्य है कि सारी प्राकृतिक सम्पदा दूसरे लोगों के विकास में आती है और वहाँ के आदमी पहले की तरह पिछड़े हुए हैं और गरीब हैं । पहाड़ी इलाकों में काफी ऊन होती है किन्तु उस के विकास के लिये हमारे पास कोई समन्वित योजना नहीं है । मैं इस सवर्ष में उद्योग मंत्री जी और उन के उपमन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि चाहे कागज की कमी हो, सीमेंट की कमी हो, वह चाहे इस्पातों के कारण या बिजली के अभाव के कारण हो, आवश्यकता इस बात की है कि

एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय से तालमेल हो। तालमेल के अभाव में हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। हम में आपस में तालमेल होना चाहिये। पहाड़ों में ऊन है, उस के विकास की योजना है। किन्तु उत्तर-पार्शी की ऊन जो विशेषज्ञों के अनुसार भारत में सब से बढ़िया होती है, वह ऊन पानीपत की फैक्टरीज में चली जाती है और वहाँ के लोगों को मैदानों से घटिया किस्म की ऊन खरीदकर तसल्ली करनी होती है। पहाड़ों में लोग भेड़ पालन करते हैं, लेकिन उन के लिये चरागाह की व्यवस्था नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भेड़ों के चरान चुगान के लिये पास्चर लैंड को कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है। वहाँ जो जमीन अब तक थी भी वह भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। पहाड़ों का जो दक्कन माल है वह चाहे सहारनपुर का प्राइवेट सेक्टर का बागज का कारखाना हो या किसी दूसरी जगह के कारखानों में उन सब को चला जाता है। इस प्रकार से पहाड़ों का शोषण पूर्ववत् जारी है। चाहे पहाड़ी इलाका हो या जन जाति क्षेत्र हो या पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो, वहाँ जो प्राकृतिक सम्पदा है उसका वहाँ समुचित उपयोग करके वहाँ के लोगों को लाभान्वित किया जाना चाहिये। वहाँ जो जन शक्ति है उसका आपको इस काम में उपयोग करना चाहिये।

इस संदर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि गढ़वाल और कुमायूँ से इस बार विधान सभा की सीटें, जो 21 हुआ करती थीं वे घट कर 19 ही रह गई हैं। यह इसलिए नहीं हुआ है कि फ़ैमिली प्लानिंग का असर वहाँ हुआ है, बल्कि इसलिये हुआ है कि जिन दिनों में सैंस होता है पहाड़ का आदमी रोटी रोजी की तलाश में, बरतन मलने, घरेलू काम करने के लिए मैदान में आ जाता है और ऐसा करने के लिये उनको मजबूर होना पड़ता है। रोजी-रोटी की आवश्यकता उन्हें ऐसा करने के लिए उनको मजबूर करती है। इस वास्ते उनकी गिनती नहीं हो पाई। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है कि वहाँ के आदमी को आप

किस प्रकार से वही जिन्दा रखना चाहते हैं? जिस आदमी ने हाई स्कूल पास किया उसके वास्ते पहाड़ पर कोई साधन नहीं होता है। शिक्षा की व्यवस्था आप इस प्रकार की करें कि वहाँ के साधनों का वहीं रह कर वह किसी प्रकार से उपयोग कर सके और अपने पैरों पर वहीं खड़ा हो सके, पहाड़ों पर रह कर वह कैसे जिन्दा रह सकता है?

पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के बारे में आप से हम बड़ी बड़ी बातें जब सुनते हैं तो वे बहुत अच्छी लगती हैं और मीठी भी। लेकिन जब वस्तुस्थिति को हम देखते हैं तो बड़ी मायूसी होती है। इस सम्बन्ध में नैशनल इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो मैं समझता हूँ कि वह भी कर दिया जाना चाहिये। 1956 के नैशनल इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन में कहा गया था :

“Only by securing a balanced and coordinated development of the industrial and agricultural economy in each region can the entire country attain higher standard of living.”

यह जो पालिसी निर्धारित हुई थी इसका यदि ठीक तरह से पालन हो जाए तो कम से कम पिछड़े हुए इलाकों का सुधार हो जाता है वहाँ बसे हुए गांवों के लोगों का विकास हो सकता है।

केन्द्रीय तथा प्रान्तीय और फाइनेंशल इंस्टीट्यूशनज द्वारा बैंकवर्ड एरियाज में सहायता की घोषणा की गई थी। किस प्रकार की सहायता की व्यवस्था है इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है, वहाँ के इलाके के लोगों को नहीं होती है, और यहां तक कि जो वहाँ जिला उद्योग अधिकारी काम करता है उस तक को नहीं होती है और अगर होती भी है तो वह किसी को बताता नहीं है। जो इंस्टिट्यूट आप देना चाहते हैं उसकी जानकारी लोगों को आपको करानी चाहिये। जिला स्तर से लेकर केन्द्रीय स्तर तक आपको सैमिनार्ज आयोजित करने चाहियें। देहरादून उत्तर प्रदेश का एक एजुकेटिड इलाका है। वहाँ काफी छोटे बड़े उद्योगपति हैं। वे लोग शटल काक

[श्री परिपूर्णन्द पेंसली]

की तरह भागते फिरते हैं उद्योग भवन के शास्त्री भवन और वहा से मिनिस्ट्री आदि में। लेकिन जो चीज उनको चाहिये वह मिलती नहीं है। कोयला नहीं है या रा मीटोरियल नहीं है तो वह परेशान होता है। इन सब में तालमेल बिठाने के लिये जिला स्तर पर आप कोओर्डिनेशन मशीनरी का निर्माण करे या इस तरह का वहा सेंट आप कायम करे ताकि उनके समय, पैसा और शक्ति वा दुरुपयोग न हो। आज होता वह है कि कोर्ट एव योजना बनाता है इडस्ट्री लगाने की तो जब तब वह उनको कार्यान्वित करने की स्थिति में आता है दो माल के बाद तब उनको पता चलता है कि दो लाख जो लागत आनी थी वह अब चार लाख हो गई है।

पिछडे हुये इलाको वा विकाम इमलिए भी नही हो पाता है कि बहा इनफा स्ट्रक्चर वा अभाव रहना है। इमका उप मंत्री जी ने स्वीकार भी कियो है। मैं पूछना चाहना हू कि कब आप वहा के लिए इनफा स्ट्रक्चर तैयार करेगे ? क्या दिल्ली के एयरकडीशन्ड कमरो में बैठ कर या लखनऊ कलकत्ता आदि-राजधानियो में बैठ कर विकाम की स्कीमे बनाएंगे ? मैं कहना चाहता हू कि स्कांज को कार्यान्वित करने के लिए आपको ध्यान दी स्पार्ट जा कर देखना चाहिए। बकिंग ग्रुप की रिपोर्ट भी सही होनी चाहिए। सब में ज्यादा जरूरत बात यह है कि जो लोग उनका अध्ययन करने हैं उनका भी रिप्रोिएटेशन होना चाहिए। उनको अच्छी तरह जा कर इस बात की देखना चाहिए कि किस क्षेत्र व. क्या आवश्यकताएं हैं, बहा पुर्स्वीनी रूप में क्या-क्या कारोबार हो रहे हैं। पुर्स्वीनी उद्योग धंधे तो सब जगह समाप्त हो रहे हैं। जो नये उद्योग धंधे बहा कायम आप करना चाहते हैं उनके लिए बहा पर लोगों वा एंटीक्वूड नहीं है और जो उद्योग धंधे उन्हें अपनाते को बहने हैं। लोग उनको करना नहीं चाहते हैं। इस सब को आप को देखना चाहिए। अब इन सब

बातो को आप देखते नहीं हैं तो बाद में आप कह देते हैं वहा के लोग कुछ करते नहीं हैं।

मैं चाहता हू कि पहाडी इलाकों में, पिछडे इलाको में रिसोर्स बेस्ट इंडस्ट्रीज और एक्सायमेट औरिएटिड इंडस्ट्रीज की तरफ आप अधिक ध्यान दें। ऐसा आपने किया तभी उन इलाकों वा विकाम होगा।

खादी ग्रामोद्योग का यहा बहुत जिक्र हुआ है। मेरा निवेदन है कि वह एक तरह का ह्याडट एंलीफैंट है। हमारे इलाके में उनका रोल नगण्य रहा है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना हू। हमारे यहा पर रेडीमेड वपडे बिकते हैं। वे मैदानो से ग्रहमदाबाद आदि से बन कर आत और बिकते हैं। क्यों नहीं खादी कमीशन वही लोगो से उनकी कोआपरेटिव बनावत करके उन म रेडीमेड वपडे बनावता है और वहां लोगो को अपने पैरा पर खडा करने में मदद देना है। ईस्ट इडिया कंपनी की तरह खादी कमीशन और खादी भण्डार पहाडो में फैलता जा रहा है। खादी कमीशन को चाहिये कि शहद, लकड़ी, जडी बूटी आदि पर आधारित उद्योग धंधो की बहा स्थापना करने के लिलसिले में कदम उठाए। ये लोग भारी भरकम तनख्वाहे लेते हैं और एनाउस भी इनको बहुत मिलते हैं। लेकिन उधर ये ध्यान ही नहीं देते हैं।

रेशम उद्योग का जहा तक ताल्लुक है मैं आपकी तारीफ करना हू और बधाई भी देता हू कि आपने उसे उचित महत्व दिया है। आपने हिन्दुस्तान के टस्सर के कोकूज और चीन के टस्सर के कोकूज से, उनके सम्मिश्रण में क्रस ब्रीड तैयार की है। पता नहीं भारत का नर है या चीन का साबा है। जो नया कोकूज निकला है कहते हैं कि यह बहुत बढ़िया है, इसका रेशम बढ़िया होता है और संसार में उसकी बिक्री करके हमें फारेन एक्सचेंज प्राप्त हो सकती है। रेशम उद्योग का काम ऐसा है कि लोगों को उससे काफी शोबदार मिल सकता है। मेरी प्रार्थना है कि पब्लिसि इलाको में आप खास तौर से इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दें।



अपनी कंस्ट्रक्शंस के बारे में एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ। देहरादून में कालसी के पास सिमेंट के कारखाने की बात तीसरी योजना में कही गई थी। मुझे खशी है कि हिमाचल में पहले से एक सिमेंट का कारखाना था और वहाँ एक और दे दिया गया है। पिछड़े हुए इलाकों के साधन जुटाने और प्राकृतिक सम्पदा का उपयोग वहीं करने और कारखाने बनाने की आपने योजना की है। मेरी आप से करबद्ध प्रार्थना है कि आपने तीसरी योजना में सिमेंट के कारखाने को कालसी में नहीं लगाया, चौथी में नहीं लगाया, अब पांचवीं में तो लगाएं। अगर सिमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया इसको नहीं कर सकती है तो कम के कम उत्तर प्रदेश की सिमेंट कारपोरेशन को ही आप लैटर आफ इन्टेंट दे दें ताकि वहाँ रोजगार के साधन बढ़ें और उस पिछड़े क्षेत्र का विकास हो।

SHRI JAGANNATH RAO (Chattrapur) : Mr Chairman, Sir, this ministry is in charge of the vital sector of the economy. This Ministry is in charge of an orderly development of industrialisation of this country. But, it is faced with two basic difficulties—one difficulty is the growth of monopoly houses in the country with the lopsided development and the other difficulty that it is faced with is the shortages. Unless these difficulties are solved, there cannot be any orderly development or planning of industrial development in the country.

The growth of monopoly is of historical origin because, business houses were in existence since a long time, by the time we gained Independence. There were getting licences because they had the know-how, resources and everything. Like a monster they grew and there is concentration of economic powers in their hands. We have passed the M.R.T.P. Act. But still, we are faced with the difficulties. We want more production. So, the only answer for this should be the rapid expansion of the public sector. But, then, the public sector takes time to come up. We

want more production with certain restrictions being placed. What kind of restrictions can there be? You will see that under Sec. 27 of the M.R.T.P. Act, there is a provision according to which, the Central Government is empowered to direct the larger houses to shed a part of their shareholdings in industries so that their shareholdings would not be diluted. As far as public sector is concerned, I say that it should be allowed to expand in a big way, but the public sector is not doing that? In spite of our Industrial Policy Resolution 1956 the public sector is slow in expanding itself. And to-day we are faced with the difficulty of financial resources. Everywhere we find that there are shortages—shortages of power, coal, cement, steel and everything. While I was in school, I read about the stone age—people using stone implements and later came Iron Age. When we come to Parliament, we learn about shortages of raw materials, shortage of finished products and so on and so forth. This is a world of shortages. That is all I can say. Shortage is world-wide phenomenon—not confined to this country alone.

I really wonder how the Ministry of Industrial Development will develop the industrialisation of the country.

Be that as it may, attempts are being made to increase the industrial development of the country. The Report has not given us the details as to how many medium industries have come up during the year under review and how many licences have been given to the larger houses. That would give us an idea whether the medium sector is coming up gradually which can be an answer to the monopoly houses in course of time. We would like to have the details in the Report on this aspect at least next year.

Sir, the Ministry is often criticised that the backward areas are not industrially developed. I do not see any reason why the Central Government or the Industrial Development Ministry be accused of industries not coming up in backward areas. The primary duty of

[Shri Jagannath Rao]

the State Government is to see that the areas which have been identified as backward districts some infrastructure is prepared by them. If the infrastructure is there then it is open to the Central Government to insist on a person who applies for a licence to go to a backward district. In the absence of the infrastructure I do not see any reason why this Ministry should be blamed. Everyday we find the Minister is asked to explain as to why industries have not come up in the backward areas. The State Governments have to prepare the infrastructure. It is their responsibility. Then only we can accuse the Ministry.

The small scale sector is a redeeming feature of our economy. They are doing a good job. About 177 items have been reserved for the small scale sector. I had been dealing with this subject some years ago and I am very happy to see the progress of the small scale sector. But then the industrial estates were started in 1958 when Shri Manubhai Shah was in charge of the Industries Ministry. The industrial estates have come up in the country but all the industrial estates are in the urban areas. No industrial estate has been started in the semi-urban or rural areas. If these industrial estates are started in these areas they will serve two purposes. Firstly it will give employment potential to the man in the village. Secondly it would prevent people migrating to the urban areas and the rural economy will also be boosted. Therefore, the Ministry should take care to see that in further when industrial estates are set-up they are established in the rural areas so that it will help rural unemployment problem and also give strength to the rural economy.

Sir, it is very essential that every industry—whether a large house or a medium house—school be compelled to have a research and development wing. They should carry on research on their own so that they can improve on the processes of manufacturing these goods. USA is the first-rate power today not because of the military strength or the

nuclear power but because of its advance in the field of science and technology. I am glad to know that the Government has entered into several agreements with the western and East European countries to get the technical know-how so that in course of time we should develop our own technology and utilise the same in manufacturing industrial goods. This is highly necessary because this will minimise losses and will also ensure the necessary quality control.

Finally, I would say a word about the private sector also. We have no control the private sector as such, except in the matter of giving them licences. The private sector cannot go scot-free. Every day we have questions here about the public sector and the performance of private undertakings, but we cannot put questions about the performance of private undertakings. This Ministry is implementing the Industrial Policy Resolution which deals with both the sectors, and therefore, it should have a control over the performance of the private sector, and the private sector also should be made answerable to the Ministry not only regarding their performance but also about utilisation of capacity, about quality control, productivity and so many other things so that there will be proper growth. When the public sector is subject to so much of scrutiny by Parliament, the private sector also should be brought under the scrutiny of Parliament.

With these words, I support the Demands.

MR. CHAIRMAN: Three more speakers are there on the list before me, Shri Giridhar Gomango, Shri Y. P. Mandal and Shri B. N. Bhargava. So, I am afraid the hon. Minister will have to start his reply at 4.40 p.m. or so. These three speakers may kindly confine themselves strictly to the time-limit of five minutes each.

SHRI GIRIDHAR GOMANGO (Koraput): I rise to support the Demands for Grants under the control of

the Ministry of Industrial Development as also the other Demands placed before the House. Since the time at my disposal is short, I shall make only three or four points.

Big industries are developing in the country and they contribute to the growth of economy. But when they are established in the forest areas and the tribal belts, where our tribal people are living, they have a bad impact on them. The recommendation made by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission is that big industries should be established in the tribal belts, and if they are established, they should give proper chance to the tribals to work in the factories and to live in the factory areas. I would like to know from the hon. Minister what steps have been taken to give all these facilities to the tribals in this regard.

Just now, Shri Jagannath Rao has pointed out that the ministry has no control over the private sector industries which are established in the various places. These private sector units also are not looking to the welfare of the tribals and the welfare of the society in general. You know, Sir, that water pollution and air pollution have been increasing in the country posing a health hazard to the people. I would request the hon. Minister that he should issue instructions to the private industries to look into this matter and take steps to prevent water and air pollution.

The Fifth Five Year Plan will be starting from the coming financial year. I received a letter from the Planning Minister that there would be sectoral allocation from the various Ministries. There is a proposal for sub-plan for tribal areas. I would like to know from the hon. Minister how the sectoral allocation from the Ministry of Industrial Development will flow into the tribal areas? My point is that let industries be established in the tribal areas not big industries but only small-scale industries. If big industries are established in tribal areas, then the tribal people will be

deprived of the opportunity of getting employment since they have no technical skill or knowledge. So smaller industries should be started in the tribal belt, especially in the forest areas. There should be forest-based industries and agro-industries and other industries of a small nature by which my people will be benefited as a consequence of industrial development.

In conclusion, I would refer to some industries which are coming up in my constituency, namely the calcium carbide plant in the Koraput district, the cement factory at Sunki, and the paper plant in Jeypore and the spinning mill at Rayagada. These four factories should come up in the Fifth Plan so that the employment opportunities to the people of the district will be higher than before.

I would like to know the allocation made in the Fifth Plan by the Ministry of Industrial Development to the tribal areas, and whether the State Government have submitted any report to the Ministry regarding the development of the tribal areas or not. I hope the hon. Minister will look into the matter and do the needful.

श्री यमुना प्रसाद मंडल (नमस्तीपुर) :  
सभापति महोदय, मैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की डिमांड्स नम्बर 157-158 तथा माइंस और टैक्नोलॉजी विभाग की डिमांड्स नम्बर 100 और 101 की पूरी तार्किकता करता हूँ। इस के साथ ही मैं मिनिस्ट्री को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने काफी नये इमेन्टिबल कूलर और बैकवर्ड एरियाज के लिए विग हैं उन्होंने बहुत मुन्दर और इत्युमिनेटिंग निटरेचर बनाया है। मा० सदस्य डा० एल० एन० पांडेय साहब (जनसंघ) और मा० सदस्या पटेल साहब भी इस तरफ देखें तो उन्हें उस से रोशनी मिलेगी। उन के दिल डिमाग में तो यह रहता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, डिस्ट्रिक्शन हो रहा है तो उन के डिमाग में तो हमेशा डिस्ट्रिक्शन ही डिस्ट्रिक्शन रहता है। हमें ऐसे विद्वान लोगों से उस शब्द की ग्राशा

[श्री यमुना प्रसाद मंडल]

नहीं थी जब कि वह देश में इतनी चीजें होते हुए देख रहे हैं।

श्री के० ए०० नन्जप्पा साहब जो डेवलपमेंट कमिश्नर थे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के उन्होंने अपने फोरवर्ड में कहा है :

"During this period of 1½ decades, we have made all these things but the problem, though formidable, has been constantly engaging the attention of Government".

5 लाख गांव हैं। गांवों में एनर्जी की कमी है और जब यह सब बातें उन्होंने कही कि फारमिडेबल है उस के बाद दूसरी पंक्ति जब उन्होंने शुरू की तो कहा :

"Industrialisation of backward areas in a country like India is admittedly a difficult task".

मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि यह बड़ा टफ टास्क है 5 लाख गांवों को ठीक करना।

सभापति महोदय, आप ने इस संबन्ध में बहुत काम किया, उस के लिए सारा देश आप का आभार मानता है और आप ने जो मेमोरेण्डम दिया प्राइम मिनिस्टर को मुझे इजाजत दीजिए मैं उस की कापी (प्रतिलिपि) सदन के मेज पर रखूँ, उस के साथ साथ मैं एक दो पैराग्राफ उस में से पढ़ना चाहता हूँ। डा० कैलास (बम्बई क्षेत्र) घबड़ाएंगे नहीं, आदरणीय सदस्य धामंकर जी (महाराष्ट्र) घबड़ाएंगे नहीं, दो एक बातें उस में ऐसी होंगी जो उन को अच्छी न लें। पार्लियामेंट के मेम्बर्स ने कहा :

"We must lodge our strong protest against the allotment of Rs. 2,000 crores for developing the twin city of Bombay".

आप बम्बई को बढ़ाएँ, कलकत्ते को बढ़ाएँ, मद्रास को बढ़ाएँ, मगर आखिर इन गांवों का क्या होगा? पांच लाख गांवों

का क्या होगा? उन के लिए तो आप ने कहा कि हम कुछ न कुछ करेंगे।

I shall read another portion from the memorandum submitted by MPs from all the States to the Prime Minister and shall request the Chairman to allow me to lay the document on the Table.

MR. CHAIRMAN: You may read the relevant portion, but whether it can be laid on the Table or not will have to be decided only according to the rules. I am not deciding it now.

SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL: We have done this so many times with the special permission of the Chair. This is not the first time it is being asked.

MR. CHAIRMAN: Your time is short. Please go on.

SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL: "It is of the utmost importance that funds be provided for the backward areas. We demand at least Rs. 10,000 crores to be allotted from plan funds..."

हमारे मुख्य ग्यम् साहब बड़े अनुभवी हैं और बहुत दिनों तक मद्रास जैसे बड़े राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। ये जानते हैं क्या करना है। मैं ने इन्हें केवल इमारा ही दे दिया।

उस के बाद आप ने आल इंडिया बैंकवर्ड कान्फरेंस किया था। मैं गोमांगो साहब से कहना चाहता हूँ कि उस में हम लोगों ने पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए भी 16 करोड़ रुपये की मांग की थी और आप मुझे अनुमति दें तो मैं यह दोनों बहुमूल्य पत्र जो पचासी एफ० पी० के हस्ताक्षर से दिए गए हैं सदन की मेज पर रखूँ\*

ऐसा पहले हुआ है, यह कोई नई बात नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : आप दें दीजिए। अध्यक्ष महोदय उस का निर्णय करेंगे।

\*The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission the documents were not treated as laid on the Table.

श्री यमुना प्रसाद मंडल : मैं आप का बड़ा अनुग्रह मानता हूँ और कृतज्ञ हूँ ।

हमारे नगन्द्र भाई ने कहा था कि उन का जिला छोड़ दिया गया है । मैं उन से कहूंगा कि वह अप्रेंडिक्स नम्बर 2 में देखें, उन का जिला है मगर वह तीन हिस्से में बंट गया है मुजफ्फरपुर, इसलिए वैशाली का तो आया ही । मैं जैसा देखता हूँ लिस्ट आफ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में तो उस में दिया है :

“List of backward districts eligible for concessional finance from the financial institutions as on 31-8-1973”.

अब मैं नार्थ बिहार की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ । यहां करीब तीन करोड़ लोग रहते हैं । आज सैकड़ों मील चले जाइए सिवाय एकाध शहर मिल के कुछ नहीं मिलेगा । गरीबी बेहद है । वे विरोधी दल के लोग लूटने का काम करते हैं । जो भी धान का पौधा होता है मा० रामावतार की शास्त्री जी की पार्टी के लोग उस को लूटने की कोशिश करते हैं । अब मैंने सुना है कि भूसा से 15 परसेंट एडिबल आयल निकाला जायगा । उस के संबंध में कुछ लिटरचर दें, कुछ करें ।

अब मैं बम्बई की तरफ आता हूँ । वहां खादी ऐंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का हेड आफिस है । मैं सारे हाउस की इजाजत से कहना चाहता हूँ, जब 20 हजार गोबर गैस प्लान्ट्स आप देना चाहते हैं, 5 लाख गांवों को सुधारने का आप न ब्रत लिया है तो बम्बई में भी आफिस रखिए, बंगलौर में भी रखिए, हरयाना (चंडीगढ़) में भी रखिये बिहार में भी रखिए जहां लाइव-स्टॉक (गोबर देने वाले मवेशी) ज्यादा है । मगर सारी चीज दखिए । मैंने एक चिट्ठी लिखी थी । उस चिट्ठी के जवाब में उन्होंने लिखा कि आप बम्बई भेजिए, बम्बई वाले पटना भेजेंगे, पटना वाले मधुवनी भेजेंगे ।

From pillar to post. What is the sad plight of the poor kisan?

गोबर का मतलब है गोपाल

Everyone is a gopal and we have now come back to this.

गांधी जी की वाणी सत्य हुई ।

Back to villages.

एक छोटी सी बात जो मैं सुब्रमण्यम् साहब से कहा चुका हूँ, अनौपचारिक रूप से, उसे फिर यहां सदन में दोहराना चाहता हूँ । समस्तीपुर पेपर पल्प के बारे में पृष्ठ 53 पर लिखा है —शार्टफाल इन पेपर प्रोडक्शन । यह बात वह मानते हैं । एक छोटी सी मिल समस्तीपुर में है हमारे यहां ‘ठाकुर पेपर मिल है । उस की सच्ची तस्वीर मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूँ । आई० एफ० सी० के चेयरमैन ने भी माना है कि 6-7 साल से वह बन्द है और कुछ हो नहीं रहा है । सारे बिहार के हिस्से में एक पेपर मिल है । मैं एक लाइन उस के बारे में बढ़ना चाहता हूँ :

Page 53—Shortfall in paper production मुख्य मंत्री (श्री गफूर) “...Hence, the whole matter is to be finalised in a day or two, and the IFC and BFC may also be informed.” This is on the 10th November last, and today is March 27, 1974. Nothing has been done and I request the Minister to look into it. I am happy that I have brought this to the notice of one of the senior-most Ministers who had also been the Planning Minister, Mines and Mineral Minister, Food Minister, etc.

श्री बशेश्वर नाथ भार्गव (अजमेर) : सभापति महोदय, औद्योगिक विकास, विज्ञान एवं तकनीकी अनुसंधान मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत मांगों का मैं समर्थन करता हूँ । देश के आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है । मैं विशेष तौर पर औद्योगिक विकास मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि देश में जो क्षेत्रीय असन्तुलन है उस को यह मंत्रालय ठीक प्रकार के समन्वित कार्यक्रम के द्वारा प्रभावकारी ढंग से दूर कर सकता है । उन का ध्यान मैं इन ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । यहां पर

सदन में बहुत से लोग कहते हैं कि राजस्थान के पूजापति देश के भिन्न भिन्न दूर-दूर के भागों में जा कर उद्योग स्थापित करते हैं। मगर क्या कभी यह ध्यान गया कि राजस्थान में उस की पुरानी ऐतिहासिक परम्पराओं के कारण तथा अन्य कारणों से, कोई इन्फ्रा-स्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं था। इसी लिये वे सब पूजापति देश के दूसरे हिस्सों में जाते रहे और राजस्थान के अन्दर कोई उद्योग स्थापित नहीं कर पाये। वहाँ के रजवाड़ों का एक पुराना इतिहास है, उन राजे-महाराजाओं ने केवल अपने विलास की सामग्री के साधन वहाँ पर उपलब्ध किये लेकिन गरीबों के लिये किसी प्रकार की कोई भूमिका भ्रदा करने की कोशिश नहीं की।

दूसरी ओर वहाँ प्रकृति का प्रकोप तो आप जानते ही हैं। एक साल के बाद दूसरे साल वहाँ भयंकर अकाल पड़ता है। ऐसी हालत में राजस्थान की जनता किधर देखे—“राम भी नाराज और राजा भी नाराज।” मैं बड़ी नम्रता के साथ, परन्तु दृढ़ता से आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान की जो समस्याएँ हैं, खास कर पिछड़े इलाकों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दें। आप ने कुछ नाम्नों के आधारे पर कुछ इलाकों को पिछड़ा इलाका घोषित किया है। आप वे बताया है कि आप के मन्त्रालय को पिछड़ा इलाका घोषित करने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार की सिफारिश पर प्लानिंग कमीशन उन को पिछड़ा इलाका घोषित करती है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ तक अजमेर का सम्बन्ध है या तो राज्य सरकार में कोई गलती हुई है या आप के यहाँ निर्णय लेने में कोई गलती हुई है। अजमेर ऐसा जिला है, जहाँ हर एक साल के बाद दूसरे साल अकाल पड़ता है। यह बात खरूर है कि अजमेरों के शासन में 1947 से पहले चूँकि वहाँ मजदूर काफी संख्या में उपलब्ध थे, अजमेरों ने वहाँ कुछ साधन पैदा किये, जिस से उस समय कुछ कारखाने लग गये, लेकिन यदि आज आप वहाँ की प्रति व्यक्ति औसत आय ले तो आप पायेंगे कि वहाँ की औसत आय बहुत

कम है, इस लिये कि वहाँ छोटी छोटी जोते हैं। मेरी प्रार्थना है कि ऐसा निर्णय करते समय उस स्थान की औसत आय की क्राइटेरिया मान कर चलना चाहिये और उसी के आधारे पर पिछड़े क्षेत्रों की घोषणा होनी चाहिये। वरना इस से आगे बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कोई दूसरी पोटेन्शियलिटी नहीं है, इस प्रकार डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उस से विषमता की स्थिति पैदा होगी और उस के बहुत गम्भीर परिणाम होंगे।

अब मैं कुछ अन्य चीजों की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूँ—हमारे यहाँ विजयनगर में एक लाइसेंस मसौदा सिन्धटिवस को दिया गया था लेकिन बाद में उस को बदल कर वहाँ से 8 मील की दूरी पर लगाने की स्वीकृति दी गई। मैंने इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को लिखा। उन्होंने जवाब दिया कि राज्य सरकार की सिफारिश पर उस को 8 मील की दूरी पर बदल दिया गया। इस का कारण क्या था—नया स्थान बैंक-वर्ड डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ आप की तरफ से बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। जिस वक्त शुरू में उन्होंने लाइसेंस प्राप्त किया—उन को मालूम था कि वहाँ क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं। लेकिन जब बैंकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की घोषणा हुई तो उन्होंने अनेकों कारण बना कर उस लाइसेंस को बैंकवर्ड एरिया में बदलवा लिया, जिस से सरकार के 5-7 लाख रुपये का चूर्ण हो गया। मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करें—जब पहले राज्य सरकार की सिफारिश पर उन को लाइसेंस दिया गया, उस समय वहाँ पानी भी उपलब्ध था और दूसरे साधन भी उपलब्ध थे। उन्होंने बदलने के लिये जितने रीजन्स दिये, उन के कोई मायने नहीं हैं—केवल बैंकवर्ड एरिया का लाभ उठाने के लिये उन्होंने ऐसा किया।—ऐसी चीजों की तरफ आप का ध्यान जाना चाहिये।

जहाँ मजदूर कार्मी होते हैं, बेकारी ज्यादा होती है, सरकार वहाँ इंडस्ट्रीयल एस्टेट

बनाती है। लेकिन मैं निवेदन करूँ—ब्याबर के अन्दर बहा के लोगो ने अपनी प्रेरणा से "इन्दिरा गांधी रूरल इन्स्टीट्यूट एस्टेट" बनाई। बहा राज्य सरकार के और दूसरे अधिकारी जाते हैं और उन के प्रयत्नो की बहुत मराहना की है, लेकिन उन को कोई सहायता या सहयोग नहीं मिलता है। अपने ही आघार पर वह चल रहा है। मन्त्री जी ने कहा कि हम लघु उद्योगो को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूँ कि ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जिन को सब से पहले तो सहायता प्राप्त करने में ही बहुत कठिनाई होती है, उस के बाद न सिमेंट है और न दूसरी चीजे हैं। जब तक कोई पैकेज डील नहीं होगा, वे फ्रस्ट्रेट होंगे, उन को ब्लैकमार्केट की कठिनाइया से गुजरना होगा और उस के बाद जब उन का उद्योग स्थापित होगा तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि उन के अन्दर किस प्रकार का करैक्टर होगा।

आज कई ऐसे उद्योग हैं जिन को रा-मैटीरियल नहीं मिल रहा है। वे ऐसे उद्योगो से रा-मैटीरियल ब्लैक में खरीद कर अपना काम चलाते हैं जिन का कोई उद्योग ही नहीं है। आप थोडा डम की गहराई में जाइये। अगर आप के पास कोई खबर भेजते हैं तो आप लिखने हैं कि इस को राज्य सरकार देखेगी। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब मैं वहा जाता हूँ तो लोग मुझ से कहते हैं कि हम को रा-मैटीरियल नहीं मिल रहा है, लेकिन जो उद्योग स्थापित नहीं है उन से रा-मैटीरियल खरीद कर अपना काम चलाते हैं—आप उस समस्या पर गम्भीरता से विचार कीजिये देखिये कि उन की क्या सहायता हो सकती है।

अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर में किशनगढ़ गाटा-बादला उद्योग था जो 1963 में स्थापित हुआ था। छोटी-मोटी, बूटी-फूटी मशीनें ला कर उन्होंने उस को स्थापित किया और रा-मैटीरियल

प्राप्त कर लिया। 1971 में उन को इम्पोर्ट लाइसेंस भी मिल गया, यद्यपि वे उस को प्रबेल नहीं कर सके। आप इस की गहराई में जाइये—यह सब क्या हो रहा है। जो एन्टरप्रेन्यार सरकारी दफतरो में चक्कर लगा कर, भेट-पूजा कर के लाइसेंस और रा-मैटीरियल प्राप्त करे, वह अपने उद्योग को अच्छी तरह से नही चला सकता, उद्योग को चलाने के लिये तो उसे अपना पूरा समय उद्योग में लगाना होगा। इस बात की गहराई में जानें की जरूरत है।

आज सीमेन्ट की हमारे यहा इतनी कमी है। 1966 में घोषणा की गई कि व्यावर के आस-पास अच्छे किस्म का चूना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है—इस काम के लिये एक लाइसेंस साहू-जैन को दिया गया, लेकिन मोनोपली हाउस की वजह से उन को लाइसेंस प्राप्त करने में विलम्ब हुआ। उस के बाद मैं निरन्तर आप को लिखता रहा हूँ, कभी फाइनेंस की दिक्कत होती है, कभी दूसरी चीजो की दिक्कत होती है। आप ने सीमेन्ट कारपोरेशन की स्थापना की है—जब वहा चूने का बहुत अच्छे किस्म को पत्थर उपलब्ध है तो वहा पर यह उद्योग क्यों स्थापित नहीं हो रहा है। यदि निश्चित अर्बाध के अन्दर साहू-जैन अपना उद्योग बहा स्थापित नहीं करते हैं तो सीमेन्ट कारपोरेशन उस उद्योग को वहा स्थापित करे, परन्तु इस काम में विलम्ब नहीं होना चाहिये।

फौरन-कोलाबारेणन के सम्बन्ध में सरकार की एक निश्चित नीति है। फौरन-कोलाबारेणन उसी हालत में एलाऊ दिया जाता है जब कि देश में उस प्रकार के तकनीकी ज्ञान की कमी हो या वह ज्ञान न हो। मैं आप के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ—वास्तव में यह नीति बहुत अच्छी है, लेकिन त्रियाम्बिति में स्वार्थ के कारण उस नीति के पालन में हस्ताक्षेप होता है तथा अनेको प्रकार की विषमताये पैदा हो जाती है। हमारे यहा अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र ग्राम कुचील में एक "माइक्रोनिकस इन्स्टीट्यूट" है जो अपने यहा इलेक्ट्रोनिकस

[श्री बशेश्वर नाथ भार्गव]

के सामान का उत्पादन करते हैं। 1973 दिसम्बर में जो यहां औद्योगिक प्रदर्शनी हुई थी उस में उन्होंने अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन भी किया था। लेकिन उस के बावजूद भी आप ने बम्बई की एक फर्म "नलिन पी० सेठ, 5, हम्माम स्ट्रीट, बम्बई-1" को अमरीका की फर्म कैम्ब्रिज थर्मोनिक कारपोरेशन, 445, कान्कर्ड एवन्यू, यू० एस० ए० के साथ कोलाबोरेशन एलाऊ किया। यह फर्म भी वही चीजें बनायेगी ऐसा कालाबोरेशन आप की नीति के विपरीत है। मुझे विश्वास है कि इन चीजों को आप गहराई में जा कर देखने और औद्योगिक क्षेत्र की महायता करेंगे।

इन शब्दों के साथ, सभापति जी, मैं आप का आभारी हूँ, आप ने मुझे बोलने का मौका दिया।

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRAMANIAM): Sir, admittedly the country is passing through a very difficult period. The economy is under great strain. I am sure hon. members are aware that Government is not taking a complacent view of the situation. The *Economic Survey* presented to this House portrays the real situation in the economy and we have not tried to hide the facts. Therefore, it is nothing surprising that this situation was reflected in the debate in this House. When we are in difficulties, naturally we try to use some harsh words also. As far as I am concerned, I am not hurt by those harsh words. I take it as a spur, a whipping to me, to make greater efforts for the purpose of remedying the situation. Every member was concerned with the stagnation in industrial production, particularly since 1965-66, when a recession set in after two years of consecutive drought. We have not got out of that difficult situation, and even though there has been some spurt in industrial production in some years, the tempo of industrial production has not picked up to the extent necessary. In 1973 it has almost come down to zero per cent growth.

Very many hon. Members made, if I may say so, relevant points from their point of view. But if we have to get over the situation, we have to take an over-all view and find out what are the basic causes for the stagnation, and unless we remove those basic causes, even though we may attempt to take action here and there, ultimately we may fail to attain our objective of pushing up industrial production.

Particularly with reference to the experience we have gone through during the last two or three years, in my view the basic infra-structure which is required for industrial development and industrial growth is not adequate enough. Here when I refer to the basic infra-structure, I mean the energy which is required for the purpose of running the industry. When I talk of energy, it is represented by two commodities, namely, coal and power. Of course, transport is also involved in it.

Unfortunately, in all these three areas we are not in a comfortable position, to put it mildly, because one affects the other. For the purpose of power production, particularly in the thermal stations, we want coal. So, unless coal is produced, we cannot have power production. Even if coal is produced, if it is not moved to the consuming point, the power cannot be produced. If we are not able to produce coal, we cannot run our railways. So, this becomes a vicious circle and this is where we have to concentrate. The Government are trying to concentrate their attention to see that a more comfortable position is reached with regard to this basic infra-structure of coal, power and transport.

Unfortunately, it is not merely a question of technical difficulties. There are also human difficulties involved it, particularly in the railways. The problem is one of labour relations, which is a human problem. To the extent it gets deteriorated, every other section will get affected. Therefore, it is necessary for all of us, particularly Members of Parliament, to take note of this situation. I am mentioning this because just now a friend gave me a notice which has been



issued by the representatives of the employees in railways that they want to go on an all India strike. What will be the consequences of that for the country as a whole will to be realized. Of course, those who are interested in chaos and fishing in troubled waters might be happy. But this is going to create a very very difficult situation for the country as a whole and for the people, and I am sure for the poorer people all the more, because the rich people can manage any situation. So, this aspect will have to be kept in mind. It will be our continuous endeavour to see that this basic infra-structure is further improved. All possible measures are being contemplated or being worked out and their implementation will have to be done in a more effective and efficient way.

Then, on parallel with this, raw materials is important for industrial production. Steel is a general raw material, which can be considered almost a basic infra-structure for industrial production. Unfortunately, there also we are facing difficulties. In regard to non-ferrous metals, the production has fallen down and, particularly, the aluminium production has gone down. So, we have to meet the situation.

I think, a pertinent question was put by the hon. Member, Shri H. M. Patel, "Your Ministry is not concerned with all the commodities. How are you going to manage it?" It is not possible to load all the commodities on one Ministry because it will break under the weight of it. Therefore, it has to be spread out in various Ministries. What is important is to have coordination amongst the various Ministries for the purpose of achieving results. That is why, recently, a Cabinet Committee on Industrial Trade has been constituted. On some occasions, the Prime Minister also, if necessary, presides over it. Generally, the Industrial Development Minister presides over it. There, all the various bottle-necks that arise between one Ministry and another Ministry are discussed and decisions taken in an expeditious manner. About things which

would have taken months and months, because we discuss various problems across the table, we take decisions then and there.

One example before me is how a decision was taken in regard to production of steel in mini-steel plants. As regards mini-steel plants, till now, there was a restriction that they could produce only ordinary steel. They could not produce any special steel or alloy steel. We have got into difficulties particularly with reference to certain types of steel which we are not able to get from integrated steel plants because they are in small quantities and they cannot plan production of those types of steel. After a full discussion, we immediately took a decision that mini-steel plants should be allowed to diversify their production and that they could produce various types of steel according to their capacity and according to their capability also. It was possible to take a decision immediately. This decision was taken only a few weeks back.

We are trying to see that instead of the old procedure of one Ministry writing to the other Ministry and the other Ministry starting noting from down below, from the Section Officer, and finally, taking months to come to a decision, we take a decision immediately by having a discussion across the table. We are trying to get over it. I am not prepared to say that we have reached the maximum efficiency. But we are in the right direction. It is by a coordinated effort that we are trying to solve the problem.

One other factor also has come into prominence during the last three or four years that industry cannot function in isolation, that it is related to agriculture more than anything else, because many of the raw materials required for our traditional industries, particularly like, textile, jute, sugar and oil, have to be provided by agriculture. Whenever there is a failure in agriculture and the raw materials are not available, automatically, these industries get affected. In the same way, agriculture today cannot function without industrial backing because it is not subsistence agricul-

[Shri C. Subramaniam]

ture. The modernised agriculture requires various industrial inputs for the purpose of increasing production in agriculture. Therefore, it is no longer possible to look at agriculture in isolation or at an industry in isolation and take decisions on the basis of plans. "This is a completely agricultural sector; this is a completely industrial sector." On the other hand, we have to take a coordinated and a well-knit decision which will take into account all the sectors of economy as a whole.

17 HRS.

In the past, we always used to say that whenever there was failure of monsoon, the agricultural production was affected. But in the last two or three years, we have come to the position where, because of monsoon failure, industrial production has been affected. About 40 per cent of electricity is produced in the hydro-electric projects. In the past when the level of industrialisation was limited and the other uses of electricity were also limited, even during monsoon periods we were able to manage. But now when it has been stretched to the utmost limit, even when there is full production, it is not adequate. And when there is shortfall in the production of electricity, immediately it affects the industrial production; the shortfall in the production of electricity affects not only industrial production but also agricultural production because a large number of pumpsets today are electricity-based. Therefore, this is the sort of situation in which we are placed today. And it is by taking a comprehensive view, by taking comprehensive decisions with regard to this, that we will be able to get out of the present situation.

Today we are faced with the problem of inflation and rising prices; whether there is justification or not, prices are rising every day. And if you look into the basic cause why this inflationary trend is so pronounced now, it is mainly because of stagnation in production whereas the money supply is increasing. When money supply is increasing, if, at the same time, production also had

been increasing, perhaps this type of inflation would not have been there. Therefore, industrial stagnation and stagnation in agricultural production have contributed to the inflationary situation. They affect the economy as a whole. Therefore, today if we want to get out of this situation, we have to plan in such a way that we increase our production in all sectors, be it agricultural sector or industrial sector, again in the industrial sector, whether it is large scale sector or medium sector or small scale or village industries, whether it is public sector or private sector or joint sector. This is the position with which we are confronted today. If, for any reason, the production lags behind, to that extent, naturally, the adverse factors in the economy will get more intensified and the position will become more and more difficult.

It is in this context that we have to view our industrial policy also. I think, the hon. Member belonging to the CPM party, who initiated the discussion, made a charge that there has been shameless retreat with regard to industrial licensing. I thought I had explained in this very House the stand that the Government have taken with regard to industrial licensing. The February 1973 publication has made this position definite that larger houses and the foreign-owned companies can enter only particular areas.

AN HON. MEMBER: The core sector.

SHRI C. SUBRAMANIAM: You may call it core sector or basic sector.

As I was saying, the larger houses and foreign-owned companies can enter into those areas which are more capital-intensive, which have long gestation period and which require greater expertise for the purpose of putting up those industries. It is not as if, simply because larger houses are entitled to enter these industries, automatically they are given preference. On the other hand, if there is a competition between a medium entrepreneur and a larger

house, the medium entrepreneur is selected. It is only when the medium entrepreneur is not available and the production of the commodity is essential for the economy that we consider either a larger house or a foreign-owned company. I would like to illustrate this with reference to cement industry which we administer in our Ministry. I think, Mr. H. M. Patel made this point; at one stage we were surplus in cement but suddenly we have gone into a state of deficit, and he asked why this had happened. It is mainly because we thought that this had now become a common technology. Anybody can adopt it and, therefore, why should this be given to the larger houses? Therefore, in my view, we rightly took the decision at the time that we may try to release this industry from the larger house, participating in it and give it to the medium entrepreneurs of others who would come into the field. But, unfortunately, for two or three years nobody else would come forward and, therefore, a sort of stagnation set in. Then again, we reviewed the situation. It is not a charge in the policy resolution as such. This was an *ad-hoc* decision taken by the Cabinet and, therefore, the Cabinet again reviewed it and said, 'If you want to get out of this situation, it looks as if we will have to consider applications from the large houses.' I've then what did we do for the purpose of 12-13 million tonnes of cement which we have got to produce during the Fifth Plan? First we said, 'What is our capacity in the public sector Cement Corporation?' And we made a realistic assessment and, we did not stop there. We added a little more than what we thought would be the capacity of the Cement Corporation and loaded it on the Cement Corporation first. Hence, as the hon. Members mentioned, six new projects came—2 in Madhya Pradesh, 3 in Andhra and other things also were mentioned. After that we gave preference to the State Industrial Development Corporations. Proposals from them for plants in the joint sector with other private entrepreneurs were given second priority. The third priority was given to such applications which came from houses which were

not considered to be larger houses but medium houses. It is only after that and when there was still a remnant we had to take a decision. Shall we face a scarcity or shall we import cement from elsewhere or shall we ask the larger houses to produce it? Then, we thought that a rational decision in this situation would be not to depend upon imports or to face a scarcity but to make use of the larger houses for the purpose of filling the gap with regard to cement.

The same process was gone through with regard to paper production also. Now, at the level of 40,000 tonnes we have to invest Rs. 30 to 40 crores. Here also, we have now a Paper Corporation and in the Paper Corporation we have also brought in a new management. It has been possible for us to get the best man available in the paper industry. He was functioning in the private sector and we have brought him as the Chairman of our Paper Corporation. This is a healthy development which is taking place to-day for many top-level executives whom we consider to be very efficient managers, are giving up large salaries like Rs. 7000 or Rs. 10,000 and in certain cases even Rs. 12,000 and are coming over to the public sector management, receiving only Rs. 3000 or Rs. 3500. Here also as a rule we cannot go beyond the salary of a Secretary. That is how there seems to be some sort of a sanctity that nobody else should get a higher salary than the Secretary. But, in spite of that, many private sector management people come, not the capitalists as such but the professional managers are coming over to the public sector and therefore, in the Paper Corporation also we loaded this Corporation also we loaded this Corporation as much as possible. It is only after that we tried to find out to whom else we should give.

In that connection, I think a mention was made about the functioning of the Nepa Mills and how by just changing one man at the top we will change the whole situation. This has happened not only in the Paper Corporation but this has happened in many other units also, provided you put the proper man at the top. The whole situation dramatically

[Shri C. Subramaniam]

changes. I can give umpteen instances in the public sector. One instance which is a very remarkable thing is the Heavy Electricals. Within two years the situation has dramatically changed. The Hardwar unit which was a lame jack is now a healthy unit going forward form strength to strength. So also is the Bhopal unit and Hyderabad unit; so also is the Trichinopoly unit and...

AN HON. MEMBER : Instrumentation Limited.

SHRI C. SUBRAMANIAM : National instruments in Calcutta. We just changed it. It is now 160 per cent increase of production in one year. What was losing at the rate 40 lakhs have broken-even already. Somebody mentioned about the Hindustan Photo Films. No doubt it is going through very difficult period but I want to assure this House that it is not a question of obsolete technology. It is a question of inefficient management till now and that is why we have changed the management and just within a few months after change of the management healthy results have started coming in.

DR. KAILAS : Cement and steel is not available in NEPA Mills. Why should the public sector also stand in the queue as the private sector? That was our difficulty, Sir.

SHRI C. SUBRAMANIAM : We are taking care of it. To be particular, the industrial project will not suffer for want of them I will come to this aspect immediately, that is to say, with regard to the steel shortage and the cement shortage. So, this is now the picture is easing and therefore while there had been stagnation, I want to point out that because of the changes taking place in the public sector, in this dark horizon there is a silver lining particularly in respect of the functioning of the public sector projects.

During 1973 there was no growth in the general industrial production but as far as public sector projects were concerned, there was 7.6 per cent growth during 1973 as compared to 1972. But in this 50 per cent weightage is given

to IOC. If you remove that then the growth is about 17 per cent. This is the sort of development that is taking place within the public sector and therefore I want to give the assurance to the hon. Members that we are giving priority to public sector projects. We have made them more efficient so that there may be more and more justification to establish further industries in the public sector. That is how we are looking at it and fortunately as far as the public sector projects are concerned, no longer can the accusations be made that they continue to make losses. They have turned the corner. They are making profits. And I want to assure the House that this profits is going on increasing from year to year

SHRI K. S. CHAVDA : By converting loans into equity the public sector has shown a profit. It is merely a book-entry.

SHRI C. SUBRAMANIAM : It is not with reference to financial profits alone that I am talking I am talking with regard to utilisation in road terms, how much we are producing. Therefore it is not a question of mere jugglery, it is actual, physical production, and how much they are producing in a particular industrial unit in the past, and how much they are producing today. So, as far as the public sector projects are concerned, with this improved management as a whole and improved management personnel we will continue to make progress. Of course there are certain limitations with regard to expansion of the public sector and every industrial activity because it is just not possible. Let us stabilise this increase, then you can go further.

And then the question of nationalisation comes now and then and then one asks, why don't you nationalise all the 75 or 80 industrial course. Sometimes the trouble starts as soon as you nationalise. This is the case. This cannot be done unless such conditions are created there. If you are getting rid of you troubles well and good. But what is the use of advising that you go on and nationalise more and more

and inviting more and more trouble ?

This is the sort of thing, particularly, the hon. Members from this side of the House will have to take note of. If they are really interested in the nationalisation, let them make the public sector projects and other nationalised projects a success. That can be done provided they give their wholehearted cooperation with regard to the labour relations.

On the other hand they want to play politics more and more, particularly, in the public sector projects. Those persons who plead for the public sector projects are most prominent in playing politics in the public sector projects. This is the position with which we are concerned. Therefore, I would request the hon. Members of my party also to make a note of this thing if they are saving that larger houses should be immediately liquidated—I wish we are in such a position—we should be in that position. Unfortunately we are not in that position. So, till then, we have got to utilise these larger houses in certain areas at least for more and more production. When we talk that others should come and take over the production of various commodities, it just does not happen overnight unless we create circumstances for the purpose of helping the new entrepreneurs, particularly, the middle and smaller men. Unfortunately, these facilities were not available to them till now. That is why we have appointed a Committee under the chairmanship of Shri Bhatt. He is the Chairman of the Investment Centre. That Committee has made recommendations with regard to the various steps to be taken in regard to new institutions, consultancy services by the financial institutions in the States. We have already circulated a list to the State Governments and we discussed the same with them at the Industries Minister's Conference. Therefore, during the Fifth Plan, we should create more and more conditions for enabling the newcomers' being introduced in the field so that they become more and more broadbased rather than getting concentrated in a few hands. That is how we are going to get over

the difficulty. Ultimately we will have to have some sort of control over the private sectors, particularly, over the larger houses. In the national interest it has to be done. That is under the consideration of the Government. I am not in a position to tell you what positive steps we are going to take because, it is still in the process of consideration. That is very much in our minds. It is in that context that I want you to look into the 1974 projects. Some people accuse us of an optimistic view being taken. Optimistic view is also taken subject to certain conditions. Take for example the industrial production which is stagnating. I asked the office to make an assessment of the industries which constitute the industrial production index. You all know that this was on the basis of the industries that existed in the year 1960-61. Public sector undertakings' production did not come into the index of industrial production. We are making a new exercise to base the index on the industries that existed in 1968. Perhaps, the hon. Members might ask me as to why is it then that we are talking in terms only of traditional industries and other industries that came into existence upto 1960-61.

With regard to this, we find no imports of raw materials are required for industries which contribute to 63% of the industrial growth according to the weightage given. That all depends upon the availability of indigenous raw materials. There is no question of the raw materials becoming scarce at all because of the foreign exchange situation. If that be so, then we should be able to break the coal position, power position as also transport position which we have got to-day. Otherwise, the nation itself will break down. With the increased availability of raw materials like cotton, jute, sugar-cane and various other things, the production is bound to go up. That is why I say that taking into account the difficulties experienced in the matter of foreign exchange, about which I shall deal a little later, we have taken an optimistic view. And if we are able to manage this sector, at least, in the proper manner, we would

[Shri C. Subramaniam]

be able to show a better level of industrial production and a better industrial growth. It is on that basis we have taken an optimistic view. Some hon. Members feel we should give the most pessimistic view and make people more frustrated. We have to point out to the optimistic points of view which could be taken and the steps to be taken for implementing that. That is more important rather than saying you have taken an optimistic view. We will see that steps are taken to increase the production of coal, steel, transport and power.

**SHRI SURENDRA MOHANTY** (Kendrapara) : How can you manipulate the monsoons ?

**SHRI C. SUBRAMANIAM** : The production of power will increase from 600MW to 1000MW.

It is a question of managing this system so that we may not further deteriorate. So, it is not a wishful thinking alone but it is based on broad facts. I agree that there will have to be a better management of the system.

Sir, mention was made about the new industrial licensing procedures and many Members complained that the old delays have continued. I am sorry to say that they have not looked into the facts. Since this new arrangement came into effect from 1st November a weekly review of the situation is made. When we say it should be disposed of within 90 days it is not just 90 days and then left the whole system to drift at the end of the 90 days. For every step we have fixed a time-limit and within the time-limit they have to—whether it is DGTD or other sister Ministries or the Textile Commissioner—send their assessment. Fortunately, during the last five months the system has been keeping to its target and about 95 per cent of the total applications have been disposed of before 90 days time-limit. The remaining five per cent will be cleared in the next few weeks. So, it is no use saying it is only a paper scheme. I am quite confident that this 90 days time-limit and

150 days time-limit for MRTP applications can be kept up and will be kept up.

I know the hon. Members are concerned about the pre-November applications. As on 1.11.1973 when we introduced this system there were 3848 pending applications, and by 1.3.1974 this has been reduced to 2071. They have been disposing of 300 to 350 applications per month. This is the rate they have kept up. If we go in the same way the remaining 2071 applications could be disposed of in the next 6 months. Of course, some hard cases will keep on hanging but by and large these applications would be disposed of. Then it is a routine of the new industrial procedures keeping to this 90 days limit. It is not merely issuing a paper which is important. After all, of this paper can solve the problems, we can issue any number of letters of intent and any number of licences also and say that we have issued so many papers and therefore the problem is solved. Unfortunately till now we had not kept track of what was happening to these papers, and that was how some people were able to corner it also by getting a Letter of Intent and sitting over it for years together so that other also did not come into the picture. Now, we have made it obligatory for every Letter of Intent and licence, in fact, we have provided a form along with that where the person has to give an account of the steps taken during those six months. If they do not provide the statistics, it means that they are not taking steps; then, we would cancel the letter of intent or the licence and we give them an opportunity to explain why they have not done it. So, continuous monitoring from the time of the issue of the paper till it goes into production and becomes a production unit has been built into this new procedure. This is how we are trying to see that not merely there is expeditious disposal of applications but the applications come to fruition as producing units. This is the sort of transformation which has come about, and I am sure that there are many faults and deficiencies in the functioning of my

Ministry and I am quite conscious of them, but still not the sort of deficiencies which some Members from Bihar had talked about and regarding which he had also levelled all sorts of charges there. I wish he has a better view and he takes a more reasonable view of the steps taken within the Ministry. If he could give me instances and point out any injustice done to anybody or any wrong which is happening anywhere, I am prepared to take immediate steps.

AN HON. MEMBER : A single Member from Bihar.

SHRI C. SUBRAMANIAM : But even a single Member counts, particularly when he speaks here. Perhaps, he has been briefed by somebody else; otherwise, he cannot speak like this. Therefore, there are interested parties to brief in that way. But if he really feels that there is something wrong, I am prepared to sit down with him and discuss the matter.

SHRI DHAMANKAR : Why attribute motives to Members?

SHRI C. SUBRAMANIAM : Various suggestions were made, particularly by my hon. friend Shri K. S. Chavda. He made a very useful suggestion from his point of view and asked why diversification should not be allowed so that everybody could be allowed to increase production by 40 per cent which according to him should not be allowed to the foreign-owned companies but to everybody also including the large houses.

SHRI K. S. CHAVDA : My point was this.....

SHRI C. SUBRAMANIAM : Let him kindly hear me. After that, he can get up.

SHRI K. S. CHAVDA : There is a wrong understanding regarding the point that I had made.....

SHRI C. SUBRAMANIAM : I have understood him fully.

SHRI K. S. CHAVDA : I shall put my question after he replies.

SHRI C. SUBRAMANIAM : As a matter of fact, we have given even now 25 per cent diversification with regard to the various industries permitting them to increase their production by 25 per cent, and that is applicable particularly to select industries, as far as the larger houses and foreign companies are concerned; they are not allowed to expand in all sorts of industries they are having but only in certain specific industries, and it is only on that basis that this diversification and increase in capacity by 25 per cent has been allowed. The hon. Member seems to think that instead of 25 per cent it should be 45 per cent. So, it is only a question of degree, but in principle it has been accepted.

SHRI K. S. CHAVDA : Why has this concession been given to foreign firms and large industrial houses under press note No. 3(3/165) CS-III dated 27-7-1969? I have written a letter to him already. That is why I am referring to that?

SHRI C. SUBRAMANIAM : I cannot remember these obliques and dashes off hand. I shall look into it

SHRI DINEN BHATTACHARYA : In the case of detergents, expansion has been allowed very recently to the Lever Brothers.

SHRI C. SUBRAMANIAM : It is not merely the number of applications which make the position a little bit optimistic but I have got some figures also. There is no evidence from the various indicators that we have that the pace of new investments incoming up is showing an increasing trend. In the first eleven months of 1973-74, capital goods imports were approved of for Rs. 152 crores as compared to Rs. 113 crores in the corresponding period of 1972-73. In the first six months of 1973-74, 1,824 companies were registered with total authorised capital of Rs. 554 crores as against 1437 companies with an authorised capital of Rs. 176 crores in the first half of 1972-73.

[Shri C. Subramaniam]

The term-lending institutions, IDBI, ICICI and State Finance Corporations sanctioned loans for Rs. 178 crores and made disbursements for Rs. 111 crores in the first half of 1973-74 as compared to Rs. 137 crores sanctioned and Rs. 79 crores disbursed in the first half of 1972-73.

Therefore, the investment climate also has, in my view, improved, to a certain extent.

SHRI K. S. CHAVDA: You have not replied to my point.

SHRI C. SUBRAMANIAM: A point was made with regard to financial institutions, that they take their own time. That is why now they are linked up with new industrial licensing procedures also. Once in a month, they come over to Delhi, sit along with our Secretariat officers and try to find out what are the capital goods clearances which have to be made and on what basis so that loans could be sanctioned on an expeditious basis. Therefore, a certain co-ordination and linkage has been brought into existence with the licensing procedure machinery particularly with regard to capital goods.

This development has got to take place keeping in view the need for bringing about regional balance. This is a well-accepted principle. But unfortunately, it has not been possible to achieve it. Particularly when we take measures for the speedy implementation of projects, we have to see that this balance is restored. We are very conscious of it, but here there is competition for the purpose of getting districts declared as backward. I wish a mere declaration of backwardness could solve the problem. The fact is that in spite of this declaration, the progress made has not been quite satisfactory.

Even though over the years I find that the number of licences/letters of intent with reference to backward areas has been increasing, it has only creepingly increased, not in a very dynamic way. Therefore, we have to take into account the factors which contribute

to the hesitancy of industry to go to these backward areas. This is where the growth-centres concept is an important point.

SHRI SURENDRA MOHANTY: Why not use the licensing procedure as a leverage?

SHRI C. SUBRAMANIAM: You can. You can take the horse to the water, but cannot force him to drink. Unless some facilities are available, you cannot expect them to just go there and establish industry on virgin land. That is why the concept of growth centres has been accepted. We are working out projects in these backward areas, identifying growth centres and providing infra-structures facilities for the purpose.

In this connection, I want to make one thing quite clear. Just pushing one big industry into a backward area is not going to remove its backwardness. If that were so, Bihar should be the most developed State because we have got so many big public sector industries located there. Among the States, Bihar has the largest number of public sector units

SHRI CHIRANJIB JHA (Saharsa): South Bihar, not North Bihar.

SHRI C. SUBRAMANIAM: Take South Bihar. But is it reflected in progressiveness or advancement? Absolutely not. Therefore, to think in terms of pushing a few industries into backward areas and making them advanced will be to indulge in an illusion. That is why more comprehensive development is required. That can happen only on the basis of area development, agricultural development, development of industries based on agricultural raw materials, processing of agricultural materials producing the various inputs required.

The finest example for us to follow—we need not go to Sweden or other foreign countries—is the pattern of Punjab. Even though there is no worthwhile big public sector industry located in Punjab today, it has the highest per



capita income which in the last ten years it has doubled.

**PROF. MADHU DANDAVATE** (Rajapur) : They are the best human material.

**SHRI C. SUBRAMANIAM** : We should also try to become a little better human material instead of blaming others. This is what has got to happen. While the human material may be inadequate, we can at least copy what has been done by others.

Therefore, this is how we have got to approach the subject. In that also, as I am going to speak later, we are going in for improved science and technology which will help backward areas in getting over their backwardness.

With regard to the small scale industries, Khadi and Village Industries Commission, coir industry and other such industries, my colleague has dealt with them elaborately, and therefore, I am not going into those things now. As I have already stated with regard to the public sector projects in my own Ministry, they are all picking up. No doubt there are some sick babies and we are trying to nurse them, but on the whole, as I have already stated, the public sector is projecting a much better image now.

I will now come to the other important subject, namely, science and technology. I am glad that at least a few Members took notice of this very important aspect of industrial development. I think Dr. Kailas started the process and then Shri Jagannath Rao and a few others also mentioned about it. Ultimately, it is not by getting technology imported, if necessary in the initial stages, that any nation is going to become industrially advanced. If today there are countries which have made advance in the industrial sector and the agricultural sector also, it is a reflection of their scientific and technological competence, and as long as we continue to be scientifically and technologically incompetent, comparatively, then, to that extent, however much

we may take measures, the development cannot match the requirements. That is why we have given importance to the development of science and technology, not the general development of science and technology, but science and technology for the purpose of reaching our socio-economic goals. This is the exercise which the National Committee on Science and Technology has made. I do not know how many Members had looked into it. Only yesterday I laid on the Table of the House the first and second volumes of the draft plan on science and technology. I would request the hon. Members, at least such of the Members as are interested in it to take hold of the volumes, go through them and I am sure this is the first exercise which is likely to bring out the defects and deficiencies and I would like to have the suggestions from the hon. Members with regard to this. I am circulating it to the entire scientific community also for the purpose of getting their suggestions. Nearly 2,000 scientists and technologists were involved in evolving this plan. It is not just an exercise of ten wise men. On the other hand, experts in every field were assembled and they have given us the plan with regard to each sector. Nearly 2,000 scientists and technologists were involved in it.

Today, what is important is, what priority we are going to give to the development of science and technology, because, in our difficult situation where resources are scarce, we seem to think that perhaps this is a luxury expenditure. On the other hand, it is only the application of science and technology which would enable us to utilise whatever resources we have to the maximum advantage. It is from that point of view that we have to approach the science and technology plan and it is from that aspect that the NCST draft plan. will have to be looked into.

I would like to place before the House certain high-lights with regard to this science and technology plan. What are the priorities we have given in it? The first point is,—It is not because I was

[Shri C. Subramaniam]

the Minister of Food and Agriculture for some time that I say this—in our economy, agriculture has got a pre-eminent place, and without that, we are not going to make any progress whatsoever. Therefore, we have given importance, as far as science and technology is concerned, to agriculture as the first priority. In that, it is not merely a question of more and more production. In our country, we produce, as a matter of fact, enough. If we avoid the wastages that happen after the harvest, we will be a surplus country. Even a very optimistic estimate shows that in foodgrains we lose about 10 million tonnes by way of wastages at various points. Therefore, post-harvest technology is as important as the technology preceding it. That is the main areas to which we have given emphasis.

The second area now is fuel and energy. As you all know, a new situation has come about because of the oil crisis. In my view, this is a blessing in disguise. I told another audience, a scientist audience, that wherever we were in a position to get cheap articles from abroad, we have been lulled into sleep and later on we have come into trouble.

We had PL 480 foodgrains. Therefore, we did not attach sufficient importance to the development of agriculture because we were getting cheap food from abroad. Somebody produced it for us and we got it here. Till we took a decision that we would get out of this and launch a new programme of modernising agriculture on the basis of application of science and technology our agriculture continued to be subsistent agriculture, without the necessary

**PROF. MADHU DANDAVATE :** I would like to seek a clarification The total allocation for research and development has not been even .5% of the GNP. Would you insist that....

**SHRI C. SUBRAMANIAM :** Let me elaborate this a little bit, before I come to that point.

In the same way, in 1962-64, when I was in charge of Mines and Metals, we took up various projects in the development of production of coal and utilisation of coal by gasification, low temperature carbonisation etc. But, all that were put into cold storage because crude oil was available at 80 cents a barrel. Because crude oil was available at 80 cents a barrel, we did not attach importance to exploration of our own resources in this country. We thought this will be more costlier. Now, we have been taken unawares.

Take for example Cotton. Sudanese cotton or Egyptian cotton was available at Rs. 1500 per tonne. Since we were able to get high staple cotton from abroad at a cheap price, we did not attach importance to the development of production of cotton. But, it is now Rs. 16,000 per tonne. The development in the production of cotton is much of relevance now, than ever before. That is why, new varieties are coming up.

We thought that since there are other rich nations which have achieved higher levels of scientific research and development, we could just make the payment and take the knowhow. In my view, it is this attitude which has brought about—this is one of the contributing factors—industrial stagnation. As a nation, we did even have the competence to absorb the technology that we were importing. We were not able to adapt the technology for the raw materials available within the country. We always became dependent on imported components or imported raw materials. This is how, we have become more and more not self reliant, but, dependent on foreign sources. Therefore, if you think in terms of cutting foreign aid, you are not going to achieve this by just your resolution. It is only by development of science and technology that you would be able to do this.

Therefore, now, we have given importance to the development of coal technology, so that we could use coal, as much as possible, as a source of energy

and as a fuel. We have also to develop various other alternative sources of energy. For example, solar energy. It was just a toy which was being used for cooking and other purposes. The whole world is now realising that perhaps this is one of the sources of energy, which could be channelised in a very big way. We should take up this work also. Then, there is tidal energy, geothermal energy and various other developments in the field of energy and fuel.

After that, we have given importance to, what we call, in house research and development for each industrial unit for the purpose of increasing production, improving technology, adapting the technology and further developing that technology so that they are able to reach higher levels of technological efficiency. So, this is how we have planned taking into account the requirements. In this also, we are moving into collaboration with other countries. Till now, we were getting collaboration in the field of industrial development. We took knowhow and equipments from abroad and established industries here. Instead of that, we have moved into the area of collaboration in the field of science and technology and research and development. We have entered into very meaningful and extensive agreements with USSR and other socialist countries, France, West Germany, U.K. and various other countries which are in a position to help us and willing to help us. From a period of industrial collaboration, we are moving into a period of scientific and technological collaboration for development within our own country, because if we start doing everything anew, it will take perhaps another generation. Therefore, we should take advantage of the advances which have already taken place and build upon them. This is how the science and technology plan has been finalised with regard to each sector of industry. The whole area has been divided into 24 sectors, each sector having been further divided into sub-sectors. This is how it is placed before the House in two volumes. To back this up, we have got a huge amount of printed

literature—a cartload of it—and only members interested in each area would get it. I am glad some of the publications are selling like hot cake. A large number of copies of the *Chemical Industry—Draft Plan* have been sold away.

Mr. Dandavate asked, what are the financial magnitudes of this and what is our target with regard to the expenditure on R & D? As a matter of fact, at Government level a policy decision has been taken with regard to the global requirements also that every country should spend at least 1% of its GNP for R & D activities. It is from that point of view that we identified in the NCST projects worth Rs. 1725 crores. But unfortunately the resources are not adequate and therefore, this has been pruned to Rs. 1033 crores. Fortunately, our scientists have given priorities. They have worked out, if this is the resources, these should be taken. If the resources are short, these should be left out and these should be taken up. Like that priorities A, B, C etc. have been indicated. This is how we are going forward. I am little disappointed because as against Rs. 1033 crores, only Rs. 100 and odd crores have been given for 1974-75. But I am quite confident of persuading the Planning Commission, the Finance Ministry and various other ministries that we should expand our area of scientific and research activities because that alone would save us from stagnation and dependence on foreign countries and make us a self-reliant, prosperous and dynamic nation. Ultimately it is the human material which counts. Fortunately, in the area of science and technology, we have the highest talents available not only in the country but functioning outside also. Often it is asked, why can't we get back all our scientists from abroad? As a matter of fact, it is not as if they are getting 20,000 or 30,000 dollars abroad and that is why they do not want to get back. They are not coming because there are not job opportunities for them. It is not our intention to ask every scientist abroad to return. We have to identify the talent available and see

[Shri C. Subramaniam]

in what area he can function. Then we should see whether that area is relevant to our plan. In that relevant area, it will be our endeavour to get back all our young men who are abroad to help the country to go forward. The future is hopeful not mainly because of the political complexion with which we are faced. It is mainly because of the large reservoir of scientific and technological talent which we have, which give us a new hope that we would not only be able to survive but march forward.

SHRI K. S. CHAVDA : Will you allow diversification to Indian firms with minor balancing equipment and imported raw materials to the tune of 40% of the licensed capacity for conversion of obsolete items into new articles

SHRI C. SUBRAMANIAM : We are interested in the Indian sector. It is not as if we are fond of the foreign sector and Mr. Chavda alone is interested in the Indian sector. We are giving all assistance to the Indian sector. It is not 40% but 25%. I will consider whether this can be further improved.

MR. CHAIRMAN : There are some cut motions, all in the name of Dr. Sardish Roy. I will now put cut motions Nos. 29 to 45 to the vote of the House.

*All the cut motions were put and negatived.*

MR CHAIRMAN : I will now put the demands to the vote of the House. The question is :

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 57, 58 and 59

relating to the Ministry of Industrial Development."

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN : I will now put the demands relating to the Department of Science and Technology to the vote of the House. The question is :

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 99, 100 and 101 relating to the Department of Science and Technology."

*The motion was adopted.*

*{The motions for Demands for Grants which were adopted by the Lok Sabha, are reproduced below-Ed.}*

#### DEMAND No. 57—MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

"That a sum not exceeding Rs. 1,94,26,000 on Revenue Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975 in respect of 'Ministry of Industrial Development.'"

#### DEMAND No. 58—INDUSTRIES

"That a sum not exceeding Rs. 4,07,52,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 35,27,37,000 on Capital Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975 in respect of 'Industries.'"

**DEMAND No. 59—VILLAGE AND SMALL INDUSTRIES**

"That a sum not exceeding Rs. 23,52,84,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 44,08,88,000 on Capital Account be granted to President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Village and Small Industries'."

**DEMAND No 99—DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**

"That a sum not exceeding Rs 4 96,98,000 on Revenue Account and not exceeding Rs 1,10,40,000 on Capital Account be granted to the President, on account, for or towards defraying the charges during the year ending the 31st day of March, 1975 in respect of 'Department of Science and Technology'."

**DEMAND No 100—SURVEY OF INDIA**

"That a sum not exceeding Rs 10,44,60,000 on Revenue Account be granted to the President, on account, for or towards defraying the charges during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Survey of India.'"

**DEMAND No 101—GRANTS TO COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH**

"That a sum not exceeding Rs. 25,10,02,000 on Revenue Account be granted to the President, on account, for or towards defraying the charges during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Grants to Council of Scientific and Industrial Research.'"

17.53 HRS.

**MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**

**MR. CHAIRMAN :** The House will now take up discussion and voting on

Demand Nos. 60 to 62 relating to the Ministry of Information and Broadcasting, for which six hours have been allotted.

**DEMAND No. 60—MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**

**MR. CHAIRMAN :** Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 26,66,000 on Revenue Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of Ministry of Information and Broadcasting'."

**DEMAND No 61—INFORMATION AND PUBLICITY**

**MR. CHAIRMAN :** Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 9,98,84,000 on Revenue Account and not exceeding Rs 1,72,92,000 on Capital Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of Information and Publicity'."

**DEMAND No. 62—BROADCASTING**

**MR. CHAIRMAN :** Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs 16,99,69,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 14,68 33,000 on Capital Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of Broadcasting'."

Hon. Members present in the House who desire to move their cut motions may please do so.

**SHRI JYOTIRMOY BOSU :** (Diamond Harbour) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Information and Broadcasting be reduced by Rs. 100."